राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 255

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ॐ नमः शिवाय

सरोकार

कश्मीर में ट्रांसजेंडर्स के लिए मसीहा हैं डॉ. एजाज बंड

श्रीनगर : कट्टरपंथ के दिनों में कश्मीर में ट्रांसजेंडर्स (किन्नरों) का भी कत्लेआम हुआ। डॉ. एजाज अहमद बंड तब इनके लिए मसीहा बनकर सामने आए। बंड की कोशिशों से यह वर्ग अब राहत की सांस ले रहा है। (पेज-10)

जागरण विशेष

झरने के नीचे विराजमान शिव, होता सतत जलाभिषेक

नीमच : मान्यता है कि 'बाहुबली' भीम ने झरने के नीचे शिवलिंग स्थापित किया था। सूखा पड़ा हो या अकाल, शिवलिंग पर गिरती रहती है जलधारा। नीमच में घने पहाड़ी जंगलों के बीच मौजूद है प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

उपहार कांड : अंसल बंधुओं को राहत, नहीं बढ़ेगी सजा

नई दिल्ली : दिल्ली में 13 जून 1997 में उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड में लापरवाही के दोषी अंसल बंधुओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल की सजा बढ़ाने की मांग वाली अग्निकांड पीड़ितों की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

जम्मू कश्मीर में फिरने वाले हैं क्षेत्रीय सिनेमा के दिन

श्रीनगर : केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय सिनेमा के दिन फिरने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य प्रशासन को क्षेत्रीय सिनेमा की स्थापना करने और संस्कृति नीति बनाने के लिए यथोचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

विदेशी टेलीकॉम वेंडर्स के लिए भारत आना होगा मुश्किल

नई दिल्ली : टेलीकॉम उपकरण कारोबार में सरकार ने जैसे को तैसा की नीति पर कदम बढ़ाया है। सरकार ने कहा है कि उन देशों की कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो भारतीय कंपनियों को अपने बाजार में जगह नहीं देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

चीन में कोरोना पीड़ितों की संख्या 75 हजार के करीब

बीजिंग : चीन में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 75 हजार के करीब पहुंच गई है। अब तक 2,100 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में हालांकि नए मामलों की दर में कमी आ रही है, लेकिन दुनिया में अनुमान से ज्यादा तेजी से वायरस फैल रहा है।

ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान पांच समझौतों की तैयारी

मजबूत होगी दोस्ती ▶ रक्षा, परमाणु ऊर्जा और कारोबारी क्षेत्र में गतिरोधों को सुलझाने का तय होगा खाका

सीमा पार आतंकवाद और आतंकी संगठनों को कड़ा संदेश देने की होगी कोशिश

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता भले ही न हो, लेकिन दोनों देशों के बीच पांच क्षेत्रों से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तैयारी है। इसमें से दो समझौते निवेश को बढ़ावा और उन्हें सुरक्षा देने से संबंधित होंगे। एक समझौता आतंरिक सुरक्षा पर होगा। इसके अलावा एक समझौता हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर होगा। दोनों देशों की कंपनियों के सहयोग से परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के संबंध में भी एक समझौता होने के आसार हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है, 'राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को एक निश्चित परिपक्वता देने की कोशिश होगी। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है और अब इसे खास दिशा देने की कोशिश होगी।' विदेश मंत्रालय के एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ट्रंप की भारत यात्रा को सिर्फ बड़े समझौतों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। जिस तरह से वर्ष 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली यात्रा ने भारत-अमेरिका रिश्तों को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया वैसा ही इस यात्रा के बाद होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और कारोबारी क्षेत्र में मौजूदा कई गतिरोधों को आगे किस तरह से सुलझाया जाए, इसका एक खाका मिल जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, 25 फरवरी, 2020 को मोदी और ट्रंप के सामने पांच समझौते करने की सहमति बन चुकी है और दो समझौतों पर बातचीत जारी है। लेकिन भारत-अमेरिका के भावी रिश्तों की असली झलक दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में दिखेगी। संयुक्त बयान रिश्तों की व्यापकता को समेटे हुए होगा। इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में भावी सहयोग का रोडमैप होगा, साथ ही स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे क्षेत्र में किस तरह से दोनों लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के काम आएंगे, इसका भी खाका होगा। संयुक्त घोषणा पत्र की एक खासियत आतंकवाद के खिलाफ दिया गया बयान भी होगा। जून, 2017 में मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद वाशिंगटन में जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। अब जबकि भारत नए सिरे से आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश में है तब भारत चाहेगा कि सीमा पार आतंकवाद और पड़ोसी देश में पनाह पाए आतंकवादी संगठनों को कड़ा संदेश देने में कोई कोताही न हो। उल्लेखनीय है कि पूर्व में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन या बराक ओबामा भारत के अलावा पाकिस्तान भी गये थे, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।

मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा सेक्टर को लेकर भी अहम बातचीत होनी है। पिछले दो वर्षों में अमेरिका भारत का एक बड़ा ऊर्जा साझीदार भी बनकर उभरा है। प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक भारत अभी अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। सितंबर, 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने अमेरिकी एलएनजी कंपनी टेलुरिएन के साथ 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया था। इस बार दोनों नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि किस तरह भारत-अमेरिका के बीच तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कारोबार को बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत को कतर से भी कम कम दर पर एलएनजी देने का प्रस्ताव किया है।

अमेरिका के सहयोग से भारत में लगाए जाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भी समीक्षा की जाएगी। सनद रहे कि वर्ष 2008 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते के मुताबिक अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस और भारतीय कंपनी एनपीसीआइ भारत में परमाणु संयंत्र लगाने वाले थे, लेकिन 12 वर्षों बाद अभी तक खास प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले दोनों कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात हुई है। बहुत संभव है कि इस बारे में एक समझौता भी ट्रंप की यात्रा के दौरान हो। (संबंधित खबरें-पेज-5 पर)

बैठक का एजेंडा

- निवेश संवर्द्धन, आइपीआर, आतंरिक सुरक्षा पर होगा समझौता
- रक्षा क्षेत्र में भावी सहयोग समझौतों का बनेगा ढांचा
- ज्यादा क्रूड-एलएनजी खरीदने का रास्ता निकलेगा
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर खत्म की जाएगी उहापोह की स्थिति

रवीश कुमार फाइल फोटो

भारत का अपमान नहीं है ट्रंप का बयान : विदेश मंत्रालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस की नाराजगी को विदेश मंत्रालय ने तवज्जो नहीं दी है। ट्रंप ने कहा था, 'भारत ने अमेरिका संग ठीक नहीं किया है।' विदेश मंत्रालय के अफसरों ने कहा, यह बयान उन्होंने अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले उच्च आयात शुल्क के संदर्भ में दिया है। ट्रंप पहले भी यह मुद्दा उठाते रहे हैं और दोनों देशों के बीच इस बारे में बात भी होती रही है। ट्रंप और मोदी के बीच भी इस बारे में बात होगी।

बेटियों को हक देने के लिए सेना तैयार : जनरल नरवाने

नई दिल्ली, एजेंसियां : सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने ने गुरुवार को कहा कि सेना लैंगिक समानता लाने के लिए प्रयासरत है और महिला अफसरों को स्थायी कमीशन प्रदान करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस दिशा में स्पष्टता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, सेना ने हर स्तर पर महिलाओं की भर्ती की पहल की है। सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल कोर में 100 महिला सैन्यकर्मियों के पहले बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला अफसरों से पूछा जा रहा है कि क्या वे स्थायी कमीशन को तरजीह देना चाहेंगी?

जनरल नरवाने ने पत्रकारों से कहा, सेना किसी जवान से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। सेना का नजरिया हमेशा से ऐसा ही रहा है और इसलिए हमने 1993 में ही महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू कर दी थी। सेना प्रमुख ने कोर्ट के फैसले को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा, यह संस्था की बेहतर क्षमता के लिए अधिकारियों की भर्ती की दिशा में स्पष्टता प्रदान करता है। ज्ञात हो, सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में कमी : जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में नरवाने ने कहा, वहां आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सेना आतंकी समूहों पर दबाव बनाए हुए है। सेना प्रतिकूल हालात में भी पाकिस्तानी फौज के नापाक मंसूबों को पूरा विफल कर रही है। उन्होंने कहा, गुलाम कश्मीर में 15-20 आतंकी कैंप हैं, जहां 250-350 आतंकी ठहरे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रूप से थियेटर कमान के प्रस्तावित गठन पर कहा, कुछ भी तय करने से पहले विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।

चीन हर समय पाक की मदद नहीं कर सकता : सेना प्रमुख ने कहा है चीन को लगने लगा है कि वह अपने सदाबहार मित्र पाकिस्तान की हर समय मदद नहीं कर सकता। उन्होंने जोर दिया कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) यदि पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कामयाब रहता है, तो उसे अपनी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने को मजबूर होना पड़ सकता है। ज्ञात हो, चीन एफएटीएफ की अब तक हुई हर मीटिंग में पाक को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की मांग करता रहा है, लेकिन, पेरिस में हुई बैठक में उसने ऐसा नहीं किया।

मनोज मुकुंद नरवाने की फाइल फोटो। प्रेट्र

मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सेना में महिला अधिकारियों समेत सभी को राष्ट्र के प्रति योगदान के साथ ही करियर में तरक्की के समान अवसर दिए जाएंगे। -जनरल एमएम नरवाने

जून तक नहीं सुधरा तो ब्लैक लिस्ट होगा पाक

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का जो दिखावा पाकिस्तान ने गत कुछ दिनों में किया है, उससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि फाइनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाक को सिर्फ चार माह की और मोहलत दी है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान ने अगर जून, 2020 तक आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बताए गए काम नहीं किए तो उसे ब्लैक लिस्ट यानी प्रतिबंधित सूची में डाला जा सकता है। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची में शामिल है और उसे वर्ष 2018 में ही एफएटीएफ ने 27 कार्यों की एक सूची सौंपी थी। आतंकी फंडिंग समेत काले धन का प्रवाह रोकने के लिए पूरे विश्व में एक समान नियम कानून बनाने के लिए गठित एफएटीएफ की पिछले रविवार से पेरिस में बैठक चल रही है और इसका फैसला शुक्रवार को सामने आएगा।

एफएटीएफ की बैठक में हिस्सा ले रहे कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को तुर्की के अलावा अन्य किसी भी देश से साफ तौर पर समर्थन नहीं मिला। यहां तक कि उसके सदाबहार दोस्त चीन ने भी इस बार उसका साथ छोड़ दिया है। मोटे तौर पर सदस्य देशों में यह आम राय थी कि आतंकी गतिविधियों तक फंड प्रवाह रोकने का खतरा पाकिस्तान में पूरी तरह से बना हुआ है।

पाकिस्तान सरकार के समक्ष जो 27 काम टास्क फोर्स की तरफ से दिए गए थे उसमें से आधे पर भी ठीक तरह से काम नहीं हुआ है। ऐसे में उसे कहा गया है कि वह जून, 2020 तक बाकी सभी काम पूरा करे। अगर तय समय सीमा में ऐसा नहीं होता है तो एफएटीएफ उचित कार्रवाई करेगा। इसके तहत सभी सदस्य देशों का कहा जाएगा कि वह पाक के साथ कारोबारी व वित्तीय रिश्तों पर खास ध्यान दे। दूसरे शब्दों में कहें तो एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तब तक वह ग्रे लिस्ट में रहेगा।

सूत्रों के मुताबिक पेरिस बैठक से यह भी बात भी सामने आ गई कि एफएटीएफ के बताए निर्देशों के मुताबिक कदम उठाने का जो स्वांग पाकिस्तान सरकार भर रही थी वे सब खोखले थे। अब पाकिस्तान के पास एफएटीएफ की कार्ययोजना को ठोस व तत्काल तरीके से लागू करने के अलावा और कोई चारा नहीं है।

पाकिस्तान को उठाने होंगे ठोस कदम पेज>>13

कसा फंदा

- पाकिस्तान को मिली प्रतिबंधित सूची में डालने की एफएटीएफ की चेतावनी
- आतंकी फंडिंग रोकने का लक्ष्य चार महीनों में करना है पूरा

राजस्थान में अनुसूचित जाति के युवकों से बर्बरता, राहुल और सोनिया गांधी ने मांगी रिपोर्ट

जयपुर : राजस्थान के नागौर जिले के करणू गांव में अनुसूचित जाति के दो युवकों के खिलाफ अत्याचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। युवकों की बर्बरता से पिटाई और अमानवीय कृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआइजी स्तर के अधिकारी को जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पीड़ित युवकों के खिलाफ 50 हजार रुपये चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। (पेज-7)

मोदी को मिला भूमि पूजन के लिए निमंत्रण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व महासचिव चंपत राय समेत चार सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें मंदिर मामले पर फैसले की बधाई भी दी और भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या आने का न्योता भी दिया। वहीं मोदी ने भी चारों सदस्यों का सम्मान किया और आशा जताई कि जनभावना के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा।

दरअसल, पीएम की ओर से नृत्य गोपाल दास, सुप्रीम कोर्ट में रामलला के वकील तथा ट्रस्ट के सदस्य परासरन, चंपत राय और संत गोविंद गिरी को बुलाया गया था। करीब 15 मिनट की बैठक में पीएम ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तो महंत नृत्य गोपाल दास ने मोदी को प्रसादी चुनरी भेंट की और उन्हें अयोध्या आने का न्योता दिया है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट की अगली बैठक अयोध्या में 3-4 मार्च को हो सकती है।

ट्रस्ट में दिखेगी पीएम की सोच पेज>>6

राम मंदिर

- पीएम को अयोध्या आने का महंत नृत्यगोपाल ने दिया न्योता
- प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट के चार सदस्यों को बुलाया था

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास व अन्य सदस्यों ने पीएम से गुरुवार को उनके आवास पर भेंट की। एएनआइ

शाहीन बाग पर दूसरे दिन भी नहीं बनी बात, आज फिर होगा प्रयास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में 15 दिसंबर से धरने पर बैठे लोगों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त दो वार्ताकार दूसरे दिन भी शाहीन बाग पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वार्ता के दौरान हूटिंग होने पर नाराजगी जताते हुए कहा, आपका यही व्यवहार रहा तो शुक्रवार से यहां नहीं आएंगे। इसके बाद लोग शांत हुए और अपनी बात रखी। वार्ताकारों ने दो प्रदर्शनकारियों के साथ अवैध रूप से बंद किए गए पूरे रास्ते का अवलोकन किया और जामिया नगर के रास्ते वापस चले गए। ज्ञात हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल बुधवार को भी धरनास्थल पर पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन गुरुवार को दोबारा प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए शाहीन बाग पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद भी वे लोगों को मनाने में विफल रहे। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकारों की मौजूदगी में साफ किया कि वह रास्ता खाली नहीं करेंगे।

वरिष्ठ वकील साधना रामचंद्रन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। कहा कि आपने बुलाया और हम चले आए। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि शाहीन बाग में सड़क रोककर अनिश्चितकाल तक धरना नहीं चल सकता, लेकिन कोर्ट आपके प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी तत्पर है। संजय हेगड़े ने कहा कि जब शाहीन बाग भारत भर में प्रदर्शन का पर्याय बन चुका है तो हम क्यों न इसे मिसाल के तौर पर पेश करें जहां बिना किसी की परेशानी के लोग प्रदर्शन करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि धरनास्थल के बदल जाने से उनकी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी।

साधना रामचंद्रन ने कहा, सभी से कुछ अच्छे और कुछ गलत निर्णय हो जाते हैं पेज>>5

मुखर हुई मांग

गांधी परिवार से बाहर के नेता को कमान देने की संदीप दीक्षित की राय का किया समर्थन, कांग्रेस ने थरूर और दीक्षित को अपना काम दिखाने और ज्ञान बांटने से परहेज की दी नसीहत

अब थरूर ने कहा, चुनाव से तय हो कांग्रेस का नेतृत्व

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस में नए नेतृत्व को लेकर जारी 'दुविधा' पर अब पार्टी नेताओं के स्वर मुखर होने लगे हैं। पार्टी नेता संदीप दीक्षित के गांधी परिवार से बाहर का नेतृत्व तलाशने में हो रही देरी पर सवाल उठाने के बाद वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तो एक कदम आगे जाकर चुनाव के जरिये नए नेतृत्व का चयन करने की मांग उठाई है। हालांकि, कांग्रेस ने नेतृत्व के ऊहापोह पर अपने नेताओं की इस मुखर बेचैनी को तवज्जो न देते हुए अपना काम करने और ज्ञान देने से परहेज करने की नसीहत दी।

राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से जारी कांग्रेस का नेतृत्व संकट सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद भी जल्दी सुलझता नहीं दिख रहा है। शशि थरूर ने इसके मद्देनजर ही कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के बयान का समर्थन किया। दीक्षित ने एक साक्षात्कार में कांग्रेस के मौजूदा ऊहापोह के लिए नेतृत्व के इर्द-गिर्द काबिज नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने परोक्ष रूप से गांधी परिवार से बाहर के नेता को पार्टी की कमान सौंपे जाने की वकालत की है। थरूर ने ट्वीट कर दीक्षित के नजरिये का समर्थन करते हुए कांग्रेस कार्यसमिति से नेतृत्व का चुनाव कराने का आग्रह किया।

कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी पर बनी दुविधा और सोनिया गांधी के लंबे समय तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहने की अनिच्छा के बीच नए नेतृत्व को लेकर ऊहापोह बढ़ गया है। इस असमंजस की वजह से पार्टी की जमीनी सियासी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेताओं को अपनी राजनीति भी संकट में घिरती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि संदीप दीक्षित और शशि थरूर से पहले जयराम रमेश और वीरप्पा मोइली जैसे नेताओं ने भी पार्टी में व्यापक सर्जरी की आवाज उठाई थी। वैसे संदीप दीक्षित की बेबाकी भी साहसिक मानी जा रही है, क्योंकि शीला दीक्षित के गांधी परिवार से बेहद करीबी रिश्ते थे।

कांग्रेस के पास योग्य नेताओं की कमी नहीं पेज>>5

राहुल गांधी ने इस्तीफा देने के बाद जब नेतृत्व संभालने की अनिच्छा जता दी, तब भी पार्टी की रीति-नीति का संचालन कर रहे नेता दोबारा उनकी वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। सोनिया गांधी भी अंतरिम अध्यक्ष अधिक समय तक नहीं रहना चाहतीं। ऐसे में पार्टी के संचालकों को किसी वरिष्ठ चेहरे को पार्टी की कमान सौंपने का रास्ता बनाना चाहिए।

-संदीप दीक्षित, पूर्व कांग्रेस सांसद

संदीप दीक्षित ने खुले तौर पर जो कहा है, वही बात पूरे देश के दर्जनों कांग्रेस नेता निजी बातचीत में कह रहे हैं। इनमें कई ऐसे नेता भी शामिल हैं, जो पार्टी में अहम पदों पर बैठे हैं। इसीलिए मैं कांग्रेस कार्यसमिति से अपनी इस अपील को दोहराता हूं कि नेतृत्व के लिए चुनाव कराए जाएं, ताकि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में जोश भरा जा सके।

-शशि थरूर, कांग्रेस सांसद

230 एयर इंडेक्स दर्ज किया गया राजधानी में गुरुवार को। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 180, गाजियाबाद का 270, ग्रेटर नोएडा का 246, गुरुग्राम का 180 और नोएडा का 253 दर्ज किया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 फरवरी 2020

तैयारी ▶ पर्यावरण मंत्रालय संभालने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों की ली बैठक

प्रदूषण से निपटने को गठित होगी संयुक्त टीम

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'रियल टाइम डाटा' किया जाएगा एकत्रित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सभी संबंधित निकायों की एक संयुक्त टीम (ज्वाइंट एक्शन टीम) बनाने पर विचार कर रही है। इस टीम में तीनों नगर निगमों, लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समेत तमाम उन सभी विभागों को शामिल किया जाएगा, जो अपने स्तर पर प्रदूषण से निपटने का काम करते हैं। इससे प्रदूषण कम करने की दिशा में बेहतर तालमेल के साथ काम हो सकेगा। इस आशय की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को दी।

दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने विभाग के साथ बैठक की। उसके बाद बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों से 10 सूत्रीय गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए एक्शन प्लान मांगा है। पर्यावरण के एक्शन प्लान में हम संयुक्त विभागीय टीम के गठन का प्रस्ताव रखेंगे ताकि दिल्ली में समान स्तर पर प्रदूषण से लड़ा जा सके।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। (फाइल)

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'रियल टाइम डाटा' एकत्र करेगी। रियल टाइम डाटा की मदद से प्रदूषण के कारक पता चलेंगे और उनसे होने वाले प्रदूषण के स्तर को मापना आसान होगा। इसके आधार पर सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें तय किया जाएगा कि दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने वाशिंगटन डीसी के एक विश्वविद्यालय के साथ करार भी किया हुआ है। इसकी रिपोर्ट मार्च में आने की उम्मीद है। शुक्रवार को गोपाल राय दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्थित वाशिंगटन डीसी विश्वविद्यालय के डाटा सेंटर का दौरा भी करेंगे।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में यमुना का प्रदूषण स्तर कम करने के लिए भी दिल्ली सरकार जल्द ही काम शुरू करने वाली है। जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का दौरा शनिवार से शुरू होगा। वह स्वयं दिल्ली गेट स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यमुना में गिरने वाले नालों को लेकर भी जल्द ही एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

पड़ोसी राज्यों को लिखा जाएगा पत्र : दिल्ली सरकार 28 फरवरी को दिल्ली के सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाने जा रही है। इसमें दिल्ली में काम करने वाले तमाम निकायों और विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक के बाद दिल्ली सरकार की ओर से पड़ोसी राज्यों (हरियाणा, पंजाब और राजस्थान) की सरकारों को प्रदूषण से लड़ने के लिए मिलकर काम करने को लेकर पत्र लिखा जाएगा।

हर साल कम हुआ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर : पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा है कि दिल्ली में बीते कुछ वर्षों में प्रदूषण का स्तर 25 फीसद तक कम हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पीएम 10 और पीएम 2.5 का पूरे साल का औसत स्तर लगातार कम हुआ है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर मापने के 28 एयर मॉनिटरिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनमें से 24 केंद्र 2018-2019 में बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को हर हाल में कम किया जाएगा।

पर्यावरण सम्मेलन 27 को

राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में आगामी 27 फरवरी को सरकार की ओर से एक पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न गैर-सरकारी संगठन, पर्यावरण मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी, नगर निगम के इंजीनियर और विभिन्न स्कूलों के छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव मांगेगी। इन सुझावों के माध्यम से दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर कार्य किया जाएगा।

तीन तरीकों से निपटेंगे प्रदूषण से

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार तीन तरीके से प्रदूषण से लड़ने की योजना पर काम कर रही है। इनमें पहला होगा जन जागरूकता अभियान। इसके तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दूसरा तरीका होगा तकनीक आधारित अभियान। इसके तहत दिल्ली सरकार प्रदूषण का रियल टाइम डाटा एकत्र करेगी। तीसरा तरीके के तहत दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने पर काम करेगी।

पर्यावरण केवल लैंडफिल साइट तक सीमित नहीं

भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा भी पर्यावरण का मुद्दा उठाए जाने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण और पर्यावरण का मुद्दा केवल लैंडफिल साइट तक सीमित न होकर बहुत व्यापक है। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो मौजूदा स्थिति में अवश्य ही सुधार होगा।

अब ड्रोन से होगी बिजली लाइनों की निगरानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर की निगरानी अब ड्रोन से की जाएगी। बांबे सबअर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (बीएसईएस) ने इसकी शुरुआत की है। पहले चरण में पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज व विवेक विहार और पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार व बुडेला इलाके में ड्रोन तैनात किए गए हैं। इससे बिजली लाइन में खराबी का समय रहते पता लगाकर उसे दुरुस्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी।

ड्रोन में अत्याधुनिक इन्फ्रारेड थर्मो स्कैनिंग तकनीक व उच्च क्षमता वाले कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से बीएसईएस के बिजली वितरण क्षेत्र में स्थित ग्रिड स्टेशनों, जगह-जगह लगे ट्रांसफॉर्मर व अन्य उपकरणों पर नजर रखी जाएगी। किसी उपकरण में कोई बदलाव होने पर ड्रोन में लगे कैमरों से फोटो खींचकर बीएसईएस के कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी। फोटो के साथ ही उस स्थान की भी जानकारी होगी जहां पर बिजली उपकरण में खराबी आने की संभावना है जिससे कि बिजली कर्मियों को वहां पहुंचने में मदद मिलेगी।

बिजली लाइनों और उपकरणों पर ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। सौजन्य : बीएसईएस

बीएसईएस अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बिजली चोरी भी आसानी से पकड़ी जाएगी। बिजली लाइन से गलत तरह से कनेक्शन लेकर बिजली चोरी करने वालों की सही जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ सुबूत के साथ कार्रवाई संभव हो सकेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ड्रोन से उन इमारतों की जानकारी मिल सकेगी जिनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सौर ऊर्जा का महत्व बताकर उसे राजी किया जा सकता है।

न्यूज गैलरी

हाई कोर्ट में वकीलों ने नहीं किया काम

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के तीसरे सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में किए जाने से हैरान अधिवक्ता गुरुवार को कार्य से विरत रहे। इसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट में विभिन्न मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सूचीबद्ध किए गए विभिन्न मामलों में प्रॉक्सी अधिवक्ताओं को सुनवाई की अगली तारीख दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के स्थानांतरण की अनुशंसा की जानकारी अधिवक्ताओं को बुधवार सुबह ही मिली थी। जानकारी मिलने के बाद बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी समिति की बैठक की और इसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह न्यायमूर्ति मुरलीधर के स्थानांतरण करने के फैसले पर दोबारा विचार करे। एसोसिएशन अध्यक्ष मोहित माथुर की तरफ से जारी किए गए प्रस्ताव में न्यायमूर्ति के स्थानांतरण की निंदा की थी और कहा था कि यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एक बड़ी क्षति है। (जासं)

दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर की किताब का विमोचन

नई दिल्ली : इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा की पुस्तक बीटिंग बुलेट का विमोचन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विजय कपूर के अलावा ओपी भुटानी, पंकज वोहरा, आइआर शर्मा मौजूद रहे। अजय राज शर्मा 1966 बैच के आइपीएस अफसर हैं और वर्ष 2004 में सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अजय राज 2001 में ससंद पर हुए आतंकी हमले के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि उस समय के हालात को वह कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि युवाओं को ओहदे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से पुलिस सेवा में आना चाहिए ताकि वे देश व अपने काम के प्रति न्याय कर सकें। (जासं)

सौरभ भारद्वाज को मिला आदर्श युवा विधायक सम्मान

नई दिल्ली : ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज को भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन की ओर से आदर्श युवा विधायक-2019 चयनित किया गया है। शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड का चयन छात्र संसद के 10वें वार्षिकोत्सव में गवर्निंग काउंसिल ने किया है। कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद से जंग- विद्रोह या नक्सलवाद विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। (जासं)

खराब हवा 'खा' रही भ्रूण का वजन, लंबाई को प्रदूषण का लकवा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

चिंताजनक

आइआइटी दिल्ली और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संयुक्त अध्ययन में सामने आई जानकारी

मां की कोख में पल रहा बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो, इसके लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन हमारे आसपास की जहरीली हवा इन गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही है। देशभर में वायु प्रदूषण के कारण अजन्मे बच्चों की लंबाई तो घट ही रही है, वजन भी कम हो रहा है। विशेषकर पीएम 2.5 के महीन प्रदूषक कण भ्रूण के विकास में बाधक बन रहे हैं। आइआइटी दिल्ली और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक नए अध्ययन 'अर्ली लाइफ एक्सपोजर टू आउटडोर एयर पल्यूशन : इफेक्ट ऑन चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया' में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. इसके मुताबिक एयर इंडेक्स के प्रमुख प्रदूषण तत्व पीएम 2.5 के अत्यंत बारीक कण अन्य बीमारियों के कारक बनने के साथ-साथ भ्रूण के विकास में भी बाधा बन रहे हैं। आलम यह है कि गर्भ के पहले तीन महीनों के दौरान भ्रूण की लंबाई 7.9, जबकि वजन 6.7 फीसद तक कम हो रहा है।

अध्ययन के मुताबिक पीएम 2.5 के कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भवती महिला के शरीर में यह कण उसकी कोख में पल रहे बच्चे के विकास को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर भ्रूण का विकास ठीक से नहीं हो पाता है तो इसके नतीजे और भी खतरनाक होते हैं। ये बच्चे नाटे और अल्पविकसित होते हैं और जीवन भर अनेक तरह की समस्याओं से जूझते हैं। इस अध्ययन के अनुसार भारत में आउटडोर प्रदूषण बहुत से स्थानों पर सुरक्षित मानकों से कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। इसके तहत शहरी, ग्रामीण और जेजे कलस्टर में घरेलू और कामकाजी दोनों महिलाओं और शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के आंकड़े जुटाए गए। इस दौरान 601,509 घरेलू महिलाओं और 2,20000 बच्चों पर शोध किया गया। वर्ष 2019 के अंत में तैयार किए गए इस अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति पर अलग से आंकड़े जुटाकर अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन आइआइटी दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर कुणाल बाली, डॉ. साग्निक डे और सौरांगशु चौधरी के सहयोग से भारतीय सांख्यकीय संस्थान (इकोनॉमिक एंड प्लानिंग यूनिट) की प्राची सिंह ने किया है।

06 लाख 1509 घरेलू महिलाओं पर किया गया अध्ययन

7.9 फीसद कम हो रही भ्रूण की लंबाई, 6.7 फीसद तक घट रहा वजन

वाहनों ने निकलता धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। (फाइल)

हवा से उड़ा प्रदूषण बारिश से बढ़ेगी ठंडक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में गुरुवार को दिन भर 25 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवा से दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण पूरी तरह नियंत्रण में आ गया है। वहीं रात से शुक्रवार दोपहर तक होने वाली हल्कीबारिश से ठंडक का भी एहसास होगा। ठंडक का यह दौर अगले दो तीन दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मौसम में फिर से गर्माहट का एहसास होने लगेगा। बादलों और सूरज के बीच भी आंखमिचौली का दौर जारी रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री अधिक 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 50 से 86 फीसद रहा। शुक्रवार को भी बादल छाए रहेंगे। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 एवं 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा और पंजाब में बारिश का दौर चल रहा है। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार देर रात से शुक्रवार दोपहर तक हल्की बारिश होगी। चूंकि यह बारिश तेज हवा के साथ होगी, लिहाजा इससे तापमान में भी थोड़ी गिरावट आएगी और ठंडक का एहसास भी बढ़ेगा। स्काइमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावत के अनुसार ठंडक का यह दौर रविवार तक चलेगा।

एम्स की मुख्य ओपीडी में 20.68 फीसद कम हुई मरीजों की संख्या

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

देश भर में बन रहे नए एम्स का असर कहें या कुछ और लेकिन एक सच यह है कि दिल्ली एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 12.41 फीसद कम हुई है। खासतौर पर मुख्य अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। एम्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ओपीडी में मरीजों की संख्या 20.68 फीसद तक कम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य ओपीडी में वर्ष 2018-19 में पिछले सात सालों में मरीजों की संख्या सबसे कम रही। हालांकि, मुख्य अस्पताल सहित एम्स के सभी सेंटरों में मरीजों के दाखिले, सर्जरी व प्रोसिजर बढ़े हैं।

एम्स में मुख्य अस्पताल के अलावा आठ सेंटर व हरियाणा के झज्जर में आउटरीच ओपीडी व राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) है। 2483 बेड की क्षमता वाले एम्स के मुख्य अस्पताल की बेड क्षमता 1162 है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अस्पताल की ओपीडी को छोड़कर संस्थान के अन्य प्रमुख सेंटरों में मरीजों की संख्या में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। जिसमें आरपी सेंटर, कार्डियक सेंटर, न्यूरो सेंटर, कैंसर सेंटर, ट्रॉमा सेंटर मुख्य रूप से शामिल हैं। वर्ष 2018-19 में एम्स की ओपीडी में कुल 38 लाख 14 हजार 726 मरीजों का इलाज हुआ। जबकि वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 43 लाख 55 हजार 338 थी। इस तरह वर्ष 2018-19 में मरीजों की संख्या 5,40,612 लाख कम हो गई। इसका कारण मुख्य अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या घटने के अलावा सीसीएम (सेंटर फॉर कम्यूनिट मेडिसिन) की सक्रियता कम होना है। वहीं वर्ष 2017-18 में एम्स के मुख्य अस्पताल की ओपीडी में 20 लाख 88 हजार 171 मरीजों का इलाज हुआ था। इसके अगले साल यह संख्या 4 लाख 31 हजार 842 कम हो गई। इस तरह मुख्य अस्पताल की ओपीडी में कुल 16 लाख 56 हजार 329 मरीजों का इलाज हुआ।

फाइल फोटो

इस मामले पर एम्स की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि इसका एक कारण यह बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स में मरीजों का दबाव कम करने के लिए छह शहरों में बने नए एम्स संचालित हो चुके हैं। इसके अलावा एम्स में अप्वाइंटमेंट सिस्टम लागू होने के बाद सभी विभागों में मरीजों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसके मुताबिक ही प्रतिदिन मरीज देखे जाते हैं। इस बारे में एम्स की प्रवक्ता डॉ. आरती विज से बात करने की कोशिश की गई। उनके मोबाइल पर मैसेज भी भेजा गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।

दो लाख से ज्यादा हुई सर्जरी : रिपोर्ट के अनुसार दो लाख 54 हजार 605 मरीज भर्ती किए गए। वहीं दो लाख एक हजार 793 मरीजों की सर्जरी व विभिन्न प्रोसिजर हुए। इसके अलावा मुख्य अस्पताल में संक्रमण दर छह फीसद से घटकर 5.8 फीसद रही। वहीं मृत्युदर (1.7) में भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन कार्डियक व न्यूरो सेंटर में मृत्युदर 2.8 से बढ़कर 2.9 फीसद दर्ज की गई।

हिंडन से लखनऊ, प्रयागराज के लिए उड़ान जल्द

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से लखनऊ व प्रयागराज के लिए उड़ान जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ पांच मार्च को बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि बैठक में लखनऊ व प्रयागराज के लिए उड़ान का रास्ता शीघ्र साफ हो जाएगा।

प्रयागराज व लखनऊ के लिए शीघ्र उड़ान व हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल पर सुविधाओं को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी ने सिविल टर्मिनल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गाजियाबाद से हुबली जाने वाली उड़ान सेवाओं की समीक्षा की। टर्मिनल के डायरेक्टर ने बताया कि गाजियाबाद से हुबली जाने को नागरिकों के लिए पूर्व में हिंडन टर्मिनल से सप्ताह में तीन दिन उड़ान सेवाएं थी, जो बढ़ाकर पांच दिन कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने हिंडन टर्मिनल की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के रन-वे के किनारे चेन लिंक फेंसिंग के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने 4.33 करोड़ रुपये स्वीकृत कर प्रशासन को भेजा है। इसे अधिशासी अभियंता केंद्रीय लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद को उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी ने डायरेक्टर हिंडन सिविल टर्मिनल को निर्देश दिए हैं कि वह अधिशासी अभियंता केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से वार्ता कर तत्काल एयरफोर्स स्टेशन के रन-वे के किनारे चेन लिंक फेंसिंग का कार्य प्रारंभ कराएं। जिलाधिकारी ने टर्मिनल पर दूरसंचार, पेयजल, परिवहन सेवा के साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों के अफसरों से कहा है।

पिथौरागढ़ की उड़ान 26 तक रद : हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ जाने वाली फ्लाइट की उड़ान छह दिन के लिए रद कर दी गई है। 21 से 26 फरवरी तक फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से यात्रियों को दी है। हिंडन एयरपोर्ट की डायरेक्टर शोभा भारद्वाज ने बताया कि हेरिटेज कंपनी ने उड़ान रद होने का कारण ऑपरेशनल बताया है। उन्होंने बताया कि एयरलाइंस कंपनी की ओर से सभी यात्रियों को मैसेज भेज दिया गया है।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने सिविल टर्मिनल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। (फाइल)

जेएनयू व स्टैनफोर्ड कैंसर पर साथ करेंगे काम

जासं, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंसर पर साथ में काम करेंगे। दोनों ही विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर व शोधकर्ता काफी समय से कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज पर काम कर रहे हैं। अब दोनों विश्वविद्यालय एक साथ कैंसर प्रतिरोधक दवाइयों के निर्माण, कैंसर के विभिन्न कारकों को समझकर उनके इलाज के नए तरीकों पर काम करेंगे।

भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों के विज्ञान को मजबूत करने के लिए वर्ष 2000 में इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई थी। इसके नेतृत्व में अब जेएनयू और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव कैंसर बायोलॉजी एंड थैरापीयूटिक्स की स्थापना की जाएगी। गुरुवार को जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज द्वारा कैंसर की रोकथाम व इलाज विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में यह जानकारी दी गई। जेएनयू के पास बायोमेडिकल व लाइफ साइंसेज में विशेषज्ञता है।

सार्थक कदम

परीक्षार्थियों को सकारात्मक माहौल देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा बोर्ड, प्रतिदिन बोर्ड दो से तीन मीम्स ट्विटर के जरिये शेयर कर रहा

मीम्स के सहारे परीक्षा का डर दूर कर रहा सीबीएसई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो गई हैं। पहली बार बोर्ड छात्रों में परीक्षा के डर को दूर करने और उन्हें सकारात्मक माहौल देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। बोर्ड ट्विटर के जरिए हर दिन दो से तीन मीम्स साझा कर छात्रों में खुशनुमा माहौल देने की कोशिश कर रहा है। इन मीम्स में सीबीएसई की तरफ से छात्रों को कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं।

मसलन, पहले छात्र शेष रह गए पाठ्यक्रम को पूरा करें, 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते हैं, मेहनत सफलता दिलाती है, परीक्षा समाप्त होने के बाद परेशान न हों, रिजल्ट की चिंता न करें, इन तमाम विषयों पर सीबीएसई ने मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। बोर्ड की इस पहल से परीक्षार्थी के साथ- साथ अभिभावक भी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर मीम्स की यह खुशी देखकर अभिभावक भी राहत में है कि कम से कम कुछ समय के लिए तो बच्चे परीक्षा के डर को मन से निकाल पाएंगे।

> पढ़ाई के दौरान जब ब्रेक लेना होता है तो ट्विटर पर जाकर सीबीएसई के मीम्स देख लेता हूं। मीम्स को देखकर परीक्षा को लेकर तनाव थोड़ा कम हो जाता है।
> -आशीष एंजेल, छात्र

> सीबीएसई की यह पहल सकारात्मक है। इससे बच्चों के साथ अभिभावकों का भी तनाव दूर होगा। परीक्षार्थियों में परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए हर वो पहल करनी चाहिए जिससे वे बिना तनाव के पढ़ें और खुशनुमा माहौल में परीक्षा दें।
> - ज्योति अरोड़ा, प्रधानाचार्या, माउंट आबू स्कूल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए जा रहे मीम्स। (सोशल मीडिया)

मीम्स पर विद्यार्थियों की टिप्पणी

- दया पता लगाओ, सीबीएसई को ह्यूमर का इंजेक्शन किसने दिया।
- लेकिन वास्तविकता में न नींद पूरी हुई न सिलेबस
- जागरूकता भरी इस मीम्स से भारत बदल रहा है।

दोषी की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

जेसिका लाल हत्याकांड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जेसिका लाल हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा की समय पूर्व रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने दिल्ली सरकार को मामले में स्थिति रिपोर्ट के साथ ही सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) के संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को निर्देश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। मनु शर्मा को 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

मनु शर्मा ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा 19 सितंबर 2019 को दिए गए आदेश को रद करने की मांग की। उसने एसआरबी द्वारा 19 जुलाई 2019 को समय पूर्व रिहाई की याचिका को रद करते हुए की गई संस्तुति को स्वीकार कर लिया था। अधिवक्ता अमित सैनी के माध्यम से दायर याचिका में मनु शर्मा ने कहा कि प्राधिकारी ने समय पूर्व रिहाई की याचिका को गलत और मनमाने तरीके से खारिज किया है। याचिका के अनुसार मनु शर्मा बगैर किसी राहत के 15 साल की सजा काट चुका है और वह समय पूर्व रिहाई के योग्य है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2006 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2010 में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। 30 अप्रैल 1999 की रात को दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में एक रेस्टोरेंट में शराब परोसने से इन्कार करने पर मनु शर्मा ने जेसिका लाल को गोली मार दी थी।

124 नए नियम बनाने की सिफारिश की गई है राज्यसभा के सुचारु संचालन के लिए। सामान्य प्रयोजन समिति की ओर से पेश नियम समीक्षा समिति की रिपोर्ट में 77 नियमों में संशोधन करने का सुझाव भी दिया गया है।

पूर्वोत्तर से नहीं हटेगा अनुच्छेद 371 : शाह

इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले आदिवासी भारतीय संस्कृति की धरोहर

ईटानगर, एजेंसियां : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देने वाले अनुच्छेद 371 को हाथ नहीं लगाया जाएगा। इससे कुछ राज्यों को अल्पकालिक और विशेष प्रावधानों से लैस किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह ने कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर मैं पूरे पूर्वोत्तर को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 371 को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से क्षेत्र में अफवाह फैलाई जा रही है कि अनुच्छेद 371 का भी यही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने से पहले तक पूर्वोत्तर देश से केवल भौगोलिक रूप से जुड़ा था। लेकिन देश के बाकी हिस्से से क्षेत्र का भावनात्मक जुड़ाव तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद से ही हुआ है। शाह ने यह भी उम्मीद जताई कि अरुणाचल प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लक्ष्य में अपना भी अहम योगदान देगा। भारत के लिए पूर्वोत्तर हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण है। इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले आदिवासी भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। 33 साल पहले आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इससे यहां रह रहे लोगों के लिए विकास का रास्ता बना। भारत के लिए यह भूमि हर तरह से बेहद महत्वपूर्ण है। 27 ट्राइब और 120 से अधिक सब-ट्राइब ये क्षेत्र बेहद खास है। मैं अरुणाचल प्रदेश में हर किसी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके अधिकारों और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति पूर्वोत्तर के बिना अधूरी है। भारत में विभिन्न स्थानों में अभिवादन के अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन देश में अरुणाचल ही अकेला ऐसा राज्य है जहां सब लोग एक-दूसरे को अभिवादन में 'जयहिंद' बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय मानते हैं कि पूर्वोत्तर का विकास और लोगों का जनकल्याण पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज समूचा पूर्वोत्तर जानता है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है।

अरुणाचल का स्थापना दिवस

- केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा-पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति की रक्षा करने को केंद्र सरकार प्रतिबद्ध
- बोले-अरुणाचल ही अकेला ऐसा राज्य जहां सब लोग अभिवादन में 'जयहिंद' बोलते हैं

असम के लखीमपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत बांस की पारंपरिक टोपी पहनाकर किया। गृहमंत्री शाह अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा भारत-चीन सीमा पर पहुंचे थे। एएनआइ

अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति को भारत ने किया खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्तियों को भारत ने सिरे से खारिज किया है। भारत ने कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और गृहमंत्री का वहां जाना सामान्य बात है। पहले भी केंद्रीय मंत्री व नेता अरुणाचल जाते रहे हैं। दरअसल, गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में शाह ने हिस्सा लिया। चीन ने अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताते हुए शाह की यात्रा पर आपत्ति जताई। उसका कहना था कि यह न सिर्फ चीन की संप्रभुता में खलल है, बल्कि द्विपक्षीय सीमा समझौते का उल्लंघन है। भारत के हर बड़े नेता या मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे के समय चीन की ओर से इसी तरह से बयान आते रहे हैं, जिन्हें भारत तवज्जो नहीं देता है। अहम बात यह है कि मोदी सरकार के दौरान पूर्वोत्तर भारत के विकास को अधिक तवज्जो दी जा रही है और इस सिलसिले में सभी केंद्रीय मंत्रियों को पूर्वोत्तर भारत का दौरा करने का विशेष निर्देश दिया गया है।

अपील का समय रहते डेथ वारंट जारी होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का समय रहते निचली अदालत द्वारा डेथ वारंट जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी अनिल सुरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ गुजरात की सत्र अदालत द्वारा जारी डेथ वारंट पर रोक लगा दी है।

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्चतम न्यायालय के 2015 के एक फैसले का जिक्र किया। इसमें कहा गया था कि किसी दोषी को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय मिला हुआ है। इससे पहले उसके खिलाफ डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि इस संबंध में एक फैसला रहने के बावजूद निचली अदालतें डेथ वारंट कैसे जारी कर रही हैं।' पीठ ने आगे कहा कि किसी को तो यह समझाना ही पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया को इस प्रकार से होने नहीं दिया जा सकता। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में सहायता करने को कहा और उनसे उच्चतम न्यायालय के अदेश के बावजूद डेथ वारंट जारी होने के कारणों का पता लगाने को कहा।

न्याय-व्यवस्था

- हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को मिला है 60 दिन का समय
- गुजरात में दुष्कर्म और हत्या के दोषी के खिलाफ जारी डेथ वारंट पर रोक

यह है मामला

गुजरात के सूरत में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने वाले अनिल की फांसी की सजा पर हाई कोर्ट द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएस काला ने डेथ वारंट जारी कर दिया। उन्होंने अनिल को 29 फरवरी को फांसी देने का आदेश दिया। डेथ वारंट के मुताबिक, उसे अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में सुबह 4.30 बजे फांसी दी जानी थी। इसी के खिलाफ अनिल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अंसल बंधुओं को राहत, नहीं बढ़ेगी सजा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड में लापरवाही के दोषी देश के जाने-माने बिल्डर अंसल बंधुओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल की सजा बढ़ाए जाने की मांग वाली अग्निकांड पीड़ितों की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। उपहार त्रासदी पीड़ित संघ ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर अंसल बंधुओं की सजा बढ़ाने की मांग की थी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, एनवी रमना और अरुण मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने क्यूरेटिव याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका और संबंधित दस्तावेज देखने के बाद उन्हें यह मामला क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए रूपा अशोक हुर्रा केस में तय मानकों में नहीं आता। कोर्ट ने इसके साथ ही क्यूरेटिव याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई किए जाने की मांग अर्जी भी खारिज कर दी।

उपहार त्रासदी पीड़ित संघ ने क्यूरेटिव याचिका में मांग की थी कि अंसल बंधुओं को लापरवाही का दोषी मानते हुए शुरू में सुनाई गई दो वर्ष के कारावास की सजा बहाल की जाए। याचिका में कहा गया था कि नौ फरवरी 2017 के फैसले में कोर्ट ने सुशील अंसल को अधिक उम्र और बीमारियों को देखते हुए उनकी सजा जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दी थी, जबकि छोटे भाई गोपाल अंसल को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। उस फैसले में कोर्ट ने दोनों भाइयों पर लगाया गया 30-30 करोड़ का जुर्माना यथावत रखा था।

क्यूरेटिव याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने सुशील अंसल को बीमारियों के आधार पर राहत दी थी, लेकिन उनकी बीमारियों की रिपोर्ट कोर्ट के सामने नहीं थी।

फरवरी 2017 में जब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था उस समय तक सुशील अंसल पांच महीने 20 दिन (माफी मिला कर नौ महीने)और गोपाल अंसल चार महीने 22 दिन की जेल काट चुके थे। गोपाल अंसल को आगे की सजा भुगतनी थी।

उपहार सिनेमा अग्निकांड

- सुप्रीम कोर्ट ने त्रासदी से प्रभावितों की क्यूरेटिव याचिका खारिज की
- 1997 में दिल्ली के सिनेमा हाल में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की हुई थी मौत

सुशील अंसल फाइल/ एपी

गोपाल अंसल फाइल/ प्रेट्र

13 जून 1997 को बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान हुआ था हादसा

13 जून 1997 को बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी और भगदड़ में सौ से ज्यादा घायल हुए थे। ज्यादातर मौते धुएं में दम घुटने से हुई थी। सिनेमाघर अंसल बंधुओं का था। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अंसल बंधुओं को घोर लापरवाही का दोषी ठहराया था। हालांकि इस केस ने सजा के स्तर पर कई उतार-चढ़ाव देखे। कभी अंसल बंधुओं को दो साल की जेल हुई तो कभी घटकर एक साल रह गई। बाद में सिर्फ जुर्माना अदा करने की शर्त पर सजा जेल में रहने की अवधि तक सीमित हो गई। अंतत: नौ फरवरी 2017 को पुनर्विचार याचिका पर नया फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने छोटे भाई गोपाल अंसल को एक साल की कैद भुगतने का आदेश सुनाया, जबकि बढ़ती उम्र के कारण सुशील अंसल पर कोर्ट का रहम कायम रहा।

गृहमंत्री शाह सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मालदीव से आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को मालदीव के अपने समकक्ष शेख इमरान अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के नेता सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। अब्दुल्ला गुरुवार को चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। यह पहला मौका होगा जब वह गृहमंत्री शाह से मिलेंगे।

एक सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यहां बताया कि दोनों देशों के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में भारतीय टीम का नेतृत्व गहमंत्री अमित शाह और मालदीव की टीम का नेतृत्व शेख इमरान अब्दुल्ला करेंगे। भारत उन देशों में शामिल है, जिसने वर्ष 1965 में मालदीव की आजादी का सबसे पहले समर्थन किया था। इसके बाद भारत ने मालदीव के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किया था।

अधिकारी ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध हैं, जो बहुत मजबूत है। हालांकि, फरवरी 2012 से नवंबर 2018 तक दोनों देशों के संबंधों में खटास भी रही। भारत के मिनिकॉय (लक्ष्यद्वीप) से मालदीव सिर्फ 70 नॉटिकल मील (करीब 129 किलोमीटर) दूर है, जबकि भारत के उत्तरी तट से इसकी दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी महत्व रखता है।

विदेशी छात्रों को लुभाने दर्जनभर देशों में लगेंगे मेले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह भारत भी उच्च शिक्षा का बड़ा हब बनना चाहता है। सरकार इसे लेकर पूरी ताकत से जुड़ी हुई है। इस कड़ी में अब वह विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए दुनिया के करीब दर्जन भर देशों में एजुकेशन मेले का आयोजन करने जा रही है, जो इसी महीने से शुरू हो रहे हैं। फिलहाल यह आयोजन उन्हीं देशों में होगा, जिन देशों से मौजूदा समय में सबसे ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं। इनमें पड़ोसी देशों सहित अफ्रीकी और खाड़ी देश शामिल हैं।

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम के तहत इस साल एक लाख से ज्यादा विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों की ओर आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, मौजूदा समय में करीब 50 हजार छात्र ही हर साल पढ़ाई के लिए भारत आते है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, विदेशी छात्रों के लिए पहले से ही कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें उन्हें जहां आकर्षक छात्रवृत्ति दी जा रही है, वहीं फीस में भी 25 से सौ फीसद तक की रियायत दी जा रही है। सरकार अब इस मुहिम को और तेज करने में जुटी है। इसके तहत छात्रवृत्ति को लेकर दुनिया के करीब 50 देशों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। बता दें कि यह छात्रवृत्ति प्रतिभाशाली बच्चों को दी जाती है। दुनिया के दूसरे देश भी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ही प्रोग्राम चला रहे हैं।

विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए मौजूदा समय में देश के करीब 160 उच्च शिक्षण संस्थान 1,500 से ज्यादा नए कोर्स ऑफर कर रहे हैं। वैसे भी यह मुहिम तब शुरू की गई है, जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। सरकार इस मुहिम में इसलिए पूरी ताकत से जुड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में यह आय का एक बड़ा साधन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में अकेले भारत से करीब चार लाख छात्र हर साल उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाते हैं, जो वहां करीब 85 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा पढ़ाई पर खर्च करते हैं। यह भारत में उच्च शिक्षा पर खर्च होने वाले बजट के दोगुने से भी ज्यादा है। मौजूदा समय में देश का उच्च शिक्षा का बजट करीब 40 हजार करोड़ के आसपास है।

- स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा आयोजन, नेपाल सहित अफ्रीकी और खाड़ी देशों पर फोकस
- विदेशी छात्रों की संख्या एक लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य, फिलहाल करीब 50 हजार ही आते हैं

राज्यवार अल्पसंख्यक घोषित करने की याचिका की सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐसी याचिका की सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने की मांग की गई थी। साथ ही राज्यवार अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग की गई थी। जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रवींद्र भट की पीठ ने अधिवक्ता व भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय से अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा। उन्हें अपनी याचिका अन्य उचित संस्था के समक्ष रखने की इजाजत दी गई है।

उपाध्याय की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, शीर्ष न्यायालय के 2002 में दिए आदेश के मुताबिक राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाए। इसके लिए जरूरी है कि खास समुदाय की प्रदेश में रहने वाली आबादी सार्वजनिक की जाए। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है लेकिन उसे कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब व मणिपुर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस पर पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को जो भी बात कहनी है-वह उसे सुप्रीम कोर्ट से इतर अन्य कहीं कह सकता है। शीर्ष न्यायालय के पास याचिका को लेकर दो विकल्प हैं। वह उसे खारिज कर सकती है या याचिका वापस ले ली जाए।

राष्ट्रीय संग्रहालय के खानपान महोत्सव में मांसाहार पर रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय संग्रहालय ने भारतीय पाकशास्त्र के इतिहास पर सप्ताह भर चलने वाले 'हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिका' नामक प्रदर्शनी और महोत्सव के मेन्यू से अंतिम समय में मांसाहार को हटा दिया है। संग्रहालय ने कहा कि यह निर्णय भावनात्मक कारणों से लिया गया है।

संग्रहालय की वेबसाइट पर जब आयोजकों ने मेन्यू में मांसाहार देखा तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। इसके थोड़ी ही देर बाद यह तय हुआ कि 25 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में सिर्फ शाकाहारी भोजन और व्यंजन को परोसा जाएगा। इस खानपान महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय और निजी फर्म वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज (ओएसएमएस) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय संग्रहालय के अतिरिक्त महानिदेशक सुब्रत नाथ ने कहा, 'ओएसएमएस ने हमारे साथ मांसाहार के मेन्यू पर कोई बातचीत नहीं की थी। हमें लगा कि संस्थान की नीति के तहत वे यहां मांसाहारी भोजन को नहीं परोसेंगे। उन्होंने इस विवाद के पैदा होने पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि हमें इस प्रकार के विवाद का कभी सामना नहीं करना पड़ा।'

सुब्रत नाथ ने कहा, 'हमारी वेबसाइट पर मांसाहार का मेन्यू एक दिन के लिए था और हमने उसे वापस ले लिया। संग्रहालय में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भरी पड़ी हैं और हम यहां आने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह एक अलिखित नीति है जो लोगों की भावनाओं पर आधारित है।' यह पूछे जाने पर कि क्या यह प्राचीन पाककला इतिहास से भटकाव है जब मांसाहार सामान्य था, नाथ ने कहा कि अतिथियों को इतिहास के बारे में बताया जाएगा, लेकिन मांसाहार नहीं परोसा जाएगा।

- संग्रहालय ने अंतिम समय में भावनात्मक कारणों से लिया फैसला
- 25 फरवरी तक चलेगा 'हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिका'

देश में कायम हो मातृभाषा के प्रयोग वाली शासन व्यवस्था : वेंकैया

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल वाली शासन व्यवस्था कायम की जाए, वह लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगी। यह बात देश के उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में कही।

नायडू ने कहा, वैश्विक स्तर पर 40 फीसद आबादी उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं करती जिसे वह आसानी से बोलती या समझती नहीं है। ऐसे में सरकारी व्यवस्था में भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल आमजन को बेहतर तरीके से शासन से जोड़ सकता है। उससे शासन व्यवस्था ज्यादा जनआधारित बनेगी। उप राष्ट्रपति ने कहा, भाषा प्रत्येक देश के सांस्कृतिक जीवन को आकार देती है। साथ ही वह देश के विकास की नींव रखती है। भाषा ही वह सूत्र होती है जो भूत से वर्तमान को जोड़ती है। इसलिए वह हमेशा भाषाई विरासत के संरक्षण पर जोर देते रहे हैं। रोजगार से भाषा के जुड़ाव पर जोर देते हुए नायडू ने कहा, सरकारी नौकरियों की भर्ती में भारतीय भाषाओं से जुड़ाव की योग्यता को भी अनिवार्य किया जाए, क्योंकि भाषा की सरलता समावेषी विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है। हाईस्कूल तक की पढ़ाई में भारतीय भाषाओं में निर्देश दिए जाने को अनिवार्य बनाया जाए। नायडू ने कहा, मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाला आयोजन सिर्फ एक दिन ही न किया जाए, बल्कि इसे व्यवहार में लाया जाए। इससे लोगों को अपनी भाषा के घर, समुदाय, बैठकों-सभाओं व सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की आदत पड़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर देशभर से आए छात्रों के एक दल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भेंट की। इस मौके पर संसद परिसर में डॉ. भीमराम आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाया। ध्यान रहे 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। एएनआइ

22 भाषाओं में बोले उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली : वेंकैया नायडू ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 22 भारतीय भाषाओं में बोलकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने इन सभी भाषाओं में उपस्थित जनों का अभिवादन किया। नायडू ने लोगों से अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने की जरूरत बताई।

केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा समूह अप्रैल में जाएगा जम्मू-कश्मीर

नई दिल्ली, प्रेट्र : 40 केंद्रीय मंत्रियों का दूसरा प्रतिनिधिमंडल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान वह केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का हाल जानेगा। सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को बताया, 'जम्मू-कश्मीर जाने वाले 40 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के गठन के संबंध में संसद के बजट सत्र के बाद फैसला लिया जाएगा।' एक विराम के बाद बजट सत्र दो मार्च को शुरू हो रहा है और तीन अप्रैल तक चलेगा।

अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नाम पर फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) करेगा। सभी मंत्रियों को स्पष्टतौर पर जिले आवंटित किए जाएंगे और कश्मीर घाटी फोकस में होगी। पिछले प्रतिनिधिमंडल के कुछ मंत्रियों को नए समूह में भी शामिल किया जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रियों का समूह केंद्र व केंद्रशासित प्रदेश की तरफ से चलाई जा रही विकास योजनाओं का जायजा लेगा। वह राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करेगा। मंत्रियों का समूह स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिये सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली की स्थिति, यूटी के प्रशासनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली आदि के बारे में वास्तविक जानकारी हासिल करेगा।

ज्ञात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पिछले महीने 37 केंद्रीय मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था और विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की थी। टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की थी। प्रतिनिधिमंडल में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खेल मंत्री किरन रिजिजू, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय व जी. किशन रेड्डी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप चुके हैं।

- केंद्र व केंद्रशासित प्रदेश की विकास योजनाओं का जानेगा हाल
- 40 केंद्रीय मंत्री होंगे टीम में, पिछले महीने गए दल में शामिल थे 37 मंत्री

डीजीपी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

आठ मंजिला होंगी सेंट्रल विस्टा की सभी इमारतें

बड़ी योजना

राष्ट्रपति भवन के दाहिने छोर पर प्रधानमंत्री और बाएं छोर पर उप राष्ट्रपति का होगा आवास, इंडिया गेट की ऊंचाई से अधिक ऊंची नहीं होगी कोई भी इमारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद भवन से लेकर राजपथ के किनारे वाली प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा की सभी इमारतें किसी भी हाल में इंडिया गेट (42 मीटर) से अधिक ऊंची नहीं होंगी। केंद्रीय सचिवालय के सभी कर्मचारियों को एकसाथ काम करने के लिए बनाई जाने वाली इसकी सभी इमारतें आठ मंजिला और समान ऊंचाई की होंगी। इस क्रम में लगभग एक दर्जन पुराने भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इनकी जगह आधुनिक संसाधनों से लैस 10 नई इमारतों के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेज दी गई है।

संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सभी इमारतें एक जैसे वास्तु और लुटियंस क्षेत्र की विशेषताओं के अनुकूल होंगी। दिल्ली जैसे महानगर के बीच में होने के बावजूद यहां का तापमान अन्य जगहों की तुलना में कम होता है। प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा में खुली जगह को बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। संसद भवन की पुरानी इमारत जहां गोलाकार है, वहीं नई इमारत त्रिभुजाकार और बहुमंजिला होगी। नया संसद भवन ऐसा होगा, जिसकी लोकसभा में एक हजार और राज्यसभा में पांच सौ सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। इनके अलावा राज्यसभा व लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों के बैठने का भी बंदोबस्त होगा। नए संसद भवन के निर्माण के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को संशोधित कर दिया गया है। नई इमारत पुराने संसद भवन के सामने बनने वाली है। इसके निर्माण पर कुल 776 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे हर हाल में सालभर के भीतर तैयार कर देने का लक्ष्य है, जहां आगामी गणतंत्र दिवस सामान्य रूप से मनाया जा सके। जिन भवनों को ध्वस्त कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाने हैं, उनमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, विज्ञान भवन, लोकनायक भवन व उप राष्ट्रपति भवन प्रमुख हैं। हालांकि, विदेश मंत्रालय की नवनिर्मित इमारत जवाहरलाल नेहरू भवन को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पा रहा है। यह इमारत वर्ष 2011 में ही बनी है। इसी तरह नेशनल म्यूजियम भवन को लेकर भी संदेह बरकरार है। हालांकि, इसे हेरिटेज बिल्डिंग मानते हुए इसके हटाए जाने की संभावना कम है।

प्रोजेक्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के मुकाबिक, केंद्रीय सचिवालय की कामन बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें 70 हजार लोगों के एक साथ बैठकर काम करने की व्यवस्था होगी। ये इमारतें ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर सात मंजिला होंगी, जिन्हें आमतौर पर आठ मंजिला कहा जा सकता है। एक बात स्पष्ट है कि लुटियंस जोन के बंगलों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। राष्ट्रपति भवन के दाहिने हिस्से में प्रधानमंत्री आवास और बाएं भाग में उप राष्ट्रपति आवास बनाया जाएगा। साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के गेट तक के हिस्से को बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।

71 विधायकों (एक नामित विधायक) में से 17 ऐसे हैं उत्तराखंड में जो अब तक अपनी आधी विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। पांच विधायकों की ही 75 फीसद से अधिक निधि हुई खर्च।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 फरवरी 2020

भारतीयता और हिंदू एक-दूसरे के पूरक : भागवत

जागरण संवाददाता, रांची

- रांची में संघ प्रमुख ने कहा, हिंदुओं पर राष्ट्रनिर्माण की जिम्मेदारी
- देश में कुछ बुरा होता है तो इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकते हिंदू

'भारतीयता और हिंदू एक-दूसरे के पर्याय और पूरक हैं। अपने देश की संस्कृति, परंपरा व विचारों का पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व हिंदू शब्द करता है। ऐसे में हिंदुओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश में अच्छा या बुरा जो भी होता है, उन सबकी जिम्मेदारी हिंदुओं को लेनी होगी।'

यह कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का। वह गुरुवार को रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि देश को बढ़ाना है तो हिंदू को बढ़ाना होगा। आज विश्व को भारत की जरूरत है। हमें फिर विश्व गुरु बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को अपना स्वार्थ छोड़कर आगे आना होगा।

भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया का होगा भला : संघ प्रमुख ने कहा कि विश्व के कुछ देश मानते हैं कि राष्ट्र के बड़ा होने से विश्व को खतरा है। उन्होंने एक बार के अपने यूके प्रवास का संदर्भ देते हुए कहा कि मेरे संबोधन से पहले वहां कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि यहां नेशलिज्म शब्द को लोग फासीवाद से जोड़कर देखते हैं। इस शब्द के प्रयोग से परहेज करते हैं।

वह मानते हैं कि राष्ट्र का बड़ा होना अच्छा नहीं है। हमारा मानना इससे अलग है। इतिहास गवाह रहा है कि भारत जब-जब बड़ा हुआ है तब-तब दुनिया का भला ही हुआ है। आज दुनिया को भारत की जरूरत है। राष्ट्र के नाते भारत बड़ा होगा तो विश्व का कल्याण ही होगा।

भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता : सरसंघचालक ने कहा कि भारत में रहने वाले चाहे वे किसी भी पंथ, मत, भाषा और जाति के हों, सभी भारतीय संस्कृति से आपस में जुड़े हुए हैं। यह संस्कृति ही हिंदू है। विदेश में भी जब यहां के इस्लाम या ईसाईयत को मानने वाले जाते हैं तो उन्हें भी हिंदू ही कहा जाता है। मेरी बातें कुछ लोगों को खराब लगती हैं, लेकिन यहीं हकीकत है। यहां के लोगों का डीएनए 40 हजार वर्ष पुराना है। अंदर से सभी एक हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू कहने वालों को संगठित करने के लिए समाज को खड़ा करना होगा। जब समाज खड़ा होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।

सेवा भावना से ही संघ से जुड़ें : इस मौके पर संघ प्रमुख ने समाज के लोगों से भी संघ से सेवा भाव के साथ जुड़ने की अपील की। समाज के प्रभावशाली लोगों, सेवानिवृत्त लोगों, छात्रों और बुद्धिजीवियों से समाज के लिए समय देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सबके सम्मिलित प्रयास से भारत आगे बढ़ेगा। साथ ही यह नसीहत भी दी कि संघ से कोई आशा-प्रत्याशा, महत्वाकांक्षा या स्वार्थ भावना लेकर नहीं जुड़ें, बल्कि सेवा, समर्पण और त्याग की भावना के साथ जुड़ें।

आरएसएस प्रमुख गुरुवार को डॉ. रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित संघ के समागम में पहुंचे। इस दौरान स्वयंसेवकों से मुलाकात के बाद वह कुछ अलग अंदाज में नजर आए। मनोरंजन

चुनावी हलफनामा मामले में कोर्ट में पेश हुए फड़नवीस

- पूर्व मुख्यमंत्री को 15 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ा

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस एक आपराधिक मामले में गुरुवार को नागपुर के एक कोर्ट में पेश हुए। यह मामला 2014 में चुनावी हलफनामे में फड़नवीस द्वारा अपने खिलाफ कथित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने से जुड़ा है। फड़नवीस के खिलाफ की गई शिकायत में उन पर आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है। भाजपा नेता को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएस इंगले ने गुरुवार को कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका दिया था। अदालत में फड़नवीस की पेशी के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मजिस्ट्रेट ने कहा, 'आरोपी (फड़नवीस) अदालत में पेश हो गए। अपराध जमानती है। उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, इसलिए जमानत दी जाती है।' वकील सतीश उके की अर्जी पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। नवंबर 2019 से फड़नवीस को पेशी से चार बार छूट दी गई थी। कोर्ट में पेश होने के बाद फड़नवीस ने बाहर मौजूद संवाददाताओं से कहा कि उनका चुनावी हलफनामा उनके वकील ने दायर किया था। फड़नवीस ने कहा, 'मेरे खिलाफ जो दो मामले हैं वे सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़े हैं। मेरे खिलाफ कोई भी निजी शिकायत नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मामलों में सुलह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामे में दो मामलों का खुलासा नहीं करने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। अपने खिलाफ शिकायत को फड़नवीस ने 'राजनीति से प्रेरित' बताया और कहा, 'मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन है।

देवेंद्र फड़नवीस। फाइल

जेयू के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने माकपा के छात्र संगठन को पछाड़ा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इंजीनियरिंग विभाग में हुए चुनाव में एबीवीपी ने दूसरे स्थान पर काबिज होते हुए माकपा की छात्र ईकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) को तीसरे पायदान पर धकेल दिया। इस चुनाव में इंजीनियरिंग विभाग में कुल 1405 वोट पड़े, जिनमें से डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट (डीएसएफ) को 1167 वोट मिले। एबीवीपी की झोली में 115 वोट आए, वहीं एसएफआइ को 70 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद को महज 29 वोट के साथ चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। जेयू के कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के लिए चुनाव बुधवार को हुए थे।

बता दें बंगाल की छात्र राजनीति में जेयू वाममोर्चा (वामो) का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। जेयू परिसर में पिछले कुछ समय के दौरान हुई घटनाओं के कारण सबकी इस पर नजर थी। पिछले साल यहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो का छात्रों ने घेराव किया था, जिन्हें छुड़ाने खुद बंगाल के राज्यपाल को आना पड़ा था।

न्यूज गैलरी

एम्स में भर्ती साध्वी पद्मावती की हालत गंभीर

नई दिल्ली : गंगा की अविरलता के लिए लंबे समय से आमरण अनशन कर रहीं साध्वी पद्मावती यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में चार दिनों से आइसीयू में भर्ती हैं। उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर का सहारा भी दिया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। (राब्यू)

एयरसेल मैक्सिस की जांच 4 मई तक पूरी हो : कोर्ट

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआइ और ईडी को एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच पूरी करने के लिए 4 मई तक का समय दिया है। ईडी ने अदालत को बताया कि उसकी जांच अभी जारी है, जबकि सीबीआइ की तरफ से कहा गया कि मलेशिया में इस मामले का कुछ लिंक जांचना है और इसके लिए वहां अनुमति पत्र भेजा गया, जिसमें कुछ प्रगति हुई है। (जासं)

दिल्ली में वनवासी रक्षा परिवार कुंभ 23 को

नई दिल्ली : वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की ओर से 23 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वनवासी रक्षा परिवार कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के 11 राज्यों से वनवासी जागरण और कल्याण कार्य में लगे हुए कार्यकर्ता शामिल होंगे। (जासं)

कांग्रेस ने राजद पर बढ़ाया दबाव, रास में भी मांगी सीट

विवाद ▶ महागठबंधन में तकरार की एक और वजह बन सकती है यह दावेदारी

शत्रुघ्न, निखिल, सदानंद और राजीव शुक्ला हैं रेस में

अरुण अशेष, पटना

वामदलों का भाजपा विरोधी एकजुट महागठबंधन का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, पटना : पिछले कई चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन से त्रस्त वाम दलों ने अब बिहार में भाजपा विरोधी एकजुट महागठबंधन का प्रस्ताव दिया है। यानी भाकपा और माकपा जैसे वामदल चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई करे। महागठबंधन में शामिल होने का विचार इन्हें पसंद है। फिलहाल ये पार्टियां इस विवाद से अलग रहना चाहती है कि किसके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। भाकपा के बिहार राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह ने गुरुवार को कहा कि जरूरी यह है कि भाजपा विरोधी सभी दल एक साथ चुनाव लड़ें। जीत की गारंटी हो जाएगी। महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव आता है। कोई बैठक बुलाई जाती है तो उनकी पार्टी जरूर शामिल होगी।

बिहार में महागठबंधन में तकरार की एक और वजह पैदा हो चुकी है। यह राज्यसभा की एक सीट है। इस पर कांग्रेस ने दावा किया है। चुनाव अप्रैल में होगा। उस महीने राज्यसभा में बिहार की पांच सीटें खाली हो रही हैं। अभी इन पांच में से तीन पर जदयू और दो पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन, दो महीने बाद जब चुनाव होंगे, एनडीए के हाथ से दो सीटें निकल कर विपक्ष के खाते में आ जाएंगी। अब तक यही माना जा रहा था कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते दोनों सीटें राजद के कोटे में जाएंगी। आज गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा. मदन मोहन झा ने कहा कि वादे के मुताबिक एक सीट कांग्रेस की होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट यह कह कर कम दी गई थी कि इसकी भरपाई राज्यसभा चुनाव में कर दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राजद नेतृत्व इस प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा।

मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में राज्यसभा का यह अंतिम चुनाव होगा। राज्यसभा के लिए अगला चुनाव 2022 में होगा। हालांकि, परिपाटी के हिसाब से अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पिछले दिनों रांची में हुई लालू प्रसाद से मुलाकात का असली संदर्भ भी यही था। सिन्हा 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में आ गए थे। चुनाव लड़े। मगर कामयाबी नहीं मिली।

बहरहाल, इस इकलौती सीट के लिए कांग्रेस में भी कम उठापटक नहीं है। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, विधायक सदानंद सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश के राजीव शुक्ला भी कांग्रेस कोटे के गंभीर दावेदार हैं। निखिल कुमार और सदानंद जहां राज्य में कांग्रेस के सामाजिक समीकरण के लिहाज से जरूरी हैं तो राजीव शुक्ला पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजद के सहयोग से कांग्रेस के डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही राज्यसभा में जा चुके हैं।

वहीं, जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की इस दावेदारी से महागठबंधन में तकरार और बढ़ सकती है।

झारखंड में भाजपा विधायक ढुलू महतो से छीने गए अंगरक्षक

जासं, धनबाद: झारखंड में सत्ता बदलते ही बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को धनबाद के एसएसपी किशोर कौशल ने ढुलू महतो के सारे अंगरक्षकों को वापस ले लिया है। उन्हें जिला पुलिस के तीन और जैप थ्री से पांच अंगरक्षक मिले थे। एक हवलदार और चार जवानों को हाउस गार्ड के नाते उनके धनबाद के चिटाही आवास पर तैनात किया गया था। अब इन सबको सबको हटा दिया गया है। एसएसपी ने कई पुलिस अफसरों को ढुलू महतो की तलाश में लगाया है।

खोली जा रही पुरानी फाइलें : धनबाद क्षेत्र के दबंग विधायक ढुलू के खिलाफ दबी पड़ी तमाम पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं। बुधवार को जमीन पर कब्जा करने के एक साल पुराने एक मामले में पुलिस ने ढुलू के घर पर छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की थी। हालांकि मौके से ढुलू फरार हो गए। पुलिस को वहां विधायक समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने विधायक के चार समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। ढुलू की तलाश में पुलिस ने धनबाद से रांची तक नाकेबंदी और छापेमारी की, लेकिन अभी तक वह पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। इस बीच एक मामले में उन्हें गुरुवार को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। शुक्रवार को विधायक ढुलू महतो के बचाव में प्रदेश भाजपा आगे आई, वहीं आजसू ने भी ढुलू पर हो हो रही कार्रवाई को गलत बताया।

कैप्टन बोले-पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाओ मुद्दे, प्रेस में नहीं

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- कांग्रेस विधायकों ने कहा- आप मिलते ही नहीं
- विपक्ष से निपटने को हुई बैठक में विधायक व मंत्री आपस में ही भिड़े

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में विरोधियों से निपटने को रणनीति बनाने के लिए हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायक और मंत्री आपस में ही भिड़ गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब विधायकों से कहा कि वह अपने मसले पार्टी प्लेटफार्म पर जितना मर्जी उठा लें, लेकिन मीडिया में न जाएं। इस पर विधायकों ने कहा कि आप मिलते नहीं हैं।

सबसे अहम मुद्दा था महंगी बिजली का। विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस पर आक्रामक रुख अपनाने को कहा। यह भी कहा कि अकाली दल ने प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ महंगे समझौते किए हैं, लेकिन हम रक्षात्मक हो रहे हैं। सदन में शिरोमणि अकाली दल ने महंगी बिजली को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया। स्पीकर द्वारा इसे खारिज करने पर अकाली विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे तो उन पर आक्रामक रुख अपनाने के बजाय कांग्रेसी विधायक चुपचाप बैठे रहे।

सीएलपी की मीटिंग में विधायकों ने अपने काम न किए जाने को लेकर मंत्रियों से शिकायत की जिस पर मंत्रियों ने भी जवाबी हमले किए। यहां तक कि इससे मुख्यमंत्री भी नहीं बच सके। विधायकों ने उन्हें कहा कि आप मिलते ही नहीं हैं। इस पर कैप्टन ने कहा कि जो भी विधायक अपने हलके के प्रोजेक्ट को लेकर आता है वह उसे समय देते हैं, लेकिन आप लोग तो अपने निजी काम ही ज्यादा लेकर आते हो।

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल

25-25 करोड़ रुपये दिए जाएं : मीटिंग में विधायकों ने 25-25 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र देने का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि यह अभी से दिया जाए और इसके नियम भी जल्द से जल्द फाइनल किए जाएं क्योंकि अब चुनाव में जाने को ज्यादा समय नहीं रह गया है।

ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया : मीटिंग में विधायकों ने ड्रग्स को लेकर हाई कोर्ट में दी गई सीलबंद रिपोर्ट का मुद्दा भी उठाया। कहा कि पिछले डेढ़ साल से यह सीलबंद पड़ी है, जबकि इसकी कई तारीखें पड़ चुकी हैं। कई विधायकों ने दिल्ली के पंजाब भवन के ए ब्लॉक में विधायकों को कमरे अलॉट न करने का मामला भी उठाया।

'फसल बीमा योजना में बदलाव किसान विरोधी'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र के प्रीमियम की हिस्सेदारी 25 फीसद घटाने पर सुरजेवाला ने सरकार को घेरा

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में बदलाव के सरकार के फैसले को किसानों के खिलाफ बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। पार्टी के अनुसार केंद्र सरकार ने इस योजना में अपना अंशदान 50 फीसद से घटाकर 25 फीसद कर दिया है। किसानों को अब बीमा के लिए दो फीसद की जगह 27 फीसद देने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने यह बात कही।

अभी तक इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें 50-50 फीसद राशि दे रही थीं। लेकिन कैबिनेट ने जो बदलाव किया है उसके बाद केंद्र सरकार 25 फीसद राशि ही देगी। यदि इस कटौती को राज्य सरकारें वहन नहीं करेंगी तो किसानों का प्रीमियम दो से बढ़कर 27 फीसद पर पहुंच जाएगा। आम किसानों के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रीमियम देना संभव नहीं होगा और अंततः योजना बंद हो जाएगी।

पीएम मोदी के फरवरी 2016 के सीहोर में दिए बयान का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि तब किसानों से 12 फीसद प्रीमियम को पीएम ने लूट कहा था, अब 27 फीसद लूट नहीं है? उन्होंने कहा कि केंद्र की तर्ज पर यदि राज्यों ने भी अपनी हिस्सेदारी 25 फीसद घटा दी तो किसानों का प्रीमियम 57 फीसद हो जाएगा। सुरजेवाला के मुताबिक, इसमें एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई राज्य अपने प्रीमियम का हिस्सा देने में देर करेगा तो उस राज्य में फसल बीमा योजना बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के कदम से साफ है कि राज्य सरकार के रुख का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। योजना में तीसरा बदलाव यह किया गया है कि देश के 732 में से 151 ज्यादा आपदा वाले जिलों में पीएम फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना से अलग एक तीसरी स्कीम सरकार लाएगी। इसका मतलब यह है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां ये योजनाएं लागू नहीं रहेंगी।

कैबिनेट के फैसले से प्रभावित नहीं होंगे किसान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फसल बीमा पर लिए गए फैसलों का पक्ष लेते हुए कांग्रेस के दावे को सच से परे बताया है। इससे कांग्रेस की समझ की कमजोरी का भी पता चलता है। सरकार ने कहा है कि किए गए बदलाव से किसानों पर प्रीमियम का अतिरिक्त भार नहीं आएगा।

केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लांच की थी। उस समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम पड़े। योजना के तहत किसान खरीफ में बीमित राशि का दो फीसद, रबी में 1.5 फीसद, बागवानी और नकदी फसलों के लिए अधिकतम पांच फीसद देता है। प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारें 50:50 अनुपात में भुगतान करती हैं। कैबिनेट ने जिन प्रावधानों का अनुमोदन किया है उसमें भी किसानों के हिस्से में प्रीमियम की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कमलनाथ ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल

नईदुनिया, छिंदवाड़ा

- बोले, इंदिराजी ने कराया था 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण कराया था। इसे लेकर कोई नहीं बोलता। ये कहते हैं कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की। कौनसी सर्जिकल स्ट्राइक की? कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की? देश को कुछ तो बताइए इस बारे में।

अपने गृह नगर छिंदवाड़ा के ग्राम उमरहर में गुरुवार को गोशाला लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने दो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनकी पार्टी में से कोई ऐसा है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया हो। कमलनाथ ने देश में बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार और किसानों के कल्याण के संबंध में बात नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने सुना क्या कि मोदीजी ने पिछले छह माह में युवाओं के संबंध में बात की हो। किसान कल्याण की बात की हो।' उन्होंने कहा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। 'मोदी जी दो करोड़ तो छोड़िए, दो लाख लोगों का नाम बता दीजिए, जिन्हें आपने रोजगार दिया हो।'

कमलनाथ। फाइल

अब कमलनाथ बोल रहे इमरान की भाषा : विजयवर्गीय

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय के बेटे के विवाह समारोह में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार को मीडिया से चर्चा में विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता राहुल गांधी इमरान खान की बात बोलते थे। अब कमलनाथ को भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोलनी पड़ रही है, ये अफसोस की बात है।

सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कमलनाथ के बयान पर उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की वीरता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मैं कमलनाथ के बयान की निंदा करता हूं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, देश का

- भूपेश सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया

विभाजन हुआ तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी प्रशंसा में कविता भी लिखी। जो अच्छा काम कांग्रेस के नेताओं ने किया उसकी हमने प्रशंसा की है, आगे भी अच्छा काम करेंगे तो हम प्रशंसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार के लिए सोचती है, थोड़ा ब्रॉडमाइंड कांग्रेस का होना चाहिए। सीएम बघेल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी ये मुख्यमंत्री का हनीमून पीरियड है। हालांकि वर्षभर हो गए, उनसे अपेक्षाएं थीं कि कुछ परिणाम देंगे, लेकिन अभी तक के कार्यकाल के अनुसार बहुत ही असफल सरकार रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और जनसमस्याओं के प्रति गैर जिम्मेदार है।

सियासत के रंग

मांझी ने इसे चुनाव की मुनादी से जोड़ा, तो तेजस्वी ने पीएम को बिहार को मिलने वाले पैकेज याद दिलाए, सोशल मीडिया में तरह-तरह की चर्चा, किसी ने बिहार के गौरव से जोड़ा, तो किसी ने पीएम को दिया धन्यवाद

पीएम के लिट्टी-चोखा प्रेम पर बिहार में बनी सियासी 'चटनी'

जागरण टीम, पटना

नेताओं की हर अदा में राजनीति होती है। हुनर हाट के लिट्टी-चोखा भोजन ने फिर इस कथन को सही ठहराया है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिट्टी भोजन के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के बातों की 'चटनी' बन रही। प्लेट में दिखी मिर्च प्याज और चोखा पर चटखारे लिए जा रहे। दनादन पोस्ट, लाइक और कमेंट दागे जा रहे। इसमें बिहार के नेता भी पीछे नहीं हैं।

मोदी के लिट्टी भोजन की तस्वीर वायरल होने के बाद बिहार में सबसे पहले मोर्चा खोला पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव थोड़ी-बहुत सफलता के लिए गठबंधन बदलते रहे मांझी ने पूछा कि 'क्या लिट्टी-चोखा भोजन बिहार चुनाव की घोषणा मानी जाए?' उन्होंने बिहारी डिश पसंद करने के लिए पीएम का 'धन्यवाद' भी दिया। इसके बाद आया राजद नेता तेजस्वी का बयान। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद मशहूर बिहारी खाना पसंद करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री मांग नहीं सकते, इसलिए मैं आपका ध्यान बिहार के हिस्से के लिए जरूरी मुद्दों पर खींचना चाहता हूं- विशेष दर्जा, स्पेशल पैकेज के लिए फंड, बाढ़ राहत कोष और आयुष्मान भारत के लिए फंड।'

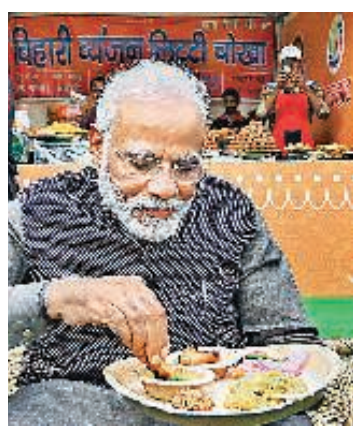

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर चल रहे हुनर हाट में पहुंचकर लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाया था। फाइल

विपक्ष के नेताओं के इन तंज के अलावा भी लिट्टी खूब चर्चा में है। मेहनती बिहारी मानुष की पहचान से जुड़ी लिट्टी के गुण गाए जा रहे। जदयू नेता संजय कुमार झा ने ट्वीट कर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि 'लिट्टी-चोखा बिहार के लाखों लोगों के लिए सादगी, विनम्रता और जमीन से जुड़े रहने का प्रतीक है। मोदी जी आपको इंडिया गेट के हुनर हाट में लिट्टी-चोखा का आनंद लेते देख बहुत अच्छा लगा। यह हमारी पाक-परंपरा का हिस्सा है और हमारा गौरव।'

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने लिट्टी-चोखा और अनरसा खाकर इस व्यंजन का ही नहीं, किसानों और मजदूरों का भी मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिट्टी-चोखा खाने पर बिहार में कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है।

चोखा को धोखा से जोड़ने पर ट्रोल हुए तेज प्रताप

लालू प्रसाद के बड़े बेटे और राजद विधायक तेजप्रताप लिट्टी चोखा को 'धोखा' से जोड़कर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। तेजप्रताप ने भोजपुरी में ट्वीट किया, 'कतनो खाइब लिट्टी-चोखा, बिहार ना भूली राउर धोखा।' ट्वीट आने के बाद कई लोगों ने तेज प्रताप से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। दरअसल, लोगों ने उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक प्रकरण को उठाना शुरू कर दिया। दरअसल शादी के छह महीने बाद ही तेजप्रताप ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी। एक यूजर ने भोजपुरी में ही पूछ लिया कि 'तोहार धोखा तो ऐश्वर्या भाभी भी नहीं भूलल होइहें।' (आपका धोखा तो ऐश्वर्या भी नहीं भूली होंगी।)

उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही जनता से लूटपाट : राजू भैया

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

- भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

योगी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ताकत झोंके हुए है, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही। पार्टी के नेता भी पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र व भाजपा के एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि पुलिस जनता से लूटपाट कर रही है। निर्दोष लोगों के साथ बदतमीजी करती है। अधिकारी कोई भी हो, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस बयान से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है।

राजवीर सिंह ने यह बयान बुधवार को अलीगढ़ के गांव गाजीपुर में हुई पंचायत के बाद दिया था। वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के योगेंद्र सिंह को फर्जी केस में जेल भेज दिया गया। तीन अन्य युवकों के खिलाफ भी लूट का केस दर्ज कर लिया गया। पंचायत में राजू भैया ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। मीडिया को दिए बयान में कहा कि गाजीपुर के ग्रामीणों के साथ पुलिस ने बदतमीजी की है। गलत केस में लोगों को फंसाया है। थाने में लोग जाते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, फिर पैसे लेकर छोड़ा जाता है। एक ग्रामीण का चालान भी विरोधी पार्टी से पैसे लेकर किया है।

साक्ष्यों के आधार पर लूट के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है। निष्पक्ष जांच की जा रही है। किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा।

-अतुल शर्मा, एसपी देहात

567 मिल मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बिहार के इन राइस मिल मालिकों पर राज्य के सरकारी खजाने को 450 करोड़ रुपये से ज्यादा के भुगतान में देरी का आरोप है।

ज्यादातर समय ट्रंप के साथ रहेंगे मोदी

मेहमाननवाजी ▶ करीब 36 घंटे तक अपनी पत्नी के साथ भारत में रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अगवानी से लेकर नई दिल्ली में विदाई तक रहेंगे साथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की व्यक्तिगत केमिस्ट्री विकसित की है वैसी मिसाल वैश्विक कूटनीति में फिलहाल देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाने पर नाराजगी जताने के साथ ही ट्रंप यह बताना नहीं भूलते कि वह मोदी को बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप की अगले हफ्ते की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान उन्हें हर कदम पर प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत मेहमाननवाजी देखने को मिलेगी। वह तकरीबन 36 घंटे भारत में रहेंगे और मोदी इसमें से अधिकांश समय उनके साथ होंगे।

सोमवार (24 फरवरी) को अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान 'एयरफोर्स वन' जब अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरेगा तो उनकी अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां रहेंगे। इसके बाद दोनों एक साथ अहमदाबाद स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे। अभी तक की जो तैयारी है उसके मुताबिक 22 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 45 मिनट में पूरी की जाएगी। बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की आगरा में भी अगवानी करें। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के आगरा जाने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक ट्रंप और मेलानिया को शाम 4.30 बजे आगरा पहुंचना है। वहां से वे 6.30 बजे में नई दिल्ली पहुंचेंगे। अगले दिन सुबह उनकी फिर 10.30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राजकीय सम्मान के दौरान मुलाकात होगी। उसके बाद देर शाम तक फिर दोनों नेता एक साथ ही रहेंगे। बीच में कुछ देर के लिए ट्रंप नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास जाएंगे जहां वह अपने दूतावास के कर्मचारियों से मिलेंगे।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेता तकरीबन तीन घंटे रहेंगे। इस दौरान उनके बीच दो चरणों में बातचीत होगी। पहले चरण में व्यक्तिगत बातचीत होगी। दूसरे चरण में आधिकारिक स्तर की बातचीत होगी। इसके बाद दोनों नेताओं के सामने समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे और संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस होगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्रंप के सम्मान में दिए गए आधिकारिक लंच में दोनों तरफ के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बहुत संभव है कि जिस तरह 2015 में ओबामा की अगवानी में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में उन्हें खुद चाय पेश की थी उसी तरह का एक संक्षिप्त आयोजन इस दौरे में भी किया जाए। सूत्रों के मुताबिक, बहुत कुछ अंतिम समय में तय होगा। इसके कुछ ही घंटे बाद फिर राष्ट्रपति भवन में भी मोदी ट्रंप के साथ होंगे।

ट्रंप की अगवानी के लिए तैयार किए जा रहे कार्यक्रम से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप के बीच पहले से बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री है। नई सरकार बनाने के बाद मोदी चार बार ट्रंप से मिल चुके हैं और अगले हफ्ते पांचवीं बार मिलेंगे। ट्रंप दो बार मोदी का वाशिंगटन में स्वागत कर चुके हैं। जबकि पिछले वर्ष ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पहुंच कर उन्होंने अपने सहयोगियों को भी अचंभित कर दिया था। जाहिर है कि मोदी को पहली बार ट्रंप के स्वागत का मौका मिल रहा है जिसे विशेष बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस यात्रा के बाद इनकी दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ होगी।

डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति कर रही आयोजन : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी में खर्च हो रहे पैसे पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है। हालांकि सरकार का कहना है कि अहमदाबाद में जो आयोजन हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति की तरफ से प्रायोजित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के आगमन पर जिस तरह का खर्च किया जाता है सरकार की तरफ से उतना ही खर्च किया जा रहा है। मोटेरा स्टेडियम या रोडशो के आयोजन की जिम्मेदारी अभिनंदन समिति की है।

दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने जाएंगी मेलेनिया ट्रंप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूल में 'हैप्पीनेस क्लास' में शामिल होंगी। अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया 25 फरवरी को दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की हैप्पीनेस क्लास में पहुंचेंगी। यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनका स्वागत करेंगे और उन्हें जानकारी देंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दो दिवसीय दौरा 24 फरवरी से अहमदाबाद से शुरू होगा। 25 फरवरी को ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जाने की इच्छा जताई है। करीब 45 मिनट से एक घंटे का समय वह बच्चों के बीच बिताएंगी और उनसे उनके अनुभवोंक को जानेंगी। इस दौरान उनका मूल मकसद दिल्ली सरकार के स्कूलों में चलने वाली हैप्पीनेस क्लास के बारे में जानने व समझने का रहेगा। वह देखेंगी कि हैप्पीनेस क्लास के सहारे बच्चों का तनाव कैसे कम किया जाता है। साथ ही बच्चे हंसते-खेलते हुए कैसे पढ़ाई भी कर लेते हैं। सुरक्षा कारणों से अभी दौरे के समय और संबंधित स्कूल की जानकारी नहीं दी गई है। दौरे के शेड्यूल में इसकी पूरी जानकारी होगी।

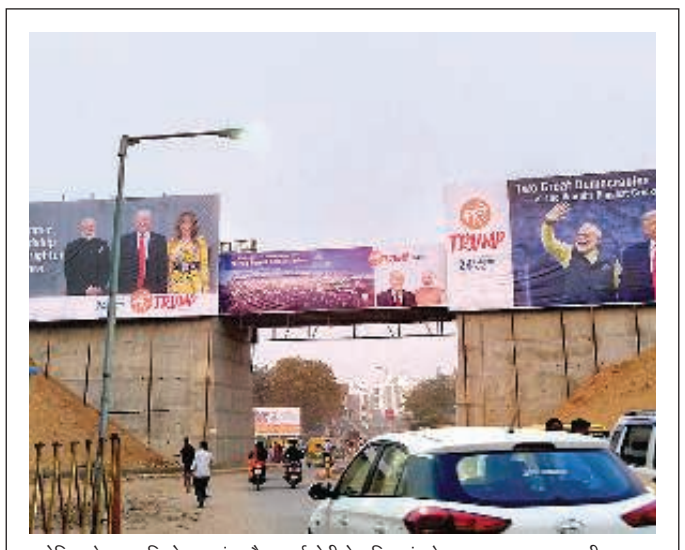

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के अहमदाबाद आगमन की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। शहर को पोस्टरों से पाट दिया गया है। जागरण

मोदी-ट्रंप के रोड शो में होंगे एक से दो लाख लोग

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को होने वाले 22 किमी लंबे रोडशो के दौरान सड़क के दोनों ओर एक से दो लाख लोग इकट्ठा होंगे। यह संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से काफी कम है जिन्होंने कहा था कि मोदी ने उनसे कहा है कि एयरपोर्ट से स्टेडियम के बीच 70 लाख लोग इकट्ठा होंगे।

अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) के आयुक्त विजय नेहरा ने बताया, 'रोडशो के दौरान गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए करीब एक से दो लाख लोग इकट्ठा होंगे।' उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद की कुल आबादी ही लगभग 70 लाख है।

इस बीच, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में मोदी-ट्रंप के रोडशो की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। हालांकि अभी तक यह फैसला भी नहीं हो पाया है कि रोड शो में मुख्यमंत्री का काफिला शामिल होगा अथवा नहीं।

विजय नेहरा ने बताया कि एएमसी ने रोडशो के दौरान प्रस्तुति देने के लिए देशभर से कलाकारों को आमंत्रित किया है। मार्ग पर निश्चित अंतराल पर हर राज्य के लिए एक अलग मंच होगा। इन 30 मंचों पर पारंपरिक परिधान पहने अलग-अलग राज्यों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। अन्य प्रस्तुतियों के लिए 20 और मंच भी बनाए जाएंगे। पूरे मार्ग को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है ताकि शहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके क्योंकि इस कार्यक्रम का दुनियाभर में सजीव प्रसारण किया जाएगा। पूरे रोडशो के दौरान दूरदर्शन 100 कैमरे स्थापित करेगा।

'नमस्ते ट्रंप' के लिए कई दिग्गजों को आमंत्रण : रोडशो के बाद अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में पिछले साल सितंबर में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम की तर्ज पर मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ट्रंप और मोदी दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, बिग बी अमिताभ बच्चन, अभिनेता अनिल कपूर, उनकी पुत्री अभिनेत्री सोनम कपूर, अभिनेत्री कंगना रनोट, अभिनेता विवेक ऑबेराय और खान तिकड़ी शाह रुख खान, सलमान खान और आमिर खान को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में कीर्तिदान गढवी लोकगायकी पेश करेंगे, वहीं संगीतकार एआर रहमान राष्ट्र गीत की धुन छेड़ेंगे।

ट्रंप भारत आने वाले सातवें अमेरिकी राष्ट्रपति

गुजरात में ट्रंप की यात्रा को लेकर भी जबर्दस्त खुशी का माहौल है। ट्रंप अमेरिका के ऐसे सातवें राष्ट्र प्रमुख होंगे जो भारत यात्रा पर आ रहे हैं। आजादी के बाद सबसे पहले 1959 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आईजन हॉवर ने भारत की यात्रा की थी।

तोहफा-ए-ताज ऐसा, व्हाइट हाउस भी करे नाज

राजीव शर्मा, आगरा

ताजमहल की दीवानगी में आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां की यादें तो भूल ही नहीं पाएंगे, मगर तोहफा-ए-ताज भी कम यादगार नहीं होगा। मंशा है कि ट्रंप को ऐसा तोहफा दिया जाए जो भारतीय कला और संस्कृति की याद दिलाता रहे। इसलिए मेहमान के लिए ताज का संगमरमरी मॉडल, टेबल लैंप और जरदोजी से तैयार मोर की कृति तलाशी गई है। इन तोहफों पर तो व्हाइट हाउस भी नाज करेगा। ताजमहल भ्रमण के बाद यादगार के लिए ट्रंप दंपती को उपहार भी भेंट किए जाएंगे।

विगत दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करने आगरा आए थे। तब सर्किट हाउस में अफसरों ने उनके समक्ष कुछ उपहार प्रस्तुत किए थे। इनमें संगमरमर से बना ताज का मॉडल, संगमरमर से बनी टेबल लैंप और जरदोजी कला से तैयार मोर का चित्र शामिल था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाएंगे शानदार उपहार

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इन उपहारों पर सहमति जताई है। अंतिम निर्णय अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की हरी झंडी मिलने के बाद ही लिया जाएगा। ट्रंप के स्वागत के लिए 24 फरवरी को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा आ सकते हैं। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ट्रंप की पत्नी को शॉल भेंट कर सकती हैं।

ताजमहल हो या फिर आगरा किला। हर जगह अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की आंख टिकी हुई है। अमेरिकी खुफिया विभाग की टीमों ने गुरुवार को ताजमहल, आगरा किला, मेहताब बाग आदि स्मारकों और संबंधित सड़कों पर करीब 45 मिनट जायजा लिया। टीम ने धूल उड़ने पर एतराज जताया। ताज के दीदार को आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति शाहजहां व मुमताज की असली कब्र देखने जाएंगे या नहीं, अभी तय नहीं है।

अहमदाबाद पहुंचा ट्रंप का आधिकारिक हेलीकॉप्टर

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

अमेरिकी हरक्यूलिस विमान के बाद अमेरिकी वायुसेना का एक और विमान अहमदाबाद पहुंचा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक हेलीकॉप्टर 'मेरीन वन' लाया गया है। संभावना है कि इसका इस्तेमाल ट्रंप मोटेरा स्टेडियम से अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए करेंगे। हरक्यूलिस विमान से अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कारें और सुरक्षा उपकरण लाए गए थे।

नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से पहले दोनों नेता एक ही कार में रोडशो करेंगे या अलग अलग यह अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी। दोनों नेता खुली कार में रोडशो करेंगे इसकी संभावना कम है।

इस बीच, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर अजय तोमर ने बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, चेतक कमांडो, गुजरात पुलिस, डीआरडीओ के अधिकारी और जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए अहमदाबाद पहुंचने लगे हैं। एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों की भी सुरक्षा जांच होगी और सीसीटीवी और विविध खुफिया एजेंसियां उनकी निगरानी करेंगी। सुरक्षा में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाएगी।

यात्रा कार्यक्रम में गांधी आश्रम का उल्लेख नहीं : ट्रंप और मोदी इस यात्रा के दौरान गांधी आश्रम नहीं जा रहे हैं। उनके कार्यक्रम में गांधी आश्रम का उल्लेख नहीं है। अजय तोमर ने बताया कि दोनों नेता अगर आश्रम जाते हैं तो उनकी ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं।

बसों से स्टेडियम पहुंचेंगे वीआइपी : वीआइपी भी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान और अन्य 24 पार्किंग स्थलों से बसों में सवार होकर मोटेरा स्टेडियम पहुंचेंगे। मोटेरा पर खास मेहमानों, वीवीआइपी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के वाहनों की ही पार्किंग हो सकेगी। गुजरात पुलिस ने रोडशो के मार्ग पर गुरुवार को रिहर्सल किया, वहीं रेपिड एक्शन फोर्स ने रोड के मार्ग पर मार्च किया।

गुजरात के सभी जिलों से भाजपा कार्यकर्ताओं, विशिष्टजनों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और कलाकारों को आमंत्रण दिया गया है। स्टेडियम आने वाले सभी मेहमानों को बार कोड वाले आमंत्रण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही हर जिले को अलग रंग आवंटित किया गया है। गांधीनगर को गुलाबी, अहमदाबाद को लाल, मेहसाणा बनासकांठा को आसमानी, वडोदरा को हरा रंग आवंटित किया गया है।

जनमत
मुद्दा

क्या भारत-अमेरिका के बीच परवान चढ़ते रिश्ते दुनिया के अन्य देशों की विदेश नीति से सामंजस्य साधने में चुनौती पेश करेंगे?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान बोले-15 करोड़ हैं 100 करोड़ पर भारी

बेंगलुरु, एएनआइ : सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लेमीन (एआइएमआइएम) के नेता वारिस पठान ने बेहद विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के गुलबर्ग में सीएए विरोधी एक जनसभा में वारिस पठान ने बिना नाम लिए कहा, 'हम 15 करोड़ (मुस्लिम) हैं, याद रख लेना, मगर 100 करोड़ (हिंदुओं) पर भारी पड़ेंगे।' उन्होंने कहा कि अगर आजादी दी नहीं जाती तो उसे छीनना पड़ेगा। पठान के इस बयान के बाद राजनीति गरम हो गई है। वारिस पठान ने जब यह बयान दिया तो वहां हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। इस बीच, पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में एक भाजपा कार्यकर्ता ने पठान वारिस के भड़काऊ भाषण के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है।

मुंबई के भयखला से चुनाव लड़ने वाले वारिस पठान ने गुरुवार को कहा, 'ईंट का जवाब पत्थर से देना हमने सीख लिया है। मगर इकट्ठा होकर चलना होगा। अगर आजादी दी नहीं जाती तो हमें छीनना पड़ेगा। वे कहते हैं कि हमने औरतों को आगे कर दिया है... अभी तो केवल शेरनियां बाहर निकली हैं तो तुम्हारे पसीने छूट गए। तुम समझ सकते हो कि अगर हम सब एक साथ आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ (मुस्लिम) हैं लेकिन 100 (करोड़ हिंदू) के ऊपर भारी हैं। ये याद रख लेना।'जनसभा को संबोधित करते हुए वारिस पठान ने कहा कि जामिया और शाहीन बाग में जो पिस्तौल लेकर चला गया वो किस की बात सुनकर चला गया और किस शाखा से आया था जवाब तो दे दो मुझे।इससे पहले पांच फरवरी को पठान ने स्वीकार किया था कि उन्होंने मुंबई के नागपाड़ा इलाके में शाहीन बाग की तरह से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। वारिस पठान के इस बयान के बाद राजनीति गरमा गई है।

कर्नाटक के गुलबर्गा में पठान ने दिया विवादित बयान

एआइएमआइएम नेता ने कहा-आजादी दी नहीं जाती तो उसे छीनना पड़ेगा

बेंगलुरु में गुरुवार को एआइएमआइएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीएए और एनआरसी के खिलाफ रैली में एक महिला ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। महिला का नाम अमूल्या था। एएनआइ

सभी से कुछ अच्छे और कुछ गलत निर्णय हो जाते

प्रथम पृष्ठ से आगे

साधना रामचंद्रन ने यहां तक कहा कि देश में अब तक कई प्रधानमंत्री आए हैं और कई चले गए हैं। सबसे कुछ अच्छे और कुछ गलत निर्णय हो जाते हैं। आप जो कह रहे हैं उसे पूरा देश सुन रहा है और प्रधानमंत्री भी आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद वार्ताकारों ने कहा कि हम अपने साथ दो लोगों को ले जाना चाहते हैं जो सड़कों को जानते हैं। और वह उनके साथ कब्जे वाली सड़क का मुआयना करने अपनी गाड़ी से गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि बातचीत का दौर शुक्रवार को भी जारी रहेगा।

..तो पूरे देश में गलत संदेश जाएगा : वार्ताकार संजय हेगड़े ने कहा कि कोर्ट ने अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो आपको भी हाथ बढ़ाना होगा। सड़क का मसला खत्म होने के बाद ही कानून पर सुनवाई करना आसान होगा। प्रदर्शन भी चले और सड़क भी चले तो शाहीन बाग असलियत में एक मिसाल बनेगा। अगर यहां कुछ गलत हो गया तो पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। इसलिए सोच-समझकर फैसला करें।

सीएए के खिलाफ 15 और याचिकाएं दायर, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर दायर ताजा याचिकाओं की बाबत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए नोटिस जारी किया है। ताजा याचिकाओं को इसी मामले की पूर्व में दायर 150 याचिकाओं के साथ शामिल कर भविष्य में सुनवाई की जाएगी।

सीएए को चुनौती देने वाली 15 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इनमें केरल नदवातुल मुजाहिदीन, अंजुमन ट्रस्ट और दक्षिण केरल जमीयतुल उलेमा की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार से इन याचिकाओं पर जवाब मांगा है। याचिकाओं पर अब मार्च में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी की है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को छह साल की भारत में रिहायश पर भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए की संवैधानिक वैधता पर 18 दिसंबर, 2019 को सुनवाई करने का फैसला किया लेकिन संशोधित कानून के लागू होने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। 22 जनवरी की सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार के लिए नोटिस जारी कर उससे चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

उपद्रव करने वाले 29 आरोपितों की जमानत रद

जासं, बिजनौर : उप्र के बिजनौर स्थित प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने के मामले में 29 आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शर्तों के साथ चार आरोपितों की जमानत मंजूर की है। 20 दिसंबर को सीएए के विरोध के नाम पर बिजनौर में बड़ा बवाल हुआ था।

एडीजीसी संजीव वर्मा के अनुसार एसआइ हरीश कुमार ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि 20 दिसंबर को चाहशीरी स्थित जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद भीड़ जमा थी, जो सीएए के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना बना रही थी। 250 उपद्रवियों की भीड़ ने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की, पेट्रोल की बोतलें फेंकी।

कांग्रेस के पास योग्य नेताओं की कमी नहीं

प्रथम पृष्ठ से आगे

दीक्षित ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि बाहर के चेहरे को नेतृत्व सौंपने के बाद गांधी परिवार के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। राहुल गांधी भविष्य में जब भी वापसी का फैसला करते हैं, तो इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि कांग्रेस में पुराने नेताओं की दोबारा ताजपोशी हुई है। दीक्षित ने दिल्ली में शीला दीक्षित और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हटने के बाद हुई वापसी का उदाहरण भी दिया।

नए नेतृत्व को लेकर दीक्षित और थरूर की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे उनकी निजी राय बताया। साथ ही दीक्षित को नसीहत देते हुए कहा कि शीला के कार्यकाल में जितना काम उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ, अगर अपनी ताकत वे वहां लगा देंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। इसीलिए दीक्षित समेत सभी नेताओं से अनुरोध है कि पूरे देश को ज्ञान देने से पहले अपने-अपने क्षेत्रों में काम का फायदा उठाएं। थरूर की टिप्पणी पर सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति ने ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया था और किसी को भ्रम है तो बयान देने से पहले कार्यसमिति का प्रस्ताव पढ़ ले।

आदेश

विभिन्न जोन से अनुबंध कर्मियों को पीएफ, ईएसआइ लाभ सुनिश्चित करने को कहा, रेलवे में ठेका कर्मियों की बदहाली पर कैग पहले ही जता चुका है एतराज

लोकलेखा समिति की जांच की आंच से रेलवे के हाथ-पांव फूले

संजय सिंह, नई दिल्ली

रेलवे के विभिन्न विभागों में अनुबंधित कर्मचारियों के शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कैग की फटकार के बाद संसद की लोकलेखा समिति के बुलावे से घबराए रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन तथा उत्पादन इकाइयों से श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। रेलवे ने ठेका श्रमिकों को दुर्दशा से उबारने को भी कहा है। लगभग 13 लाख स्थायी कर्मचारियों के वेतन बिल से परेशान भारतीय रेलवे में इस समय लगभग 95 हजार कर्मचारी अनुबंध या ठेके पर कार्यरत हैं।

रेलवे बोर्ड ने कैग की 2018 की रिपोर्ट (संख्या 19) के साथ लोकलेखा समिति की ओर से इस मसले को जांच के लिए चुने जाने का हवाला देते हुए विभिन्न जोन से तैयारियों के साथ पूरी तरह चाकचौबंद रहने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि सभी जोन तथा उत्पादन इकाइयां अपने यहां मौजूद अनुबंधित कर्मचारियों के साथ उनकी आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के सारे रिकॉर्ड तत्काल चेक कर अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि उनके विभिन्न विभागों, इकाइयों में ठेका कर्मचारियों को कानून सम्मत लाभ प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं।

विभागों से यह पक्का करने को भी कहा गया है कि सभी ठेकेदारों ने अनुबंध कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआइ खाते खुलवा लिए हैं तथा इन खातों में कर्मचारियों के साथ खुद का नियमित योगदान कर रहे हैं। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ठेकेदारों द्वारा अनुबंध श्रमिकों को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। जो ठेकेदार कानूनी प्रावधानों को ठेंगा दिखा रहे हैं उन्हें अनुपालन के लिए बाध्य किया जाए। न मानने पर पेनाल्टी लगाई जाए अथवा भुगतान रोक दिया जाए या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।

रेलवे बोर्ड ने जोनल अधिकारियों से भविष्य में ठेका कर्मियों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध तथा चयनित की जाने वाली फर्मों के लिए जारी किए जाने वाले टेंडर डाक्यूमेंट में भी संशोधन करने तथा उनमें श्रम कानूनों के अनुपालन की सामान्य व विशिष्ट दशाओं का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा है।

कैग ने पकड़ी थीं कई खामियां : गौरतलब है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में रेलवे के नौ जोन में अनुबंध कर्मियों के शोषण व अन्याय के अनेक मामले पकड़े थे। कैग ने पाया था कि 323 विभागों ने श्रम विभाग में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। जिन विभागों ने कराया है उनमें से 380 विभागों ने रिटर्न नहीं दाखिल किया है। रेलवे कैग को 285 ठेकेदारों के रिटर्न के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करा पाया।

रेलवे नहीं दे पाया पर्याप्त रिकॉर्ड : इतना ही नहीं, ऑडिट में रेलवे के 100 विभाग ठेका कर्मियों के लिए पीने के पानी, शौचालय आदि की बुनियादी सुविधाओं का ब्योरा तक नहीं उपलब्ध करा सके थे। कैग ने 172 कांट्रैक्टर को बिना लाइसेंस के काम करते पाया था। रेलवे ने जिन 207 कांट्रैक्टर के पास लाइसेंस होने का दावा किया गया था उनका रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक वेतन भुगतान में नियमों की अनदेखी की गई।

ईएसआइ व पीएफ में भी गड़बड़ी

इसी तरह 103 अनुबंधों में कर्मचारियों की पीएफ कटौती नहीं की गई थी। ईएसआइ का योगदान लेने व जमा करने में गड़बड़ी मिली। 12 अनुबंधों में कर्मचारियों से ईएसआइ में अधूरा तथा 80 अनुबंधों में कोई भी योगदान नहीं लिया गया। 10 अनुबंधों में योगदान अधूरा और 88 में बिलकुल जमा नहीं कराया गया। इसके अलावा 335 अनुबंधों में कैग को योगदान लेने, जमा कराने का कोई ब्योरा ही नहीं मिला। किस अनुबंध के तहत कितने कर्मचारी काम पर लगाए जाने हैं या लगाए गए इसका सही ब्योरा भी जोन नहीं दिखा पाए। 140 अनुबंधों में जरूरी कर्मचारियों का कोई आकलन नहीं किया गया, जबकि 133 अनुबंधों में कर्मचारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

लखनऊ में 29 और उपद्रवियों पर कसा प्रशासन का शिकंजा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में लखनऊ में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ने लगी है। हसनगंज और परिवर्तन चौक मामले में रिकवरी आदेश के बाद अब दो अन्य थाना क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई के लिए 29 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। इन्हें 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। इस पर सुनवाई के बाद रिकवरी का आदेश जारी होगा।

19 दिसंबर को सीएए कानून के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और उपद्रव हुआ था। उपद्रव में करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति खाक कर दी गई थी। हिंसा में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में करीब 150 लोगों को नोटिस जारी हुए थे। अपर जिला मजिस्ट्रेट ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र के मुताबिक कैसरबाग में 15 और ठाकुरगंज में 14 उपद्रवियों को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। इनमें से कैसरबाग में छह और ठाकुरगंज में आठ के जवाब दाखिल किए गए हैं। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी, जिसमें जवाब की समीक्षा की जाएगी। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर रिकवरी की जाएगी।

इससे पहले राजधानी में करीब एक करोड़ रुपये के नुकसान की वसूली के लिए प्रशासन की ओर से दो नोटिस जारी की जा चुकी हैं। हसनगंज क्षेत्र में हुए करीब 21 लाख के नुकसान के लिए 13 लोगों के खिलाफ और हजरतगंज क्षेत्र के बवाल में 69.70 लाख रुपये की भरपाई के लिए 24 के खिलाफ आदेश जारी किया गया है। उधर, उपद्रव करने के आरोप में घिरे पूर्व आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ अदालत जाने की बात कही है।

853 वार्डरों और 28 मैटर्न के पदों पर भर्ती की पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा जेल विभाग के लिए 37 नए वाहन खरीदने को हरी झंडी मिल गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 फरवरी 2020

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए भी बनेगा ट्रस्ट

तैयारी ▶ सुन्नी वक्फ बोर्ड 24 की बैठक में कर सकता है एलान

इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखा जा सकता है नाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर मस्जिद निर्माण के लिए भी ट्रस्ट का गठन करने की तैयारी है। यह ट्रस्ट मस्जिद निर्माण के साथ ही वहां शैक्षिक व सामाजिक गतिविधियां संचालित करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड 24 फरवरी को होने वाली बैठक में इस ट्रस्ट का एलान कर सकता है। इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ भूमि दी जा रही है। इस भूमि पर मस्जिद बनाने के अलावा और क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर फैसला 24 फरवरी की बैठक में होगा। इस बैठक में ट्रस्ट के एलान के साथ ही सदस्यों के नामों की भी घोषणा हो सकती है। ट्रस्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने के साथ ही मस्जिद मामले में मध्यस्थता करने वालों को भी शामिल किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हो सकते हैं।

अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर मिली पांच एकड़ भूमि पर अस्पताल, विद्यालय, इस्लामिक कल्चरल गतिविधियां बढ़ाने वाले संस्थान और लाइब्रेरी बनाने के साथ ही सामाजिक गतिविधियां बढ़ाने वाले कार्यक्रम संचालित होंगे। इस फाउंडेशन के जरिए सुन्नी वक्फ बोर्ड हिंदू व मुस्लिमों के बीच सामंजस्य बनाने के कार्यक्रम भी चलाएगा।

बोर्ड को मिला प्रस्ताव : सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बताया कि 24 फरवरी की बैठक में अयोध्या से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड के पास अयोध्या में ट्रस्ट गठन का सुझाव आया है, जिस पर अंतिम फैसला बैठक में होगा।

जल्द शुरू होगा श्रीराम मंदिर निर्माण : नृत्य गोपाल दास

जासं, नई दिल्ली : श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण की देशवासियों की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले तीन साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा।

महंत नृत्य गोपाल दास गुरुवार को रामलीला मैदान के नजदीक स्थित मंदिर श्रीराम हनुमान वाटिका पहुंचे थे। यहां महंत श्रीरामकृष्णदास महात्यागी (मचान वाले बाबा) की अगुआई में अनेक साधु-संतों, नेताओं व श्रद्धालुओं ने उनका अभिनंदन किया। महंत श्रीरामकृष्णदास महात्यागी ने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास वर्षों से मंदिर का निर्माण कराने का प्रयास कर रहे थे। आखिर उनका संघर्ष रंग ले आया है। उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने पर ट्रस्ट के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

खत्म होगा शिलाओं का 30 साल पुराना इंतजार

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

▶ रामजन्मभूमि न्यास के मॉडल के अनुरूप मंदिर निर्माण के आसार प्रबल

▶ एक लाख घन फीट पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो चुका है

रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व महासचिव बन गए हैं, तो यह भी तय माना जा रहा है कि 30 वर्ष पुराने राममंदिर के न्यास के मॉडल के अनुसार ही मंदिर का निर्माण होगा और न्यास कार्यशाला में तराशी जा रहीं शिलाएं उसका हिस्सा बनेंगी। इससे लोगों में खासा उत्साह है।

1990 में स्थापित न्यास की कार्यशाला में करीब एक लाख घन फीट पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो चुका है। दो मंजिला मंदिर के लिए अभी करीब 75 हजार घन फीट पत्थर और तराशे जाने हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इन शिलाओं के समक्ष मत्था टेकना नहीं भूलते।

रामजन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा एवं 128 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की प्रथम पीठिका आठ फीट ऊंची होगी। इस तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा। इसी पीठिका पर मंदिर का 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। चार फीट नौ इंच ऊंची एक आधार पीठ पर मंदिर का निर्माण होना है। अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्यमंडप, रंगमंडप और गर्भगृह के रूप में मंदिर के मुख्यतया पांच प्रखंड होंगे। मंदिर दो मंजिल का होगा। प्रथम मंजिल की ऊंचाई 18 फीट एवं दूसरी मंजिल की ऊंचाई 15 फीट नौ इंच होगी। मंदिर में 212 स्तंभ लगेंगे। प्रथम मंजिल में 106 स्तंभ एवं इतने ही दूसरी मंजिल पर लगेंगे।

अयोध्या के श्रीरामजन्मभूमि न्यास कार्यशाला में तराशी गईं शिलाएं। जागरण

प्रथम मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 16 फीट तीन इंच एवं दूसरी मंजिल पर लगने वाले स्तंभों की ऊंचाई 15 फीट नौ इंच होगी। प्रत्येक स्तंभ पर यक्ष-यक्षिणियों की 16 मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनका व्यास चार से पांच फीट तक है। जिस कक्ष में रामलला विराजेंगे, उस गर्भगृह से ठीक ऊपर 16 फीट तीन इंच का विशेष प्रकोष्ठ और इसी प्रकोष्ठ पर 65 फीट तीन इंच ऊंचा शिखर निर्मित होगा। प्रस्तावित मंदिर में एक लाख 75 हजार घन फीट लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होना है।

1991 से संचालित कार्यशाला में 28 वर्षों के दौरान एक लाख घन फीट से अधिक पत्थर तराशे जा चुके हैं। इनमें प्रथम तल में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों का काम पूरा हो गया है, जबकि दूसरे तल के पत्थर भी आंशिक तौर पर तराशे जा चुके हैं।

ट्रस्ट में दिखेगी पीएम की सोच

प्रथम पृष्ठ से आगे

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही नृपेंद्र मिश्रा ने काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कुछ सदस्यों के साथ उन्होंने अनौपचारिक बैठक की और जल्द ही निर्माण को लेकर व्यापक बैठक का मन बनाया है। यह तय है कि समय सीमा के अंदर ही कार्य संपन्न किया जाएगा।

दरअसल मिश्रा का चयन ही बहुत कुछ कहता है। जाहिर तौर पर एक प्रशासक के रूप में मिश्रा का अनुभव बहुत लंबा है लेकिन उससे भी खास यह है कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा है। उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वह निजी सचिव थे और बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के काल में वह प्रमुख सचिव थे। मुलायम के काल में जब राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश हुआ था तो उन्होंने इससे असहमति जताई थी। यही कारण है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड में कुछ नकारात्मक टिप्पणी भी की गई थी। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे देखा जाए तो उनकी मौजूदगी पीएम नरेंद्र मोदी की सोच को जमीन पर उतारेगी। ध्यान रहे कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें पीएमओ में प्रमुख सचिव बनाया गया था।

न्यूज गैलरी

नरसिंहानंद ने कहा-ज्यादा बच्चे पैदा करें हिंदू

मुजफ्फरनगर : अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि बढ़ता जातीय वैमनस्य और घटता जनसंख्या अनुपात हिंदुओं के विनाश का कारण बनेगा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदुओं को चार-पांच बच्चे पैदा करने होंगे। उप्र के मुजफ्फरनगर में गुरुवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ऐसे ही चलता रहा है तो कम समय में ही भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जिससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग प्रकरण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस, भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हिंदुओं को अपनी रक्षा और अस्तित्व बचाने की खातिर जातीय भेदभाव भी खत्म करना होगा। जाति-बिरादरी में बंटने से देश टूट रहा है। बताया कि हिंदुओं की रक्षा के लिए मुजफ्फरनगर में अप्रैल माह में नौ दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ होगा। यज्ञ में आहुति देकर शत्रुओं के विनाश की कामना की जाएगी। (जासं)

बिहार में दो नक्सलियों की 26 लाख की संपत्ति जब्त

पटना : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बिहार में दो नक्सली कमांडरों की करीब 26 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। इन दोनों कमांडरों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा था। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार नक्सली कमांडर पिंटू राणा और अभिजीत यादव विशेषकर जमुई और इसके आसपास के इलाके में सक्रिय थे। इन दोनों नक्सलियों ने लोगों को डरा-धमका कर और नक्सली गतिविधियों के जरिए लाखों रुपये की चल-अचल संपत्ति बना ली थी। इन दोनों द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जन की जानकारी मिलने के बाद ईओयू ने इनके खिलाफ जांच की। ईडी सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान जानकारी मिली कि नक्सली पिंटू राणा ने करीब 16.49 करोड़ और अभिजीत यादव ने 9.57 लाख रुपये की अचल संपत्ति बना रखी है। पिंटू राणा के खिलाफ 76 और अभिजीत यादव पर करीब 55 मामले चल रहे हैं। महीनों तक दोनों पर नजर रखने के बाद ईओयू ने इन दोनों नक्सली कमांडरों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने इसके पूर्व नक्सली संदीप यादव और प्रद्युमन शर्मा की भी संपत्ति जब्त की थी। (राब्यू)

नए सियासी मंच की तैयारी में अल्ताफ बुखारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ अगले दो-तीन दिन में अपने संगठन का कर सकते एलान, पुराने साथियों संग मंथन जारी

▶ मुजफ्फर हुसैन बेग से मुलाकात के बाद सियासी अटकल तेज

जम्मू-कश्मीर में नया सियासी मंच तैयार करने में जुटे पूर्व वित्तमंत्री अल्ताफ बुखारी परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर अगले दो-तीन दिन में अपने संगठन का एलान कर सकते हैं। इस बीच, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग से उनकी मुलाकात ने भी नई सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है। बुखारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वह कहते हैं कि आप बस इंतजार करिए, जो होगा जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में ही होगा।

बुखारी को पीडीपी के ताकतवर नेताओं में गिना जाता रहा है। बुखारी के करीबियों ने बताया कि वह इस समय अपने साथियों और समर्थकों के साथ नए राजनीतिक मंच को लेकर गहन विचार विमर्श की प्रक्रिया मे हैं। कई पुराने नेता चाहते हैं कि वह नया मंच बनाने से पूर्व पीडीपी को दोबारा खड़ा करने के विकल्प पर विचार करें। अगर वह चाहें तो पीडीपी के नेताओं की बैठक बुलाकर नए पदाधिकारियों को चुना जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस विकल्प से कथित तौर पर इन्कार किया है।

बेग का साथ चाहते हैं बुखारी : सूत्रों ने बताया कि बुखारी ने पीडीपी के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन से भी गत दिनों एक मुलाकात की है। बेग बीते कुछ महीनों के दौरान कई बार महबूबा की नीतियों की आलोचना करते हुए जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बुखारी चाहते हैं कि बेग उनका साथ दें। बेग का साथ मिलने पर महबूबा अकेली पड़ जाएंगी। एक तरह से पीडीपी के लगभग सभी पुराने नेता और कैडर बुखारी के साथ चला जाएगा। बेग का जवाब गुरुवार शाम तक नहीं मिला था। बुखारी उनके जवाब के बाद ही अपना अगला सियासी कदम उठाने के मूड में हैं।

अल्ताफ बुखारी। फाइल

महबूबा ने निष्कासित कर दिया था : जून 2018 में जब पीडीपी-कांग्रेस-नेकां के गठजोड़ की सरकार बनाने की कवायद हुई तो उन्हें ही पीडीपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया था। वहीं, पिछले साल पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अपने निष्कासन पर बुखारी ने कहा था कि अब मैं आजाद हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए खुलकर काम कर सकता हूं।

सियासी आवाजें मंद पड़ीं : जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी सरीखे क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक गतिविधियों को सीमित कर लिया है। इन दलों का राजनीतिक एजेंडा मौजूदा परिस्थितियों में पूरी तरह आप्रसंगिक हो चुका है। इससे जम्मू-कश्मीर में एक तरह का राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। आम लोगों को पेश आने वाली दिक्कतों को उठाने वाली सियासी आवाजें मंद पड़ गई थी। ऐसे हालात में बुखारी राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। उन्होंने पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के कई पुराने नेताओं और पूर्व विधायकों को साथ जोड़ राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास शुरू किया। बुखारी के साथ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर के अलावा पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासीन भी हैं। बुखारी के नेतृत्व में पीडीपी के आठ वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों ने बीते माह उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी। ये लोग कश्मीर दौरे पर आए विदेशी राजनयिकों से भी मिले थे।

देविंदर और आतंकी साथियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी

राज्य ब्यूरो, जम्मू : एनआइए की विशेष अदालत ने गुरुवार को फिर निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह और उनके आतंकी साथियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 15 दिन और बढ़ा दी है। अलबत्ता, अदालत में सिर्फ देविंदर को पेश किया। डीएसपी संग पकड़े गए आतंकी व उसके अन्य साथियों ने कोट भलवाल जेल से वीडियो कांफ्रेंस से अदालत में उपस्थिति दर्ज कराते हुए सुनवाई में हिस्सा लिया।

एनआइए ने देविंदर सिंह को अदालत में पेश किया। उसे हीरानगर जेल से लाया था। हिजबुल कमांडर नवीद मुश्ताक, आरिफ, इरफान और सईद इरफान ने सेंट्रल जेल कोट भलवाल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लिया। एनआइए विशेष अदालत के जज एससी गुप्ता ने एनआइए के मुख्य जांच अधिकारी द्वारा अदालत मे पेश किए तथ्यों व दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है। आरोपितों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने का एनआइए का आग्रह तर्कसंगत और न्यायोचित है। सभी को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इसके साथ जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी आरोपितों का रिमांड की अवधि के दौरान स्वास्थ्य जांच कराए।

पाक के गोलों और बर्फबारी पर भारी क्रिकेट का जुनून

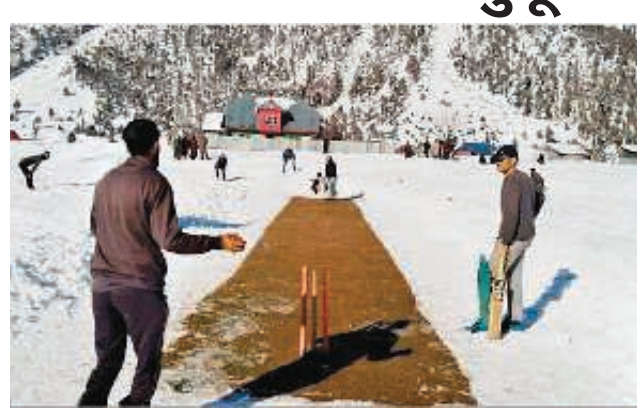

नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज सेक्टर में बर्फ के मैदान पर युवा क्रिकेट मैच खेलते हुए। सौजन्य ट्विटर

नवीन नवाज, श्रीनगर

गुरेज सेक्टर भारत-पाक नियंत्रण रेखा से सटा क्षेत्र। यहां कभी भी पाक सेना तोपों से गोले बरसाने शुरू कर देती है। तापमान भी शून्य के लगभग। ऐसे हालात में खेल तो दूर, घर से बाहर निकलने के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता, लेकिन गुरेज के नौजवानों की जीवटता और क्रिकेट के प्रति जुनून कुछ और ही बयां करता है। विकास की दौड़ में पिछड़े गुरेज के युवाओं ने अपने क्षेत्र में विंटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने जुनून को सहारा बनाते हुए स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया। गुरेज के मरकूट गांव के मैदान के बीच खेल गए टूर्नामेंट को देखने के लिए रोजाना 250 से 300 दर्शकों की भीड़ जुटती रही है। बर्फ से ढके मैदान में सिर्फ पिच पर बर्फ नहीं थी। प्रतियोगित का अंतिम और फाइनल मुकाबला फुजी एकादश और ड्रीम एकादश के बीच खेला गया। ड्रीम एकादश ने मैच जीता। मैच के दौरान जब कोई विकेट गिरती या बल्लेबाज चौका-छक्का जड़ने शॉट लगाता तो मैदान में गूंजने वाली तालियों की आवाज एलओसी पर सामने बंकरों में बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के कानों में गूंजती। यह इलाका घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है।

राजा अली नामक स्थानीय युवक ने कहा कि स्नो क्रिकेट पूरे गुरेज सेक्टर में लोकप्रिय है। कुछ वर्षों के दौरान स्थानीय लड़कों ने इसकी शुरुआत की है। इसके सभी नियम क्रिकेट के ही है सिर्फ मैदान में बर्फ होने के कारण हमने इस स्नो क्रिकेट का नाम दिया है। यह प्रतियोगिता सर्दियों में तभी करवाई जाती है जब मैदान में तीन से चार फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो और मौसम साफ हो। इसे देखने अब दूसरे इलाकों से लोग आने लगे हैं।

अगर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन हो सकता है तो फिर गुरेज में क्यों नहीं? गुरेज भी प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है। यहां एडवेंचर स्पोर्ट की संभावना है। गुरेज की मशहूर चोटी हब्बा खातून की तलहट्टी में आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय लोग अपने स्तर पर करते हैं। स्थानीयवासी मुहम्मद यूसुफ खान ने कहा कि हमारा इलाका सर्दियों में चार से छह माह तक जिला मुख्यालय बांडीपोर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से कटा रहता है। क्रिकेट यहां लोकप्रिय है। दो-तीन साल पहले हम लोगों ने कहा कि सर्दियों में यहां कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे गुरेज सेक्टर के सभी लोग सम्मिलित हों, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिले। उस समय स्नो क्रिकेट का विचार हमारे मन में आया। अब आने वाले दिनों में हम यहां स्नो हॉकी, स्नो सॉकर और स्नो रग्बी जैसे खेल करने के बारे में सोच रहे हैं।

गुरेज में तैनात सैन्य अधिकारियों ने कहा कि हम अपने संसाधनों से स्थानीय लोगों को इस प्रतियोगिता में आवश्यकतानुरूप मदद करते हैं। गुलाम कश्मीर में बैठे पाक सैनिकों द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं पर उक्त अधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोगों के क्रिकेट के प्रति जुनून के आगे वह भी नतमस्तक हैं।

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले कैसे बन गए मालिक

जेएनएफ, जम्मू

▶ हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट पर उठाए गंभीर सवाल, राजस्व विभाग को हलफनामा दायर करने के निर्देश

▶ रोशनी एक्ट के लाभार्थियों की सूची हाई कोर्ट में पेश

▶ जम्मू में 25 हजार व कश्मीर में 4500 लोगों को लाभ दिया गया

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोशनी एक्ट के नाम से प्रख्यात जम्मू-कश्मीर लैंड एक्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। बेंच ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में यह किस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। बेंच ने कहा कि क्या केंद्र या देश के किसी अन्य राज्य में ऐसा कोई कानून है, जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना अधिकार दिए जाते हों? अगर देश के किसी हिस्से में ऐसा है, तो उस कानून की कापी बेंच के सामने पेश की जाए।

हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस ताशी रबस्तान ने गुरुवार को रोशनी एक्ट को चुनौती देने वाली एडवोकेट अंकुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की। बेंच के पूर्व निर्देशानुसार सरकार की ओर से एक्ट का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की सूची बेंच के सामने पेश की गई। इसमें बताया गया कि जम्मू संभाग में एक्ट के तहत 25 हजार व कश्मीर में 4500 लोगों को लाभ दिया गया, जबकि लद्दाख में रोशनी एक्ट का कोई लाभार्थी नहीं था। बेंच ने इस पर हैरानगी प्रकट करते हुए कहा कि क्या आज तक इस सरकारी जमीन की कीमत का आकलन किया गया? बेंच ने राजस्व विभाग को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के सचिव या उससे उच्च पद का कोई अधिकारी यह हलफनामा दे कि जो सूची बेंच के सामने पेश की गई है, वो सही व हर लिहाज से पूर्ण है। बेंच ने कहा कि यह बताया जाए कि जो सरकारी जमीन बेची गई, उसमें से शहरी इलाके में कितनी थी, ग्रामीण इलाकों में कितनी और वन विभाग की कितनी जमीन थी।

सुंजवां व चुआदी मामले पर भी लिया संज्ञान, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश : डिवीजन बेंच ने पाया कि हाल ही में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने सुंजवां व चुआदी क्षेत्र में 5000 कनाल सरकारी जमीन के राजस्व रिकार्ड में गलत एंट्रियों को खारिज किया है और ऐसे मामलों की जांच जारी है। बेंच ने जम्मू की डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि ऐसी सभी अवैध एंट्रियों की निशानदेही करके उन्हें खारिज किया जाए और इसके लिए जो भी सरकारी अधिकारी और लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

राजनेताओं व अधिकारियों की बेंच का देंगे जानकारी : मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा कि रोशनी एक्ट के लाभार्थियों में कई राजनेता व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं और वह अगली सुनवाई के दौरान उनकी जानकारी बेंच के सामने पेश करेंगे। शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मामले की सीबीआइ जांच करवाने की मांग इसलिए की थी क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि रोशनी एक्ट के तहत 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। बेंच ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेंच ने अंकुर शर्मा को यह रिपोर्ट अगली सुनवाई को पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसपर बहस की जाएगी।

क्या था रोशनी एक्ट

नेशनल कांफ्रेंस की सरकार ने 2001 में रोशनी एक्ट बनाया था। इसके अनुसार, 1999 से पहले कब्जे वाली सरकारी जमीन के पैसे लेकर मालिकाना हक देने की बात कही गई। इससे जमा धनराशि को बिजली सेक्टर के प्रोजेक्ट में लगाने की बात कही थी।

पहल

गृह मंत्रालय ने दिए क्षेत्रीय सिनेमा की स्थापना और संस्कृति नीति बनाने के निर्देश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्षेत्रीय सिनेमा की मांग

जम्मू-कश्मीर में फिरने वाले हैं क्षेत्रीय सिनेमा के दिन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय सिनेमा के दिन फिरने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को क्षेत्रीय सिनेमा की स्थापना और संस्कृति नीति बनाने के लिए यथोचित कदम उठाने के लिए कहा है। कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी और गोजरी भाषा में स्थानीय कलाकारों व फिल्मकारों द्वारा फिल्में बनाई जाती हैं। इनमें अधिकांश छोटे पर्दे के लिए होती हैं। बड़े पर्दे के लिए डोगरी और पहाड़ी भाषा में फिल्में बन चुकी हैं। सबसे ज्यादा फिल्में डोगरी भाषा में बनती हैं।

भारतीय कला संगम के अध्यक्ष और कलाकार रमेश चिब ने गृह मंत्रालय के जारी निर्देश पर कहा कि हमने याचिका दायर का क्षेत्रीय सिनेमा और संस्कृति नीति के गठन का आग्रह किया था। हमने याचिका 23 फरवरी 2019 को दायर की थी। लगभग एक साल बाद हमें गृह मंत्रालय का जवाब प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय ने चार फरवरी 2020 को कला संस्कृति सचिव को उचित कार्रवाई के लिए कहा है।

भारतीय कला संगम बीते कई वर्षों से विभिन्न समाजसेवी संगठनों और कलाकारों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सिनेमा व संस्कृति नीति के लिए विभिन्न विभागों, केंद्र सरकार और पुनर्गठन से पहले के जम्मू-कश्मीर में सत्तासीन रही सरकारों के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है। गृह मंत्रालय के निर्देश से हमारा संघर्ष रंग लाता नजर आ रहा है। चिब ने कहा कि हमने याचिका में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय सिनेमा की मांग की है जिस भी राज्य में क्षेत्रीय सिनेमा है वहां संबंधित राज्य सरकार स्थानीय भाषाई सिनेमा और थियेटर व संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय मदद व सब्सिडी प्रदान करती है। हम बरसों से यहां सिनेमा और संस्कृति नीति की मांग करते आए हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जम्मू-कश्मीर विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृतियों वाला प्रदेश है। जम्मू-कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन संस्कृति नीति के अभाव में स्थानीय सांस्कृतिक संगठन, फिल्म निर्माता निर्देशक, कलाकार, लेखक कभी आगे नहीं बढ़ पाए। इसका नुकसान हमारी संस्कृति के संरक्षण और विकास कार्यों को भी पहुंचा है।

कुछ गिनी चुनी फिल्में ही सिनेमाघरों में पहुंचती हैं

वरिष्ठ कलाकार सुधीर जम्वाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हर साल करीब 150 छोटी बड़ी फिल्में बनती हैं। इनमें से कुछ गिनी चुनी ही सिनेमाघरों में पहुंच पाती हैं, शेष अन्य प्लेटफार्म पर रिलीज होती हैं। क्षेत्रीय सिनेमा और संस्कृति नीति के बनने से यहां हर भाषा के कलाकार को लाभ होगा। यहां पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरह स्थानीय सिनेमा उभरेगा। सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बड़ी बात यह कि लोक कला, भाषा और संस्कृति का संरक्षण और विकास भी होगा। यहां बहुत से काबिल कलाकार, फिल्म निर्माता व लेखक वित्तीय मदद न होने के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सिनेमा व संस्कृति नीति होने पर सब्सिडी मिलेगी, फिल्मों पर टैक्स माफ भी होगा। कश्मीर में हमारे बहुत से साथियों ने भी इस दिशा में बड़ी मेहनत की। हमारे एक साथी रमेश चिब ने तो बाकायदा अभियान चला रखा है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पांच अगस्त 2019 से पहले के जम्मू-कश्मीर में जो भी वर्ग सत्ता में रहा है, उसने एक कारण विशेष के तहत स्थानीय सिनेमा और संस्कृति के प्रचार प्रसार को अहमियत नहीं दी है।

पर्यटन से उम्मीदें लगाए लद्दाख में विंटर कार्निवाल आज से

राज्य ब्यूरो, जम्मू

वर्ष 2020 में पर्यटन क्षेत्र में कायाकल्प की उम्मीदें लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुक्रवार से विंटर कार्निवाल शुरू हो रहा है। इसमें देश-विदेश के पर्यटकों को बर्फीले रेगिस्तान आने का संदेश दिया जाएगा।

तीन दिवसीय कार्निवल लद्दाख के लेह मुख्यालय में शुरू होगा। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनते ही क्षेत्र के पर्यटन संगठनों ने विश्व के पर्यटकों को संदेश देना शुरू कर दिया था लद्दाख में पर्यटकों का आना पूरी तरह सुरक्षित है। अब विंटर कार्निवाल में लद्दाख में विंटर टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के पर्यटन उद्योग, फिल्म जगत से जुड़े लोगों, संगठनों को बुलाया गया है। यह कार्यक्रम 23 फरवरी तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाएगा कि लद्दाख में पर्यटन की कितनी क्षमता है।

लद्दाख में बड़े पैमाने पर निवेश की भी उम्मीद : लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल के चीफ एक्जीक्यूटिव काउंसिलर ग्याल पी वांग्याल का कहना है कि लद्दाख में जारी वर्ष से पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की तैयारी है। विंटर कार्निवल इस दिशा में एक कोशिश है। लद्दाख को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पर्यटन मुख्य भूमिका निभाएगा। ऐसे में इसमें बड़े पैमाने पर निवेश की भी उम्मीद है। तीन दिवसीय कार्निवाल के दौरान पुराने लेह में हेरिटेज वाक, पोलो मैच, ट्रैकिंग अभियान व 22 व 23 फरवरी को विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। विचार विमर्श सत्र के मुद्दे विंटर खेल, साहसिक गतिविधियां, लद्दाख का पर्यावरण व वन्यजीव होंगे।

न्यूज गैलरी

उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या में फैसला 29 को

नई दिल्ली : उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा 29 फरवरी को फैसला सुनाएंगे। इस मामले में सभी आरोपितों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को पीड़ित पक्ष के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने अंतिम बहस की। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से 55 लोगों की गवाही हुई, जबकि आरोपित पक्ष की तरफ से नौ गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। सीबीआइ ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को हत्या का आरोपित नहीं बनाया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील की दलीलों के बाद कुलदीप सेंगर पर भी हत्या का ट्रायल हुआ। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर व अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस मामले में कुलदीप सेंगर के अलावा उसका भाई अतुल सेंगर, माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, एसआइ कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान सहित कुल 11 आरोपित हैं। (जासं)

केरल में बस से टकराई कंटेनर लारी, 20 यात्रियों की मौत

कोयंबटूर (तमिलनाडु) : टाइल लदी एक कंटेनर लारी के गलत लेन में घुसने के बाद बेंगलुरु से आ रही केरल जाने वाली ट्रांसपोर्ट बस के बीच आमने सामने की टक्कर में 20 यात्रियों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। यह हादसा गुरुवार को भोर में तमिलनाडु हाईवे पर हुआ। पुलिस ने कहा कि केरल राज्य पथ परिवहन निगम की बस हादसे का शिकार हुई है। चार बजे भोर के आसपास यह बस सलेम-कोच्चि हाईवे पर कोयंबटूर से 40 किलोमीटर दूर तिरुपुर के अविनाशी में थी। बेंगलुरु से एर्नाकुलम जा रही बस में कम से कम 48 यात्री सवार थे। हादसे में मौके पर ही दम तोड़ने वाले सभी 20 यात्री केरल के निवासी हैं। (प्रेट्र)

सुरक्षा बलों को बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट में दिखे नक्सली

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन प्रहार लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। फोर्स को दो नक्सलियों को मारने में सफलता मिली। सुकमा जिले में नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों ने 30 घंटे तक ऑपरेशन चलाया। कोबरा, डीआरजी व एसटीएफ की टीम के साथ नक्सलियों की पांच बार मुड़भेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों ने दो जगह एंबुश भी लगाया था। मुठभेड़ के दौरान नक्सली बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट पहने देखे गए। (नईदुनिया)

राजस्थान में दो एससी युवकों से बर्बरता पर कांग्रेस सख्त

मांगी रिपोर्ट ▶ राहुल ने ट्वीट कर घटना को बताया क्रूरतापूर्ण व भयावह

वीडियो वायरल होने के बाद नागौर का मामला आया सामने, सात गिरफ्तार

जागरण ब्यूरो, जयपुर

राजस्थान में अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ अत्याचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। नागौर जिले के करणू गांव में अनुसूचित जाति के दो युवकों के साथ बर्बरता से मारपीट और अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को गहन जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी इन पीड़ित युवकों के खिलाफ 50 हजार रुपये चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा है कि इस मामले के वीडियो से जाहिर हो रहा है कि अजा युवकों के साथ क्रूरतापूर्ण अत्याचार किया जा रहा है। यह भयावह है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के अशोक गहलोत की सरकार से मामले तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी को नागौर के एक गांव स्थित एक ऑटोमोबाइल एजेंसी पर दो युवक बाइक की सर्विसिंग के लिए गए थे। यहां इन दोनों युवकों पर चोरी का इल्जाम लगा कर उनके साथ बर्बरता से मारपीट और अमानवीय कृत्य किया गया।

पुलिस का दावा है कि 19 फरवरी को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पांचैडी के थानाधिकारी को मामले का पता चला। इसके बाद थानाधिकारी ने घटनाक्रम पता किया और पीड़ित युवकों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीम सिंह, आईदान सिंह, जसु सिंह, सवाई सिंह, लिछमण सिंह, हनुमान सिंह व गणपतराम सोनी ने उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की। इस दौरान सर्विस सेंटर के पीछे ले जाकर अमानवीय बर्बरता की। इसके साथ ही जाति सूचक गालियां देकर धमकी देते हुए बंधक बना लिया। इसके बाद पीड़ित युवक के बड़े भाई को बुलाकर 5100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लेकिन युवक की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल से प्राथमिक उपचार करवा कर छोड़ दिया। राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नागरिक अधिकार) डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में हनुमान सिंह राजपूत, आईदान सिंह, भीम सिंह तथा घटना में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले में तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया। गौरतलब है कि राजस्थान में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2019 की बात करें तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, एससी के खिलाफ अत्याचार के कुल 6794 मामले दर्ज किए गए।

पीएफआइ को लेकर ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट

कसता शिकंजा

- कुछ राज्यों और अन्य जांच एजेंसियों से भी मांगी है जानकारी
- सीएए विरोधी प्रदर्शनों के लिए धन उपलब्ध कराने का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पीएफआइ पर कट्टरता को बढ़ावा देने तथा देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के आरोप हैं।

केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और अन्य एजेंसियों से भी पीएफआइ को लेकर रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने जानना चाहा है कि क्या उनके राज्यों में आयोजित सीएए विरोधी प्रर्दशनों में भी पीएफआइ शामिल रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को ईडी ने पीएफआइ से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। उसकी जांच की जा रही है।

माना जा रहा है कि ईडी ने पीएफआइ और उससे जुड़े एक एनजीओ के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में संगठन के पदाधिकारियों से पूछताछ की है। इसके बाद उसने यह रिपोर्ट तैयार की है। केरल स्थित संगठन के आधा दर्जन पदाधिकारियों से ईडी ने इसी महीने की शुरुआत में पूछताछ की थी। उनसे वित्त, व्यय, आय के विभिन्न स्रोतों तथा संगठन के धन का लाभ उठाने वाले लोगों के बारे में सवाल पूछे गए थे।

सूत्रों का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत पीएफआइ के पदाधिकारियों के भी बयान दर्ज किए गए। ईडी ने पीएफआइ और उसके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) रेहाब इंडिया फाउंडेशन (आरआइएफ) के खिलाफ वर्ष 2018 में पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसकी जांच की जद में पीएफआइ, आरआइएफ और कुछ अन्य के बैंक खाते हैं, जिनमें अलग-अलग मौकों पर विभिन्न स्रोतों से 120 करोड़ रुपये जमा किए गए। इस सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने भी मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया है।

प्रतीकात्मक।

तिहाड़ जेल में ही चावला से करनी होगी पूछताछ

जासं, नई दिल्ली : भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच-फिक्सिंग मामले में प्रत्यर्पण कर दिल्ली लाए गए संजीव चावला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने जांच एजेंसी को तिहाड़ जेल में ही चावला से निर्धारित समयसीमा के अंदर 28 फरवरी तक पूछताछ करने का आदेश दिया। जांच एवं पूछताछ के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि चावला को मुकदमा चलने और सजा सुनाए जाने तक तिहाड़ जेल में रखा जाए, जैसा कि भारत सरकार ने विदेशी प्राधिकारियों को आश्वासन दिया था।

12 दिन के न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनती देने वाली चावला की याचिका पर पीठ ने स्पष्ट किया कि इसके बाद चावला से पूछताछ के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठ ने जांच एजेंसी से कहा कि पूछताछ के दौरान चावला से सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन की उस दलील को रिकॉर्ड पर लिया कि एजेंसी द्वारा चावला से सिर्फ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में पूछताछ की जाएगी।

बुधवार को गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जानकारी दी थी कि सरकार ने कभी भी यूनाइटेड किंगडम (यूके) की अदालत को यह आश्वासन नहीं दिया कि संजीव चावला से जुड़े मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने पीठ को बताया कि निष्पक्ष ट्रायल के लिए संजीव के खिलाफ जुटाए गए सुबूतों से सामना कराना पड़ेगा, ताकि साजिश का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल अन्य आरोपितों की पहचान की जा सके।

13 फरवरी को निचली अदालत ने मामले में पूछताछ के लिए संजीव चावला को 12 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। याचिका पर एएसजी संजय जैन ने कहा था कि तिहाड़ जेल में रहेंगे और जांच एजेंसी वहीं पर उनसे पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि अगर जांच के लिए चावला को जेल से बाहर ले जाने की जरूरत होगी तो अदालत से इसकी अनुमति ली जाएगी। एएसजी ने कहा था कि भारत सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से यूके कोर्ट में कहा था कि चावला से अब तक पूछताछ नहीं की गई है और वह कभी जांच के लिए उपलब्ध नहीं रहा है। फरवरी-मार्च 2000 में भारत में आयोजित हुई भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट मैच सीरीज में हुई फिक्सिंग मामले में 19 साल बाद संजीव चावला को लंदन से प्रत्यर्पण पर दिल्ली लाया गया था।

वकील ने दोषी विनय को बताया मानसिक रूप से बीमार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस अदालत में एक अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि विनय को सिजोफ्रेनिया (एक तरह का पागलपन) है और उसे इलाज की जरूरत है। विनय के सिर पर गंभीर चोट लगी है और उसके हाथ पर भी प्लास्टर लगा है।

तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अदालत में कहा गया कि विनय ने रविवार को जेल नंबर 3 के सेल में अपना सिर फोड़ लिया और उसको मामूली चोट आई थी, जिसका इलाज जेल में ही करा दिया गया है। वहीं, उसके वकील ने अदालत में कहा कि विनय के परिजनों के कहने पर वह उससे मिलने जेल गए थे। जहां देखा कि उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है और हाथ भी टूटा हुआ है। वह लोगों को नहीं पहचान रहा है। यहां तक की

अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कल तक मांगा जवाब

विनय कुमार(फाइल)

वकील ने कहा, लोगों को नहीं पहचान रहा, इहबास में इलाज की जरूरत

उसने उन्हें और मां को भी नहीं पहचाना। अर्जी में कहा गया है कि विनय को एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत है और उसे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस (इहबास) में भर्ती कराया जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस अर्जी पर शनिवार तक तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने 17 फरवरी को विनय, अक्षय, मुकेश और पवन के खिलाफ तीन मार्च के लिए डेथ वारंट जारी किया था।

कमल हासन की फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा, तीन लोगों की गई जान

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : जाने-माने अभिनेता कमल हासन की आगामी फिल्म 'इंडियन 2' के सेट पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें फिल्म के असिस्टेंट निर्देशक समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दस लोग घायल हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में अभिनेत्री काजल अग्रवाल और कमल हासन भी बाल-बाल बच गए।

दरअसल, बुधवार देर रात चेन्नई के ईवीपी स्टूडियो में सेट बनाने का काम चल रहा था, तभी वहां अचानक एक क्रेन गिर गई, जिसकी चपेट में आने से फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर कृष्णा, प्रोडक्शन असिस्टेंट मधु और आर्ट असिस्टेंट चंद्रन की मौत हो गई। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। हासन और काजल अग्रवाल ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हासन ने लिखा, 'आज (19 फरवरी को) जो हादसा हुआ वह बहुत खतरनाक था। मैंने अपने तीन सहयोगियों को खो दिया है। उनके परिवार वालों का दर्द मेरे अपने दर्द से कई गुना ज्यादा है। इस हादसे के लिए मैं दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं। अस्पताल में हासन ने कहा कि वह इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को एक करोड़ रुपये देंगे। काजल ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछली रात (19 फरवरी) उस भयानक हादसे के बाद से वह सदमे में हैं। अभिनेत्री ने लिखा, 'उस हादसे में बचकर जीवित रहने में बस एक सेकेंड का समय लगा। वह एक पल। आभारी हूं। समय और जिंदगी की अहमियत से बहुत कुछ सीखा और इसका सम्मान करती हूं।'

अपनी फिल्म इंडियन-2 के सेट पर मारे गए मजदूरों के प्रति फिल्म अभिनेता व राजनेता कमल हासन ने गुरुवार को चेन्नई में शोक संवेदना व्यक्त की। प्रेट्र

पंजाब में कंटीली तार पार कर कृषि विभाग ने किया टिड्डियों का सफाया

मोहित गिल्होत्रा, फाजिल्का

पंजाब के जिला फाजिल्का में 18 फरवरी को फिर टिड्डी दल का हमला हुआ है। इस बार ये हमला भारत-पाक सीमा पर बसे गांव बारेकां में हुआ। जहां गांव के सहित कंटीली तार के पार किसानों द्वारा की गई खेती पर टिड्डी दल ने हमला किया। इसकी सूचना मिलने पर कृषि विभाग गांव में पहुंचा और कई स्थानों पर टिड्डियों को मार गिराया। इसी के तहत मंगलवार सुबह बीएसएफ अधिकारियों की सहमति से कृषि विभाग ने किसानों सहित कंटीली तार पाकर जाकर स्प्रे करके टिड्डियों का सफाया किया।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान के कई क्षेत्रों में उत्पात मचाने के बाद फाजिल्का जिले में कई जगहों पर टिड्डियां दिखाई दी थीं। इसके तहत तीन फरवरी को बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने जिले के गांव रूपनगर की तरफ रुख किया था और शाम होने के चलते पेड़ों पर डेरा डाला था। इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा आपात बैठक बुलाई गई थी और स्प्रे करके लाखों टिड्डियों को मार गिराया था।

फाजिल्का के तहत गांव बारेकां में स्प्रे करते कृषि विभाग के कर्मचारी। विज्ञप्ति

किसान बोले-टिड्डी दल का हो पूर्ण हल : गांव बारेकां के किसान जगदीश कुमार, जोगिंद्र सिंह व किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रगट सिंह ने कहा है कि टिड्डी दल के हमले को लेकर भले ही कृषि विभाग पूरी तरह से सर्तक है। मगर, टिड्डियों का पूर्ण हल होना चाहिए। इसके लिए भारत को पाकिस्तानी से बात करके इसका निवारण करना चाहिए।

बराड़ ने कहा, स्प्रे से मार गिराई टिड्डियां: जिला कृषि अधिकारी मंजीत सिंह बराड़ ने कहा कि गांव बारेकां के भीतर व कंटीली तारों के पार स्प्रे के जरिये टिड्डियों का पूरी तरह से सफाया किया जा चुका है। मंगलवार को टिड्डियों के खात्मे के बाद से ही विभाग की टीमें गांव के किसानों के साथ संपर्क बनाए हुए है, ताकि दोबारा हमले पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को टिड्डियों से घबराने की जरूरत नहीं हैं।

भोपाल में आइपीएस अधिकारियों से भरी नाव पलटी

नईदुनिया, भोपाल : आइपीएस सर्विस मीट 2020 के दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया। मीट में शामिल होने आए अधिकारियों की नाव मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बड़े तालाब में पलट गई। नाव में डीजीपी वीके सिंह की पत्नी तुहीन, डीजी विजय कटारिया, उनकी पत्नी, एडीजी राजेश चावला सवार थे। सभी लोग लाइफ जैकेट पहने थे। उनकी नाव के पीछे राज्य का राहत एवं आपदा बचाव प्रबंधन दल भी था। जैसे ही नाव डूबी आपदा प्रबंधन के दल ने सभी को बचा लिया।

आइपीएस मीट के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट्स रखे गए थे। इसमें शामिल होने के लिए सभी आइपीएस अधिकारी पहुंचे थे। राज्य आपदा राहत प्रबंधन दल के एडीजी डीसी सागर वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता करा रहे थे। इसी बीच एडीजी विजय कटारिया, उनकी पत्नी, डीजीपी वीके सिंह की पत्नी तुहीन, एडीजी राजेश चावला अपने परिजनों के साथ नाव चलाने के लिए निकल गए। इसी दौरान कुछ दूरी पर जाकर उनकी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पलटने के साथ ही उनके साथ चल रहे आपदा प्रबंधन दल ने उन्हें बचा लिया।

जौहर यूनिवर्सिटी में चला बुलडोजर

आजम खां प्रकरण

जागरण संवाददाता, रामपुर

रामपुर प्रशासन ने गुरुवार को सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलवा दिया। तीन स्थानों पर चाहरदीवारी तोड़ी गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चकरोड की भूमि पर कुलपति आवास का कुछ हिस्सा और मेडिकल कॉलेज की इमारत का हिस्सा खुद हटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी और तहसीलदार प्रमोद कुमार गुरुवार दोपहर पुलिस फोर्स के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां चकरोड की जमीन पर बनी चाहरदीवारी पर बुलडोजर चलवा दिया। मेडिकल कॉलेज और कुलपति आवास के सामने की दीवार भी तोड़ी गई। इसके बाद जिला सहकारी बैंक की ओर और दक्षिण दिशा में बनी चाहरदीवारी पर भी बुलडोजर चला दिया गया। चकरोड की जमीन खाली कराने को लेकर काफी दिन से प्रक्रिया चल रही थी। सपा शासनकाल में चकरोड की जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया था और इसके बदले में दूसरी जमीन ग्राम पंचायत को दे दी गई थी। इस मामले में पिछले दिनों राजस्व परिषद ने चकरोड की जमीन को कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया। परिषद ने जमीन की अदला-बदली को भी गलत माना था। इसके बाद प्रशासन ने पैमाइश कर चकरोड की जमीन पर कब्जा ले लिया और ग्राम पंचायत सींगनखेड़ा के सुपुर्द कर दिया। साथ ही उप जिलाधिकारी ने जमीन पर बने निर्माण को हटाने के लिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कुलाधिपति सांसद आजम खां को भी नोटिस जारी किया। निर्माण हटाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था, जो 16 फरवरी को पूरा हो गया। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया। इस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि तीन स्थानों पर 12-12 फीट चारदीवारी तोड़ दी गई है।

दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी के कुलपति सुल्तान मोहम्मद खान का कहना है कि चारदीवारी का मुकदमा तहसील सदर और राजस्व परिषद में विचाराधीन है। इसके बाद भी एसडीएम ने चाहरदीवारी पर बुलडोजर चलवा दिया।

जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी तोड़ने से पहले गेट पर खड़ा बुलडोजर। जागरण

सफलता

बिहार के बरौनी रेलवे स्टेशन से 30 साल पहले लापता हो गई थीं रुक्मिणी देवी, बंगाल रेडियो क्लब के सदस्य ने गंगासागर में एक साइक्लोन सेंटर में देखा

बंगाल रेडियो क्लब ने 30 साल पहले लापता मां को बेटों से मिलाया

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता

वह क्षण दिवास्वप्न की तरह ही था, जब बेटों को उनकी बिछड़ी मां 30 साल बाद मिल गई। खुशी से मां और उसके बेटों की आंखें छलक गईं। बिहार के बरौनी स्टेशन से 30 साल पहले लापता होने वाली रुक्मिणी देवी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागरदीप में मिलीं। रुक्मिणी देवी को उनके बेटों से मिलाने में में बंगाल रेडियो क्लब के सदस्यों की भूमिका अहम रही।

बिहार के सारन जिले की रुक्मिणी देवी 30 साल पहले कोलकाता में काम करने वाले अपने पति रामनाथ राय से मिलने के लिए अपने बच्चों के साथ निकली थीं। वह अपने बड़े बेटे मिथिलेश, मझले बेटे दिनेश तथा छोटे बेटे दीपक को लेकर बरौनी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। हालांकि तब उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तभी उन्होंने अपने 14 वर्षीय बेटे मिथिलेश के पास छोटे बेटों दिनेश व दीपक को देकर कहा कि वह थोड़ी देर में आ रही हैं। उसके बाद वह नहीं लौटीं। गांव के कुछ लोगों ने प्लेटफार्म पर उन बच्चों को पहचान लिया तथा उन्हें घर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद रुक्मिणी देवी का कोई पता नहीं चला।

रुक्मिणी देवी (बीच में) के साथ उनके बड़े बेटे मिथिलेश (पीछे), छोटे बेटे दीपक (बाएं) व पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब के संचालक सदस्य दिबस मंडल (दाएं)। जागरण

साइक्लोन सेंटर के बरामदे में मिलीं

रेडियो क्लब के सचिव अंबरीश नाग विश्वास ने बताया कि वर्षों से गंगासागर मेले में देशभर के श्रद्धालु आते हैं और उनमें से कई बिछड़ कर या किसी कारणवश यहीं रह जाते हैं। इस साल पहली बार दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी पी उलगानाथन की पहल पर रेडियो क्लब के सदस्यों ने बिछड़े लोगों को परिवार से मिलाने के लिए सागर मेले के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। उसी दौरान गंगासागर में एक साइक्लोन सेंटर के मिली 60 वर्षीया महिला को देखकर बंगाल रेडियो क्लब के संचालक सदस्य दिबस मंडल की उत्सुकता जगी। वृद्धा से सवाल करने पर वह अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बता पाईं। मंडल ने हार नहीं मानी और रेडियो क्लब के सदस्यों ने रुक्मिणी देवी के घर का पता लगाने के लिए ठान ली। बाद में किसी तरह रुक्मिणी देवी की बातों से उनके घर का पता चला और गहराई से जांच करने पर पता चला कि 30 साल पहले बरौनी स्टेशन से एक महिला लापता हो गई थी।

ऐसे मिलाया बेटों से

इसके बाद रेडियो क्लब के सदस्य गंगासागर से रुक्मिणी देवी को सामने रखकर बाजितपुर के लोगों के पास वीडियो कॉल किया। रुक्मिणी देवी को उनके बेटे मिथिलेश तथा अन्य परिजन व गांव वासियों ने देखा, लेकिन कोई पहचान नहीं पाए। इसी बीच छोटे बेटे दीपक का नाम सुनकर रुक्मिणी देवी की आंखें भर आई। इसके बाद रेडियो क्लब के सदस्य रुक्मिणी देवी की फोटो लेकर सारण पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मिथिलेश के लड़के अमित यानी रुक्मिणी देवी के पोते से हुई। वह उन्हें अपने घर ले गया लेकिन वहां कोई भी फोटो देखकर रुक्मिणी देवी को पहचान नहीं पाया। क्योंकि रुक्मिणी देवी जब लापता हुई थीं तब उनके तीनों बेटे काफी छोटे थे। रुक्मिणी देवी के पति रामनाथ राय का 10 साल पहले निधन हो गया है। इसके बाद रुक्मिणी देवी की फोटो को लेकर परिजनों के साथ-साथ गांव के बड़े-बुजुर्गों को दिखाया गया। इस दौरान ज्यादातर लोग रुक्मिणी देवी को पहचान गए। इसके बाद ही रुक्मिणी देवी को घर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद रुक्मिणी देवी के बड़े बेटे मिथिलेश अपने छोटे भाई दीपक व अपने चाचा के साथ गंगासागर पहुंचे।

पटना हाई कोर्ट ने कहा, सरकारी स्कूलों में पढ़ें अधिकारियों के बच्चे

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश डा. अनिल कुमार उपाध्याय ने बिहार सरकार की नीतियों पर तल्ख टिप्पणी की है। पूर्णिया में गेस्ट टीचरों को हटाए जाने के मामले पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में खुद हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह भी बताने को कहा कि बिहार में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है?

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि भविष्य में गरीबों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे में उन्हें सरकारी स्कूलों की कोई चिंता नहीं रहती। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। अदालत ने हलफनामा दायर करने के लिए मुख्य सचिव को 23 मार्च तक का समय दिया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 फरवरी 2020

दैनिक जागरण

यदि आप पराजय से सीख सकें, तो आप दरअसल हारे नहीं हैं

अमेरिका से उम्मीदें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान व्यापार पर किसी समझौते की संभावना न होने के बावजूद इस यात्रा को लेकर उत्सुकता है तो इसीलिए कि रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, आतंकवाद से लड़ाई, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क समेत अन्य अनेक मसलों पर सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा इन उम्मीदों पर इसलिए खरी उतरनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। चूंकि दोनों देश एक-दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं इसलिए यह तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय मसलों के साथ-साथ उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिनमें दोनों के साझा हित निहित हैं। पश्चिम एशिया के हालात और चीन-पाकिस्तान के रवैये को लेकर दोनों देशों को आपसी समझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये पर निर्भर करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ समस्या यह है कि वह कई बार अपने राष्ट्रीय हितों के आगे मित्र देशों और कभी-कभी तो वैश्विक हितों की भी अनदेखी कर देते हैं। भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति के इस रवैये को लेकर सतर्क रहना होगा।

यह ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप अलग स्वभाव वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन यह बुनियादी बात तो उन्हें पता होनी ही चाहिए कि दो देशों के बीच समझौते तभी होते हैं जब वे उभय पक्षों के लिए उपयोगी होते हैं। व्यापार मामले में नई दिल्ली जिस तरह वाशिंगटन की अनुचित शर्तें मानने के लिए सहमत नहीं हुआ उससे अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका भी आभास हो जाना चाहिए कि आज के भारत के साथ ऐसे समझौते नहीं किए जा सकते जो दोनों देशों के लिए हितकारी न हों। निःसंदेह अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है। एक तथ्य यह भी है कि अमेरिका की उन्नति में भारतीयों की एक बड़ा भूमिका है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद जा रहे हैं तो भारतीय मूल के लोगों को आकर्षित करने के इरादे से भी। जब यह स्पष्ट है कि दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है तब फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि आपसी विश्वास को बढ़ाने की दिशा में हर संभव कदम उठाए जाएं। दोनों देशों को अपने साझा हितों की पूर्ति के साथ साझा समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए। बेहतर होगा कि अन्य अनेक मसलों के साथ दोनों देश फर्जी और वैमनस्य फैलाने वाली खबरों पर अंकुश लगाने के उपायों पर भी चर्चा करें। यह चर्चा इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जिन प्लेटफार्म से यह काम हो रहा है उनके मुख्यालय अमेरिका में ही हैं।

प्रदूषण पर नियंत्रण

कचरे को आग लगाने से बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए जम्मू नगर निगम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश सही दिशा में उठाया गया कदम है। कचरे के निस्तारण के बजाय इसमें आग लगाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। लोग कचरे में आग लगा कर शहर की आबोहवा को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहे थे। दोषियों पर पांट हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इन दिनों जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। अगर पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो काफी देर हो जाएगी। लाइन सेवा भी शुरू कर लोगों से कचरे में आग की शिकायत के लिए टेलीफोन नंबरों को सार्वजनिक किया है। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जरूरी है कि प्रदूषण के स्तर को हर तरह से नियंत्रित किया जाए। अभी शहर की आबोहवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों के लिए खतरनाक बनती जा रही है। अगर उप राज्यपाल प्रशासन ने अभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जम्मू शहर के व्यस्त सतवारी चौक की करें तो यहां प्रदूषण का स्तर 81.28, अंबफला चौक 79.31, गुम्मट चौक 81.06 तक पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज चौक पर तो ध्वनि प्रदूषण 75.88 है, जो खतरे से ऊपर है। अस्पताल के पास खतरे के स्तर को पार कर जाना चिंताजनक है। ध्वनि प्रदूषण भी अन्य प्रदूषण की तरह ही इंसान पर कई तरह के दुष्प्रभाव डालता है। इससे इंसान में चिड़चिड़ापन, तनाव, बेवजह चिंतित रहना आदि की शिकायत होती है तो कभी-कभी जानलेवा हद तक पहुंच जाती है। दुखद है कि धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का श्रीनगर शहर गत वर्ष विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 10वें तथा मंदिरों का शहर जम्मू 20वें पायदान पर है। जम्मू का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वर्ष 120 तक पहुंच गया है। माना कि शहरों का विकास जरूरी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तर्ज पर अगर पेड़ों को उखाड़ कर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो इन्हें कटने से बचाया जा सकता है। हालांकि इसमें थोड़ी मेहनत और खर्च तो आता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए यह अच्छा विकल्प है।

आसान नहीं राजनीति के अपराधीकरण पर रोक

डॉ. एके वर्मा

चूंकि बाहुबली जनप्रतिनिधि और उसका दल उसके निर्वाचन को जनता के 'आशीर्वाद' के रूप में महिमामंडित करते हैं इसलिए शायद न्यायपालिका के निर्देश का सकारात्मक असर न हो

राजनीति में अपराधियों की 1970 के दशक से जो बाढ़ आई वह अब विकराल रूप ले चुकी है। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु अनेक आयोग बने, कुछ प्रयोग भी हुए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। संसद, विधानसभाओं और पंचायतीराज संस्थाओं में आपराधिक वृत्ति वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 2004 में 24 प्रतिशत, 2009 में 30, 2014 में 34 और 2019 में 43 प्रतिशत दागी किस्म के लोग संसद पहुंचे। वर्तमान में 159 सांसदों पर हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे सांसदों से हमें क्या अपेक्षा हो सकती है? आचार, विचार और व्यवहार के जो मानक सांसदों से अपेक्षित हैं वे दिखाई नहीं देते। जब अपराधियों पर लगाम लगाने की बात होती है तो सब किनारा कर लेते हैं। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवारों को टिकट मिलने के बाद उन्हें अपने ऊपर दर्ज सभी अपराधों की सूचना अपने दल को देनी होगी और दल को 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से बताना होगा कि उसने अपराधी छवि के प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया? सितंबर 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशियों को निर्देश दिया था कि चुनाव लड़ने से पूर्व उन्हें अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका प्रचार-प्रसार भी करना होगा। उसने संसद को सुझाव दिया था कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने हेतु वह कानून बनाए, लेकिन न प्रत्याशियों ने उसे माना, न संसद ने। क्या हम नहीं चाहते कि इस पर लगाम लगे? क्या दलों को यह लगता है कि आम आदमी के राजनीति में आने से उनके निहित स्वार्थों पर विपरीत असर पड़ेगा?

आज साधारण व्यक्ति किसी पार्टी से टिकट की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर टिकट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की कौन कहे, पंचायत चुनावों तक में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सत्ता, अपराध और धन की तिकड़ी राजनीति पर जैसे कुंडली मारकर बैठी है। ऐसे में लोगों की आस्था लोकतंत्र से उठ सकती है और तब जनता संभवतः कोई वैकल्पिक प्रयोग करना चाहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरुण मिश्र ने क्षुब्ध होकर टिप्पणी की, 'इस देश में कानून बचा भी है? यहां रहने से बेहतर है कि देश छोड़ कर चला जाऊं।' जब न्यायमूर्ति की यह दशा है तो आमजन की क्या दुर्दशा होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। पूरी व्यवस्था बाबुओं, अधिकारियों, माफिया और नेताओं की ऐसी जकड़न में है कि कितना भी योग्य, कर्मठ, ईमानदार नेतृत्व हो, जनता को राहत नहीं मिलती।

अवधेश राजपूत

अपवादों को छोड़ अधिकांश नेताओं के लिए राजनीति एक 'निवेश' है और सत्ता में आने पर व्यवस्था को निचोड़ कर धनार्जन उनका एकमात्र उद्देश्य। यदि इसे बदलना है तो सभी संस्थाओं का दायित्व है कि वे राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट की पहल जनचेतना के स्तर पर है जो मानती है कि लोग प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे तो उसे वोट नहीं देंगे। ऐसा होता तो हालिया दिल्ली चुनाव में आपराधिक छवि वाला अमानतुल्लाह इतने भारी मतों से कैसे जीतता? भ्रष्टाचार-लालफीताशाही से प्रशासनिक व्यवस्था इतनी जनविरोधी हो गई है कि मतदाता को 'एक बाहुबली' में ही अपनी समस्या का समाधान दिखाई देता है। बाहुबली जनप्रतिनिधि और उसका दल उसके निर्वाचन को जनता के 'आशीर्वाद' के रूप में महिमामंडित करते हैं। इसलिए शायद न्यायपालिका के निर्देश का सकारात्मक असर न हो।

अपराधियों के राजनीति में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम चुनाव आयोग 'एलॉटमेंट ऑफ सिंबल आर्डर 1968' के तहत गंभीर आरोपों वाले प्रत्याशियों को दलीय चुनाव चिन्ह से वंचित करे। इसके लिए उसे एक प्रशासकीय निर्णय लेना है। इससे अपराधी छवि का प्रत्याशी और उसका दल, दोनों दंडित होंगे, क्योंकि दलीय प्रत्याशी के मुकाबले स्वतंत्र उम्मीदवार का जीतना काफी मुश्किल होता है।

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को गैर संवैधानिक घोषित कर दो वर्ष या ज्यादा की कैद पाए सांसदों और विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त होने का आदेश दिया था। इससे लालू यादव की संसद सदस्यता गई थी। संसद को संविधान के अनु.102 और 191 अथवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर 'आपराधिक पृष्ठभूमि' के प्रत्याशियों की अयोग्यता में शामिल करना होगा, क्योंकि अपराधियों के दबदबे का यह आलम है कि वे जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं। ध्यान रहे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) के तहत जेल में बंद मतदाता वोट तक नहीं डाल सकता। न्यायपालिका को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर आरोपित जनप्रतिनिधि मुकदमे को लंबा न खींचें। कार्यपालिका को भी प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देना होगा जिससे सरकारी कार्यालयों में जनता लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से होने वाले उत्पीड़न से बच सके और उसे लगे कि बिना किसी 'रॉबिन हुड' के और बिना रिश्वत के उसका काम आसानी से हो जाएगा। सीधे सब्सिडी भेजना आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे दबंग बिचौलियों और दलालों से जनता को कुछ राहत मिली है। राज्य सरकारों के स्तर पर ऐसे सुधारों की बहुत दरकार है, क्योंकि आम आदमी का ज्यादा काम राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों से ही पड़ता है। इसी के साथ गैर-सरकारी और सिविल सोसायटी संगठनों को अच्छे लोगों को राजनीति में लाने की मुहिम चलानी चाहिए जिसकी परिकल्पना संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऐसी सामाजिक धारणा है कि राजनीति गुंडे-बदमाशों के लिए है। जनता को समझाना होगा कि यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छे निर्णय लेने वाली संसद और सरकार कैसे बनेगी और अच्छे समाज की नींव कैसे पड़ेगी? इस बदलाव में तकनीक, मीडिया और सोशल-मीडिया की भूमिका अहम है। वास्तव में सभी संस्थाओं और जनता के समन्वित प्रयास से ही राजनीति में अपराधियों के प्रवेश पर लगाम लग सकेगी।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

मातृभाषा से ही निकलेगी प्रगति की राह

यह पूर्णरूप से सत्य है कि मां, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोई महिला कितनी भी श्रेष्ठ एवं सुंदर हो वह हमारी मां नहीं हो सकती। कोई देश कितना भी संपन्न एवं समृद्ध हो, परंतु वह हमारी मातृभूमि नहीं हो सकता। इसी प्रकार विश्व की अन्य कोई भी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं हो सकती। इसे बांग्लादेश के लोगों ने सिद्ध किया है। 14 अगस्त, 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान स्वतंत्र देश बना तब पाकिस्तान के दो भाग थे। 1971 में पाक का विभाजन हो गया। पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने का महत्वपूर्ण कारण भाषा बनी। पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बांग्ला थी, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन शासकों ने उस पर उर्दू थोपी, जिसका वहां जबरदस्त विरोध हुआ। 21 फरवरी, 1952 को ढाका विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों ने बांग्ला को वहां की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उसे दबाने के लिए पाकिस्तान ने भरसक प्रयास किए। छात्रों पर गोलियां तक चलाईं, जिसमें अनेक बंगाली छात्रों ने अपनी मातृभाषा के लिए बलिदान दिया। उनकी स्मृति में वर्ष 1999 से यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया।

हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भाषा मात्र संप्रेषण का माध्यम है। वहीं यूनेस्को के अनुसार भाषा मात्र संपर्क, शिक्षा या विकास का माध्यम न होकर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान और उसकी संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास का कोश है। इसके साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को संजोने का कार्य भी मातृभाषा ही करती है। बांग्लादेश में हुए उस आंदोलन ने भी यह बात सिद्ध की कि मातृभाषा का महत्व मजहब, जाति आदि से भी अधिक है। जब कहीं कोई भाषा विलुप्त होती है तो उसके साथ एक संस्कृति और परंपरा पर भी पूर्ण विराम लग जाता है। आवश्यकता केवल इसकी ही नहीं है कि मातृभाषा के महत्व को समझा जाए। आवश्यकता इसकी भी है कि उनके संरक्षण के प्रयास किए जाएं। यह ठीक नहीं कि मातृभाषा के अनन्य महत्व को जानने-समझने के बाद भी हम उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में

अतुल कोठारी

मातृभाषा के अनन्य महत्व को जानने-समझने के बाद भी हम उनके संरक्षण में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं

1652 भाषाएं थीं। 1971 आते-आते यह संख्या 808 तक रह गई। भारत सरकार द्वारा की गई 2011 की जनगणना के अनुसार देश में भाषा के मानक पर खरी उतरने वाली 1369 बोलियां/भाषाएं थीं। इसमें से 121 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10 हजार से अधिक है। इसी में आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएं भी सम्मिलित हैं। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के वर्ष 2013 के अध्ययन के अनुसार देश में 780 भाषाएं हैं। पिछले 50 वर्ष में यहां 220 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं तथा 197 लुप्तप्राय होने के कगार पर हैं यही स्थिति दुनिया के अन्य अनेक देशों में हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मातृभाषाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं। सबसे अधिक खतरा उन भाषाओं को है जो छोटे समूहों द्वारा बोली जाती हैं।

कुछ विद्वानों का मानना है कि मां की भाषा ही मातृभाषा है। यह पूर्ण सत्य नहीं है, मां की भाषा के साथ-साथ बच्चे का शैशव/बचपन/बाल्यावस्था जहां बीतता है, उस माहौल में ही जननी भाव होता है। जिस परिवेश, परिवार एवं उसके सांस्कृतिक मूल्यों में बच्चे पलते हैं, वहां जो भाषा वह सीखता है वह भाषा उस बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। इस प्रकार मातृभाषा मात्र भावनात्मक विषय नहीं है, परंतु पूर्णरूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, यह जरूरी है। यूनेस्को सहित वैश्विक स्तर पर भाषा संबंधी हुए अनेक अध्ययनों, शिक्षा संबंधी संस्थाओं की अनुशंसाएं एवं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महापुरुषों के विचार इसकी पुष्टि करते हैं। गांधीजी ने कहा था कि विदेशी माध्यम ने बच्चों की तंत्रिकाओं पर भार डाला है, उन्हें रट्टू बना दिया और वे सृजन के लायक नहीं रहे हैं। विदेशी भाषा ने देसी भाषाओं के विकास को बाधित किया है।

सभी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य एवं प्रमाण मातृभाषा के पक्ष में होने के उपरांत भी हम अंग्रेजी के मोहजाल से मुक्त होने के बदले उस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। यदि आज हम शोध-अनुसंधान में पिछड़ रहे हैं तो इसका एक बड़ा कारण शोध-अनुसंधान का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना है। भारतीय वैज्ञानिक सीवी श्रीनाथ शास्त्री के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वालों की तुलना में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े छात्र अधिक उत्तम अनुसंधान करते हैं। इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने की दृष्टि से भारतीयों को प्राप्त नोबेल पुरस्कार और अपनी भाषा में शिक्षा देने वाले देश इजरायल, जापान, जर्मनी आदि के विद्वानों द्वारा प्राप्त नोबेल पुरस्कारों की तुलना करने से स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। यदि ये देश अपनी मातृभाषा के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते?

उचित यह होगा कि देसी विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में शोध अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में हों अथवा जो भी शोध अंग्रेजी में होते हैं उनका किसी एक भारतीय भाषा में अनुवाद अनिवार्य हो। चूंकि इन बातों का आधार शिक्षा है, इसके लिए जरूरी है कि देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा हो एवं उच्च शिक्षा के सभी स्तर पर भारतीय भाषाओं का विकल्प दिया जाना चाहिए। हमारे छात्र समझदार होने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था एवं अवसर दोनों होने चाहिए, परंतु शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। इसी से छात्रों का एवं देश का सही दिशा में विकास संभव हो सकेगा।

(लेखक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शिव और शिवत्व

यत् सत्यं तत् शिवं, यत् शिवं तत् सुंदरं। जहां सत्य है, वहां शिव है और जहां शिव है, वहां सुंदरता है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी है। सभी के लिए और सदा मंगलकारी एवं हितैषी होने के कारण वे सदाशिव हैं। परमात्मा शिव की समस्त संसार और प्राणियों के लिए हितकारिता ही उनकी सच्ची सुंदरता है। 'शि' और 'व' से बना शिव शब्द पापनाशक और मुक्तिदाता है। अर्थात जो सबके पाप हरते हैं और सबको मुक्ति देते हैं, वे परमात्मा शिव हैं। शिव के ज्ञान, गुण और शक्तियां ही तो उनके शिवत्व हैं। उन्हें धारण करने से मनुष्य में आंतरिक शक्ति एवं सद्गुणों का विकास होता है तथा उनके अवगुण एवं विकारों का अंत होता है। शिवत्व से ही मानव जीवन और समाज में देवत्व की पुनः स्थापना एवं दानवी संस्कारों की पूर्ण समाप्ति होती है। शिव आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं और शिवत्व उनके मंगलदायिनी गुण तथा शक्तियों की किरण, जो हर समय, हर स्थान और हर प्राणी के ऊपर पड़ती है। तभी तो गाते हैं, 'ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश।' परंतु अगर हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान सभी बंद पड़े हैं तो हम रोशनी न मिलने का दोष न तो सूर्य, न ही उसकी किरणों को दे सकते हैं। जैसे दैहिक प्राप्ति के लिए दैहिक संबंधियों को याद किया जाता है, वैसे ही देहरहित निराकार परमात्मा शिव से सुख-शांति रूपी शिवत्व की रोशनी पाने के लिए हमें अपने शरीर रूपी कुटिया यानी भृकुटि के मध्य विराजमान आत्मिक ज्ञान की खिड़की खोलनी होगी और निराकार शिव को याद करना होगा।

मनुष्य का मन-बुद्धि से शिव की स्मृति में रहकर सांसारिक कर्म में प्रवृत्त होने को ही सर्वोच्च योग यानी राजयोग कहा गया है। और इसी से ही हर कर्म में आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसाहस, आत्मकुशलता एवं आत्मसंतुष्टि रूपी शिवत्व की प्राप्ति होती है।

ब्रह्मा कुमारी आशा

दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन से पहले उनके सुरक्षा अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक जगह होंगे तो वहीं मान लीजिए कि दुनिया के दो सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे दिखाई दे रहे होंगे।

दरअसल पीएम मोदी को जो एसपीजी सुरक्षा मिलती है, उसमें 3000 कमांडो हैं। उनके पास एफएनएफ-2000 असॉल्ट राइफलें होती हैं और साथ ही ग्लोक-17 नाम की पिस्टल भी होती हैं। काले चश्मे उन्हें क्लीयर विजन देते हैं। वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। साथ ही दस्ताने और नी कैप भी पहने रहते हैं। इस एसपीजी दस्ते में पीएम मोदी को सुरक्षा देने के लिए आधुनिक गाड़ियां होती हैं, जिनमें अधिकतर बुलेट प्रूफ और हथियारों से लैस होती हैं। इसमें बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की सिडान कारें, बीएमडब्ल्यू की एसयूवी और साथ ही टोयोटा-टाटा की एसयूवी भी होती हैं। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर भारतीय वायु सेना के एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल एसपीजी सुरक्षा के कमांडो करते हैं।

फिर से

डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पर रोजाना करीब 36.5 करोड़ डॉलर खर्च होते हैं। यानी करीब 2500 करोड़ रुपये?

वहीं ट्रंप के सुरक्षा घेरे में 14 वाहन जरूर होते हैं। सबसे आगे और अगल-बगल में नौ ऐसे मोटर बाइक सवार होते हैं जो आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं। किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होते हैं और आगे का रास्ता साफ कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। सबसे आगे बीएमडब्ल्यू होती है। उसके बाद एसयूवी और उसके पीछे दो लिमोजिन कारें चल रही होती हैं। उसके ठीक पीछे एक शेवरले वाहन होता है। एसयूवी और पहली लिमोजिन में हथियारबंद एजेंट और सीक्रेट सर्विस के एजेंट होते हैं। बता दें कि ट्रंप जहां भी जाने वाले हाते हैं, सीक्रेट एजेंट महीने भर पहले ही उस जगह का दौरा कर लेते हैं। उनके पास आधुनिक हथियारों के साथ नाइट विजन गॉगल्स और ग्रेनेड होते हैं। इस पूरे सुरक्षा घेरे के बीच में चलती है ट्रंप की 'द बीस्ट' लिमोजिन, जो बमप्रूफ, केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होती है। यानी सुरक्षा के नजरिये से एकदम परफेक्ट। जिस सीट पर ट्रंप बैठते हैं, उसके बगल में सैटेलाइट फोन होता है, जिससे वे सीधे पेंटागन और उप राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। उनकी कार के शीशे पांच लेयर से बने होते हैं। उनकी कार का सिर्फ एक ही गेट खुल सकता है, ड्राइवर का, वह भी सिर्फ तीन इंच। उनके पीछे चल रही गाड़ियों में ट्रंप के डॉक्टर, मिलिट्री ऑफिसर, ट्रंप के ब्लड ग्रुप वाला खून भी होता है। यानी उनका सुरक्षा दस्ता हर मुसीबत से निपटने के लिए तैयार रहता है, भले ही वह मुसीबत कैसी भी हो। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पर रोजाना करीब 36.5 करोड़ डॉलर खर्च होते हैं। यानी करीब 2500 करोड़ रुपये?

जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर परिंदे ने पर मारने की कोशिश की तो जान से जाएगा।

(आइचौक.इन से साभार)

मेलबाक्स

देर से उठा सही कदम

संरक्षणवादी नीति के नुकसान शीर्षक से लिखे अपने लेख में विवेक कौल ने दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। पहला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आदि देशों के मुकाबले भारत कहां पर खड़ा है? दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग विशेषकर नेटवर्क से संबद्ध उत्पादों की असेंबलिंग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की समुचित भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो? इन दोनों सवालों के जवाब विचार और क्रियान्वयन के स्तर पर छिपे हुए हैं। अफसोस की बात है कि आजादी के बाद से ही देश की सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोगों की अर्थव्यवस्था को लेकर दृष्टि काफी तंग रही। उन्होंने जिस समाजवादी-संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, उसमें साहसी उद्यमियों के लिए कोई खास प्रोत्साहन नहीं था। पूरा जोर चूंकि सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन पर था, इसलिए शोध-अनुसंधान अथवा कौशल विकास की वैचारिकी विकसित न हो सकी। उदारीकरण के पूर्व तक तो किसी तरह यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन उदारीकरण एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में यह परंपरागत बंद अर्थव्यवस्था हमारे लिए घाटे का सौदा होती गई। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुप बैठी रही। सुधार के पहल हुए। उद्योगों के हित में नीतियां भी बनीं और उनका असर भी दिखा, लेकिन एक तो इसमें काफी देरी हुई, दूसरे देश की रोज बढ़ती कार्यशील आबादी की तकनीकी श्रेष्ठता के लिए ठोस प्रयास नहीं हुए। अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयास करती दिख रही है। इस बार के बजट में कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस आवंटन का सदुपयोग देश भर में प्रखंड स्तर पर कौशल विकास केंद्र तथा जिला स्तर पर तकनीकी-व्यावसायिक विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों की स्थापना करके की जानी चाहिए। यदि पैसे कम पड़ें तो पीपीपी मॉडल को अपनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के इस कठिन दौर में हम अपनी विशाल आबादी को अकुशल रखने का जोखिम नहीं उठा सकते।

चंदन कर्ण, देवघर

रोजगारपरक शिक्षा नीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई शिक्षा नीति पर खुद संज्ञान लिया है। इससे उनकी शिक्षा के प्रति रुचि, जागरूकता और गंभीरता का पता चलता है। हर्ष का विषय यह है कि यह शिक्षा नीति देश में वर्ष 1986 के बाद अथवा 34 वर्षों बाद आ रही है, जिसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तनों के बाद यह देश में जल्द लागू हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी इसका रोजगारपरक होना जो देश में रोजगारों के अवसरों अथवा काम के अवसरों को प्रेरित करने के साथ-साथ देश की साक्षरता दर में भी इजाफा करने का कार्य करेगी। नई शिक्षा नीति की सफलता केवल केंद्र सरकार की मेहनत पर ही नहीं, बल्कि राज्यों के सहयोग पर भी निर्भर करेगी। क्योंकि शिक्षा का विषय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अतः राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग की इसमें विशेष दरकार रहेगी, तभी यह योजना अपने अपेक्षित परिणामों तक पहुंच सकती है व देश की बुनियादी जरूरत शिक्षा और रोजगार के 100 फीसद मुकाम को हासिल कर सकती है।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

जरूरी है मातृभाषा

हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बच्चा सबसे पहले मातृभाषा अपने घर से सीखता है, जब परिवारजन उस भाषा में संवाद करते हैं। यह सराहनीय है कि राष्ट्र शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात कही गई है। इसमें इस तथ्य को स्वीकारा गया है कि भाषाओं को समझने के लिए सबसे अधिक बौद्धिक क्षमता 2-8 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। मातृभाषा में मजबूत नींव से ही अन्य भाषाएं बेहतर ढंग से सीखी जा सकती हैं। चूंकि भाषा सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है, अपनी मातृभाषा का बचाव करके ही हम भारत की सांस्कृतिक और भाषिक विविधता को सुरक्षित रख सकते हैं।

डिंपी भाटिया, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

36 करोड़ थी भारत की जनसंख्या वर्ष 1951 में यानी देश की स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जबकि आज यह आंकड़ा बढ़कर 136 करोड़ तक पहुंच गया है।

आजकल

आबादी काबू में करने के लिए बने कानून

प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बीच देश की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से सभी को समुचित सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में सरकार और समाज को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हमारी भीड़ जैसी बेतरतीब जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, किसी भी प्रकार के विकास कार्य का मकसद हासिल करना मुश्किल है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता राष्ट्र हित में है। एक सबल और मजबूत भारत के लिए इसकी जरूरत राजनीतिक हितों से ऊपर है

श्रीनिवास
सह संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

हाल ही में शिव सेना के एक सांसद ने जनसंख्या कानून बिल पेश करने की मांग संसद में उठाई है। इसके लिए शिव सेना ने 'छोटा परिवार बेहतर परिवार' का नारा दिया। सरकार पहले ही यह बात कह चुकी है। भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों में मानव संसाधन भी एक कारण रहा है। नए आर्थिक सिद्धांत भी इस बात की विवेचना करते हैं, लेकिन यह भी सोचना जरूरी है कि आबादी के साथ भूमि का विस्तार नहीं होता। प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ते। इसलिए एक समय के बाद जनसंख्या वृद्धि एक मुसीबत बन जाती जाती है। एक मजबूत देश की कल्पना जहां सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा मिले, वह अधर में लटक जाता है। विकास की गति थम जाती है, सामाजिक और प्राकृतिक विषमताएं कुकुरमुत्ते की तरह फैल जाती हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कठोर निर्णय लिया जाए ताकि विकासवादी नीतियों का विस्तार दिख सके। वर्ष 2020 के पहले दिन करीब चार लाख बच्चों का जन्म हुआ जिसमें 68 हजार भारत में बच्चों का जन्म हुआ, चीन दूसरे पायदान पर 46 हजार पर था। अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन मान चुके हैं कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होगा, चीन दूसरे स्थान पर होगा। इस बात की भी उम्मीद है कि आने वाले 100 वर्षों तक कोई भी देश भारत को पहले पायदान से हटा नहीं पाएगा। यह स्थिति आणविक बम से भी खतरनाक है।

भारत के पास केवल 2.4 प्रतिशत भूमि है, जबकि दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा भारत के खाते में है। पेयजल का चार प्रतिशत भाग ही भारत के पास है। भविष्य के संदर्भ में देखें तो यह समस्या घातक दिख रही है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के बीच देश की प्रगति और विकास कार्यों के लिए तैयार किया जाने वाला प्रारूप बाधक बनकर सामने आता है। आर्थिक समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ती जनसंख्या और उसके दुष्परिणामों के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। साथ ही इसके लिए कानून बनाने की बात भी वह कह चुके हैं। कई विद्वानों ने यह कहकर इस पहल की आलोचना शुरू कर दी कि भारत में इस कानून की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों ने तो इसे सांप्रदायिक रुख देने की कोशिश भी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष व शिया धर्मगुरु मौलाना डॉ. कल्बे सादिक ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। हम सभी का दायित्व है कि सब मिलकर देश को बेहतर बनाएं। ऐसा तभी होगा, जब जनसंख्या नियंत्रित होगी। आज जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उससे आने वाले दशकों में मुश्किलें खड़ी होंगी। यह कानून किसी समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह देशहित में है। आज हमारे पास स्वयं का अनाज, दवा, पानी है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रित नहीं हुई तो हमें दूसरे देशों का मोहताज होना पड़ेगा। ऐसा होगा, तो हम सिर उठाकर नहीं रह सकेंगे। इसलिए कानून की जरूरत एक तार्किक सच्चाई है जिससे कोई भी राजनीतिक दल इन्कार नहीं कर सकता।

आखिरकार यह समस्या इतनी विकराल बनी कैसे। देश की आजादी के बाद वर्ष 1951 में आबादी 36 करोड़ थी जो आज 136 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 1971 तक हर सातवां व्यक्ति भारतीय था, जबकि 2011 में हर छठा व्यक्ति भारतीय था। आर्थिक समीकरण भी भारत के प्रतिकूल है। भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जिसका मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। देश की जीडीपी में खेती और पशुपालन का योगदान 18 प्रतिशत है, जबकि कामगारों की तादाद 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

आबादी बढ़ने के कई उल्लेखनीय कारण हैं। स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर बेहतर हुई हैं। बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। 1971 से 2001 के बीच इस कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर 24 प्रतिशत रही है। एक कारण शिक्षा की कमी भी रही है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या दर में भारी अंतर है। सबसे ज्यादा तेजी हिंदी पट्टी के राज्यों में है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में विकास काफी धीमा रहा है। इसकी वजह से राज्य स्तरीय पलायन भी एक समस्या बन गई है।

चीन के मुकाबले तीन गुना अधिक वृद्धि दर : यदि चीन से तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल चीन का लगभग एक तिहाई है, लेकिन आबादी वृद्धि की दर चीन से तीन गुना ज्यादा है। चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे और भारत में प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा होते हैं। देश में मौजूद जल जंगल जमीन, रोटी कपड़ा मकान और गरीबी बेरोजगारी भुखमरी आदि समस्याओं के पीछे कारण जनसंख्या विस्फोट बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 103वें स्थान पर, साक्षरता दर में 168वें स्थान पर, वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स में 140वें स्थान पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें स्थान पर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 53वें स्थान पर, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें स्थान पर और होमलेस इंडेक्स में 8वें स्थान पर हैं।

जनसंख्या से पैदा होती चुनौती : भारत की बढ़ती आबादी हर व्यक्ति के लिए चुनौती है। जिस समुदाय में शिक्षा और जागरुकता की कमी है, वहां यह समस्या ज्यादा गंभीर है। इसलिए इसका हल महज इस बात पर नहीं छोड़ा जा सकता कि लोगों में स्वतः जागरुकता आएगी और लोग दो बच्चों से संतुष्ट हो जाएंगे। गरीब तबकों में मां-बाप प्रत्येक बच्चे को रोजगार का जरिया समझते हैं, जितने बच्चे होंगे उतने हाथ होंगे, लेकिन यह उनकी नासमझी है, एक मजबूत परिवार के लिए गुणसंपन्न बच्चे ज्यादा उपयोगी और आर्थिक व्यवस्था के लिए हितकर होंगे। यही सिद्धांत भारत के विकास पर भी लागू होता है।

विकास में बाधा डाल रही जनसंख्या

बाल मुकुंद ओझा

अमेरिकी शोध संस्थान 'वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू' की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण जीडीपी में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भारी उथल-पुथल के बीच भारत की जीडीपी के लिहाज से एक अच्छी खबर भी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब मोदी सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी पांच वर्षों में भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में वर्ष 2019 में 2,940 अरब डॉलर के साथ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जीडीपी के मामले में भारत ने पिछले वर्ष ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है।

हालांकि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगातार तीसरी तिमाही में कमजोर रहते हुए पांच फीसद के आसपास रह सकती है। जीडीपी को लेकर देश में भारी चर्चा हो रही है। आखिर ये जीडीपी है क्या? कहां से आया इसका विचार। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935-44 के दौरान इस्तेमाल किया था। यह वह समय था जब विश्व की बैंकिंग संस्थाएं आर्थिक विकास का अनुमान लगाने का काम संभाल रही थीं, जिनमें से ज्यादातर को इसके लिए कोई सटीक शब्द नहीं मिल रहा था। जब साइमन ने अमेरिकी कांग्रेस में शब्द 'जीडीपी' को परिभाषित करके दिखाया तो उसके बाद आइएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी से यह शब्द दुनिया भर में प्रचलित हुआ। जीडीपी को सरल भाषा में हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है जीडीपी।

जीडीपी किसी निश्चित अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर होती है। ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। सरल शब्दों में अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है। यदि किसी देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उस देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है जिससे देश का विकास प्रभावित होता है। इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप जीडीपी में गिरावट का सामना करना पड़ता है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.36 अरब है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। परिवार नियोजन के कमजोर तरीकों, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता का अभाव, अंधविश्वास और विकासात्मक असंतुलन के चलते आबादी तेजी से बढ़ी है। संभावना है कि 2050 तक देश की जनसंख्या 1.6 अरब हो जाएगी। तेजी से बढ़ रही आबादी विकास को अवरुद्ध कर रही है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था के साथ जीडीपी पर पड़ता है। देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या देश के विकास में बाधा है, यह हर कोई जानता और समझता है। फिर भी, बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास अब तक नहीं किया गया है। आज आवश्यकता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए।

आज हमारे पड़ोसी देश चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में अपना महत्वपूर्ण मुकाम स्थापित किया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उसने समय रहते अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया। मगर हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति और इस पर होने वाली सियासत विकास के बढ़ते कदम को रोक देती है जिसका खामियाजा आर्थिक मोर्चे पर हमें उठाना पड़ता है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

अजी! कुछ तो बोलिए बजट पर

कैलाश मंडलेकर

बजट आने के बाद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की परंपरा लंबे समय तक चलती रहती है। बजट आते ही कैमरे वाले बाइट लेने निकल पड़ते हैं। बाइट देने वाले भी उतने ही उतावले बैठे रहते हैं। बजट की फितरत होती है कि वह पूरी तरह किसी के समझ में नहीं आता। उसे बनाया ही ऐसे जाता है कि वह समझ में न आए। बिना समझे बजट पर आत्मविश्वास के साथ बोल लेना बहुत बड़ी कला है।

बजट के बारे में मेरी जानकारी इतनी ही है कि वह हर साल आता है और चला जाता है। हम लोग उस श्रेणी में आते हैं, जो कारवां गुजर जाने के बाद गुबार देखते रहते हैं। जैसे ही बजट आता है, वित्त मंत्री का फोटो अखबार के मुखपृष्ठ पर छप जाता है। कुछ लोग तो फोटो देखकर ही अंदाज लगा लेते हैं कि हो न हो, बजट आया होगा। फोटो में वित्त मंत्री के चेहरे पर मुस्कान और हाथ में अटैची होती है। आम धारणा है कि बिना बजट के वित्त मंत्री का फोटो नहीं छपता। लगता है, वित्त मंत्री फोटो छपाने के लिए ही बजट बनाते होंगे। हालांकि आजकल वित्त मंत्री लोग अटैची की जगह खाता-बही लाने लगे हैं, जिसमें पारंपरिक रूप से लाभ और शुभ का प्रावधान रहता है। जहां तक लाभ का सवाल है तो वह हर हाल में सरकार का ही होता है और जनता के हिस्से में चाहे शुभ आए या अशुभ, इससे वित्त मंत्री को कुछ लेना-देना नहीं होता। बजट की कुल मिलाकर यही दास्तान है।

जो लोग बुद्धिजीवी हैं, और जिन्होंने बजट आने के पहले ही फ्रेंच कट दाढ़ी और सुनहरी फ्रेम का चश्मा बनवा लिया है, वे इतना उलझा हुआ वक्तव्य देते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि वे समर्थन में बोल रहे हैं या विरोध में! उन्हें सुनकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। हैरत में तो खुद विद्वान या फिर बुद्धिजीवी भी पड़ जाता है कि वह आखिर बोला तो क्या बोला। बाद में मित्रगण उसे बधाई देना शुरू कर देते हैं कि वाह सुलेखिया जी, आप बजट पर बहुत बढ़िया बोले।

बजट भले बढ़िया न हो, बोलना बढ़िया होना चाहिए। मैं खुद भी काफी समय से इस पर बोलने की तैयारी कर रहा हूं, ताकि अगले वर्ष से कुछ बोल सकूं।

ट्वीट-ट्वीट

33 वर्षीय दीवान शरीफ मुल्ला कर्नाटक के लिंगायत मठ में पुजारी बनने जा रहे हैं। वह बचपन से ही 12वीं सदी के महान समाज सुधारक बासवन्ना से प्रभावित हैं। सबकी अपनी आस्था है और ये विविधता ही भारतवर्ष की ताकत है।
समीर अब्बास@TheSamirAbbas

कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के हाथ से निकल जाए। यह बेतुकी चर्चा है। परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा सकता। केवल राहुल गांधी में यह क्षमता है। दूसरे नेता अपने-अपने धड़ों के नेता हैं, उन्हें कमान सौंपने से गुटबाजी ही बढ़ेगी।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

राजस्थान में दलित युवकों के साथ हुई दरिंदगी शर्मनाक है। वास्तव में जातिवाद भारत और हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। इससे पहले कि जाति व्यवस्था भारत को तबाह कर दे, हमें उसे ही तिलांजलि देनी होगी। इस संदर्भ में अफसोस की बात यह भी है कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा।
साध्वी खोसला@sadhavi

शाहीन बाग का मसला हल करने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। खासतौर से तीस्ता सीतलवाड़ की सक्रियता से यह बात और पुख्ता हो गई है जो अपने आप में झूठ और धोखाधड़ी का पुलिंदा हैं।
आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या कोरोना वायरस विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नया खतरा बन गया है?

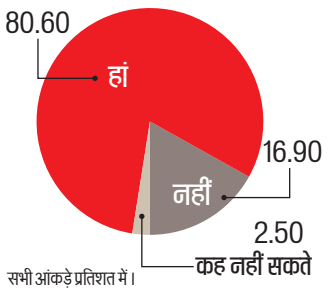

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाना सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

समझाने वो हैं गए या भड़काने आग,
नहीं समझ में आ रहा मध्यस्थों का राग।
मध्यस्थों का राग सुनें यदि उनकी भाषा,
तो जाती है टूट बंधी जो उनसे आशा।
जाय बाग शाहीन लगे उनके सुर गाने,
बने भीड़ में भीड़ गए थे जो समझाने!
– ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

बाबूलाल की वापसी और भाजपा की मजबूती

अंत भला तो सब भला। यह कहावत भाजपा और बाबूलाल मरांडी दोनों पर चरितार्थ हो रही है। चौदह वर्षों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की धूम-धड़ाके से भाजपा में वापसी हो गई। भाजपा और मरांडी को एक-दूसरे की कितनी जरूरत थी यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य (मैं 2014 से ही बाबूलाल जी को भाजपा में लाने का प्रयास कर रहा था) से बखूबी समझा जा सकता है। बाबूलाल ने भी स्वीकार किया, जिद्दी हूं, मैं ही अड़ा रहा, लेकिन अब वापस घर आकर अभिभूत हूं। दरअसल वर्ष 2014 में भाजपा ने रघुवर दास के रूप में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का प्रयोग जरूर किया था, लेकिन वह समझ रही थी कि बाबूलाल जैसा आदिवासी चेहरा चाहिए ही होगा जिसकी कोल्हान और संताल परगना सहित पूरे प्रदेश के आदिवासियों में स्वीकार्यता हो। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर भी पार्टी दांव खेल सकती थी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरण बाबूलाल मरांडी के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। खैर, लंबी कवायद के बाद यह मिलन हो गया और इसी के साथ प्रदेश में झाविमो इतिहास बन गया। दो अन्य निष्कासित विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की उसी दिन दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। सवाल उठ रहा है कि बाबूलाल पर दल-बदल कानून लागू होगा कि नहीं? लगता नहीं है, क्योंकि प्रदीप यादव व बंधु तिर्की के हाव-भाव बता रहे हैं कि अंदरखाने सबकुछ सहमति से हुआ है। विभानसभा चुनाव में झाविमो प्रत्याशियों का जो हश्र हुआ, उससे सभी ने अपने-अपने हिसाब से मोलभाव कर अपना-अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। हां, यह कहा जा सकता है कि राज्य की राजनीति में भाजपा में एक बार फिर से बाबूलाल युग शुरू हो चुका है। जल्द ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। भाजपा ने राज्य में मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए खुद को तैयार करना भी शुरू कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भाजपा में शामिल होते बाबूलाल मरांडी। फाइल

रांची में हुए विलय समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के प्रति नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा, 'बेशक भाजपा सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में रहते हुए जितना काम किया था उससे ज्यादा काम हम विपक्ष में रहते हुए करेंगे। जरूरत पड़ी तो सत्ता पक्ष के कान भी खीचेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इससे यह तय हो गया है कि बजट सत्र से ही सरकार को बाबूलाल के कड़े तेवर झेलने पड़ेंगे। हेमंत सरकार पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यकाल की कई योजनाएं बंद करने की तैयारी में है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है। इस योजना में हर वर्ष किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये (अधिकतम 25 हजार) दिए जा रहे हैं। चर्चा है कि सरकार इस योजना के बजाय किसी अन्य तरह से किसानों को यह धनराशि देने के बारे में सोच रही है। भाजपा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। भाजपा का संकट यह था उनके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था जिसकी बात आदिवासी से लेकर गैर आदिवासी तक सुनें। बाबूलाल मरांडी के आने से यह संकट खत्म हो गया है।

हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार अभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना सकी है। झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में तमाम बड़े वादे किए हैं। राजद के पास तो सिर्फ एक विधायक है, इसलिए उस पर बहुत दबाव नहीं है, लेकिन झामुमो और कांग्रेस दोनों ही पहले बजट में अपनी बड़ी योजनाओं को शामिल करना चाहेंगे। सरकार लगातार यह कह रही है कि राज्य का खजाना खाली है और यह संकेत भी दे रही है कि तमाम गैर जरूरी योजनाओं को बंद करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार पहले बजट में कुछ बड़ी योजनाएं लाकर अपने मतदाताओं को साधना चाहेगी। झामुमो ने हर गरीब परिवार को सालाना 72 हजार रुपये देने की घोषणा कर रखी है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को पांच से सात हजार रुपये मासिक भत्ता, दस रुपये में धोती-साड़ी योजना और सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की तरफ कदम बढ़ा सकती है। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी के प्रति संकल्पित है। देखना होगा यह कैसे होता है। सरकार सचेत भी होगी कि पूर्व की बड़ी योजनाएं बंद करने का जनता में कोई प्रतिकूल संदेश न जाए।

मातृभाषा दिवस

अपनी भाषा में हो आरंभिक शिक्षा

आज अभिभावक बच्चों को आरंभ से ही अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमारे सामने बड़ी संख्या में ऐसे महान व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हासिल की है

विवेक शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार

बेशक असली शिक्षा का आनंद आप तब ही पा सकते हैं, जब आपने कम से कम पांचवीं तक शिक्षा अपनी मातृभाषा में हासिल की हो। कई अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जो बच्चे मातृभाषा में स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक सीखते हैं। इसमें अंग्रेजी का विरोध नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। मसला यह है कि हम अपनी मातृभाषा, चाहे वह हिंदी हो या तमिल, बांग्ला या फिर कोई अन्य भाषा, इसमें प्राथमिक शिक्षा देने के संबंध में कब गंभीर होंगे? क्योंकि उसके बिना हम बच्चों को शिक्षा तो नहीं ही दे रहे हैं। हां, शिक्षा के नाम पर प्रमाणपत्र दे देते हैं। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। और बच्चे को ज्ञान कहां मिला? हम उन्हें नौकरी पाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे यहां पर दुर्भाग्यवश आज शिक्षा का अर्थ नौकरी पाने से अधिक नहीं है।

मातृभाषा के माध्यम से आगे बढ़ने वाले महान व्यक्तित्व : आपको जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने लिए खास जगह बनाने वाली अनेक हस्तियां मिल जाएंगी जिन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में ग्रहण की। इनमें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर बाबा साहेब आंबेडकर तक शामिल हैं। रवींद्रनाथ टैगोर की आरंभिक शिक्षा का श्रीगणेश उनके उत्तर कोलकाता (तब कलकत्ता) के घर में ही हुआ। उनके परिवार में बांग्ला भाषा ही बोली जाती थी। उन्होंने जिस स्कूल में दाखिला लिया, वहां पर भी पढ़ाई का माध्यम बांग्ला ही था यानी बंगाल की धरती की भाषा।

देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी। तब गांवों में अंग्रेजी का नामोनिशान नहीं था। उन्होंने स्कूल में हिंदी, संस्कृत और फारसी पढ़ी। अपनी उच्च शिक्षा उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से हासिल की थी। बाबा साहेब आंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा के एक सामान्य स्कूल में हुई थी। उस समय वहां पर पढ़ाई का माध्यम मराठी था। भारत की इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सक्रिय बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एवी नाईक का संबंध दक्षिण गुजरात से है। उनकी आरंभिक शिक्षा भी अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। वहां पर उन्होंने पांचवीं तक गुजराती, हिंदी और सामाजिक ज्ञान जैसे विषय पढ़े। अंग्रेजी से उनका संबंध स्थापित हुआ आठवीं कक्षा में आने के बाद।

आपको तमाम ऐसी नामवर हस्तियां मिल जाएंगी जिन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने के बाद अंग्रेजी या किसी अन्य विषय में महारत हासिल की। स्कूली शिक्षा में बच्चों को मातृभाषा से इतर किसी अन्य भाषा में पढ़ाना उनके साथ अन्याय करने के समान है। विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देना मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से वांछनीय है, क्योंकि विद्यालय आने पर बच्चे यदि अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो वे विद्यालय में आत्मीयता का अनुभव करने लगते हैं और यदि उन्हें सब कुछ उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए सारी चीजों को समझना आसान हो जाता है। इस स्थिति से देश के लाखों मासूम बच्चे गुजरते हैं। लाखों बच्चे ऐसे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो बच्चों पर कोई भाषा थोप देते हैं और उस भाषा की अनदेखी करते हैं जिसमें उन्होंने बोलना, अपने माता-पिता को संबोधित करना, पेड़-पौधों, फलों, फूलों, जानवरों, पर्यावरण और अपने परिवार तथा सदस्यों को जानना सीखा हो। किसी बच्चे की प्रारंभिक भाषा उसकी पहली पहचान की, उसके सभी शुरुआती अनुभवों और सीखों की, अपने दोस्तों व बड़ों के साथ उसके संबंधों और अपनी समझ और समाधानों को तलाशने की उसकी कोशिशों की भाषा होती है। यह भाषा उसके घर, परिवार और समुदाय के लिए पर्याप्त होती है, और वह उसे अपनी सामाजिक दुनिया के साथ तालमेल बनाकर चलने की ताकत देती है।

अंग्रेजी की मानसिकता से घिरा बड़ा वर्ग : एक तरह से देश के एक

बड़े वर्ग ने यह मान लिया है कि अंग्रेजी जाने-समझे बिना काम नहीं चलने वाला है। इसके चलते हर स्तर पर इसे बढ़ावा देने की मानसिकता नजर आती है। ये सोच घर कर गई है कि अंग्रेजी जाने बिना दुनिया अधूरी है। हां, कुछ हद तक ये दावा सही है। दरअसल आधे-अधूरे ज्ञान के बल पर भी बीपीओ में लाखों नौजवानों को नौकरी मिलने लगी है। इसका ही नतीजा है कि शहरी मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को कथित अंग्रेजी स्कूलों में भेजने पर खर्च करने लगा है। दरअसल माता-पिता अधीर रहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी से जल्दी अंग्रेजी जान लें। उन्हें अंग्रेजी सत्ता, प्रगति और आर्थिक अवसरों की भाषा प्रतीत होती है, और इसलिए लोगों को घरों में तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी लाने की सनक है। बहुत छोटे और मासूम तथा अविकसित बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की लालसा रहने लगी है। दरअसल अंग्रेजी के लिए यह मौजूदा पागलपन कोरी नासमझी है।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जापान का उदाहरण देकर समझाया था कि वहां जितनी उन्नति हुई है, वह वहां की अपनी भाषा जापानी के ही कारण है। जापान ने अपनी भाषा की क्षमता पर भरोसा किया और अंग्रेजी के प्रभुत्व से जापानी भाषा को बचाकर रखा। भारत के भी शिक्षाविदों और नीति निर्धारकों को समझ लेना चाहिए कि वे अंग्रेजी के पीछे नहीं भागें। भारत में हरेक बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही मिले। तभी ही बच्चे का समग्र मानसिक विकास मुमकिन होगा और संबंधित भाषा का अस्तित्व भी कायम रहेगा जिसका परिणाम लंबे समय बाद सामने आता है।

पंजाब

बेजा कवायद

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पांच सलाहकारों का नियुक्ति के पांच माह बाद ही अपने पदों से इस्तीफा देने पर मजबूर होना सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इससे यह साबित होता है कि सरकार ने इन सलाहकारों की नियुक्ति से पूर्व यथोचित विचार नहीं किया और जल्दबाजी में फैसला ले लिया। बिना सोच-विचार के किए कार्य किस प्रकार से नुकसानदेह साबित हो सकते हैं यह प्रकरण इसका अच्छा उदाहरण है। सरकार को अपना ध्यान राज्य के विकास पर केंद्रित करना चाहिए। तभी अगले चुनाव में उसकी वापसी का रास्ता खुलेगा। हालांकि उनकी नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल-2019 विधानसभा में लाकर इन विधायकों को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब फाइल राज्यपाल से मंजूर होकर आई ही नहीं थी तो इन्हें नियुक्त कर देने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी?

सभी को मालूम है कि इस तरह सलाहकारों की फौज खड़ी करने का मतलब सीधे-सीधे उन विधायकों को कोई पद एवं अहमियत देना है जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा सका या विभिन्न उपक्रमों का चेयरमैन इत्यादि नहीं बनाया जा सका। यह विधायकों को संतुष्ठ करने की एक कवायद प्रतीत होती है। राज्यपाल ने अगर इन सलाहकारों की आवश्यकता, इनकी योग्यता और वैधानिकता पर सवाल उठाया था तो पहले इन पहलुओं पर सरकार ने विचार क्यों नहीं किया? हर किसी के जहन में यह सवाल तो उठता ही है कि जिन क्षेत्रों में सलाह के लिए इन विधायकों को सलाहकार नियुक्त किया गया है, क्या ये उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं? अगर नहीं हैं तो फिर सलाह क्या देंगे? ऐसे फैसलों से ही सरकार की छवि अपनों को रेवड़ियां बांटने वाली की बनती है। उस स्थिति में यह गंवारा नहीं हो सकता जब राज्य घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हो और कई बार कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने के लिए भी पैसा नहीं होता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने सलाहकार पदों से इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और इंतजार करने को कहा है, इससे यही समझा जा सकता है कि अभी इन्हें इन पदों पर विराजमान रखने की बेजा कवायद जारी है।

> राज्यपाल ने अगर इन सलाहकारों की आवश्यकता, इनकी योग्यता और वैधानिकता पर सवाल उठाया था तो पहले इन पहलुओं पर सरकार ने विचार क्यों नहीं किया?

ऐसे समय में जब सरकार के सामने बिजली, बेरोजगारी, नशा, अवैध खनन जैसे मुद्दे मुंह बाये खड़े हों तो उसकी ऊर्जा इन पर खर्च होनी चाहिए न कि इस पर कि कैसे अपनी पार्टी के विधायकों को एडजस्ट किया जाए। राज्य की जनता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिन उम्मीदों की पूर्ति के लिए भारी मतों से सत्ता सौंपी थी उन्हें उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए पंजाब सरकार को सुशासन पर ध्यान देना चाहिए। उसे न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मंत्र को अपनाना चाहिए। इसी से तरक्की की राह खुलेगी। ऐसा करने के बजाय वह अपने विधायकों को एडजस्ट करने के तौर तरीके अपना रही है। इसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश

जल, जंगल और जमीन

जीवन के लिए जल, जंगल और जमीन जरूरी हैं। इसे हिमाचल प्रदेश ने खूब समझा है। सरकार के साथ-साथ यहां के लोगों ने भी इसे आत्मसात किया है। कई लोग धरा के प्रहरी पेड़ों के संरक्षण में जुटे हैं। इन्हीं लोगों में से एक हैं बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की पट्टा पंचायत के पूर्व सैनिक लाल सिंह। सेना में सेवाएं देने के बाद जब घर आए तो धरा के प्रहरी पेड़ों के लिए जुट गए। जुनून ऐसा था कि उन्होंने अपनी जमीन पर तो पौधे रोपे ही साथ लगती सरकारी बंजर जमीन पर चट्टानों को काटकर करीब ढाई किलोमीटर क्षेत्र में चंदन का जंगल खड़ा कर दिया। राज्य सरकार ने भी प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभी हरित आवरण करीब 28 फीसद है जबकि कभी राज्य में यह ज्यादा होता था। यह सुखद है कि राज्य में कुछ वर्षों से निरंतर हरित आवरण में वृद्धि हो रही है। हरित पट्टी का घनत्व बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास होने लगे हैं।

क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैंपा) फंड से भी हरियाली बढ़ेगी। 1660 करोड रुपये के कैंपा फंड के तहत पहले चरण की कार्ययोजना पर 157 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह भी सुखद है कि राज्य में कई संस्थाएं, स्कूली बच्चे भी पर्यावरण संरक्षण के तहत हर साल लाखों

> जंगल बचाना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी जरूरी है

प्रतीकात्मक फोटो

पौधे रोपते हैं। राज्य में लोगों ने विशेष अवसरों को यादगार बनाने के लिए उस दिन पौधे रोपने शुरू किए हैं। कई लोग पौधों को परिवार के सदस्य की तरह देखरेख कर रहे हैं। यह सही है कि विकास के लिए कई स्थानों पर पेड़ों को काटना पड़ता है, लेकिन एक पड़े के बदले पौधे लगाने का फैसला भी पर्यावरण संरक्षण में अहम कड़ी साबित हो रहा है। यह बात हर व्यक्ति को समझना होगी कि जंगल सिर्फ स्वच्छ वायु ही नहीं देते, बल्कि हमारी हर तरह की जरूरतों को पूरा करने में सहायक हैं। भूस्खलन रोकने के साथ-साथ वर्षा के लिए भी जंगल अहम हैं। जंगल हरे भरे रहें तो जंगली जानवर भी बस्तियों में दस्तक नहीं देंगे। कई तरह की बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी जंगलों के कारण ही सुरक्षित रह पाएंगी।

बहरहाल पेड़-पौधों और जंगलों को बचाने, संरक्षित करने और उसे बढ़ाने के काम में सरकार के साथ-साथ पर्यावरणविद भी पहले से ही लगे हुए हैं। नागरिक समाज भी बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर सभी लोग एक साथ मिल कर काम करें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें पर्याप्त मात्रा में वन, हरियाली के साथ-साथ स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा जहां हम खुल कर सांस ले सकेंगे। इसमें सरकार, राजनीतिक दलों, नागरिकों, मीडिया और वन एवं पर्यावरण विशेषज्ञों की महती और विशेष भूमिका है। हमें समझना पड़ेगा कि इस मामले में उदासीनता आत्मघाती हो सकती है और दोषारोपन बेमानी। ऐसे मामले में केंद्र सरकार को जंगल के स्थायी विकास के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग, राज्य सरकार और केंद्रीय समितियों एवं इससे संबद्ध मंत्रालयों को समयबद्ध कार्रवाई की जिम्मेदारी देनी चाहिए।

बंगाल

मौत पर सियासत

बांग्ला फिल्मों के अभिनेता और पूर्व तृणमूल सांसद तापस पाल की मौत पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने तापस की मौत के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। इधर बंगाल भाजपा के नेताओं ने ममता को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि तापस की मौत पर वह राजनीति कर रही हैं। 61 वर्षीय तापस पाल का मंगलवार को सुबह निधन हो गया। वह अपनी बेटी से मिलने मुंबई गए थे और कोलकाता वापस लौटते समय मुंबई हवाई अड्डे पर उन्हें सीने में दर्द हुआ। जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सुबह चार बजे उनका निधन हो गया।

ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने तापस का जमकर उत्पीड़न किया। उन्हें 13 माह जेल में रखा गया और यह भी नहीं साफ हो सका कि उनका गुनाह क्या था। भाजपा भी ममता को कठघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं रही। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सवाल उठाया कि ममता ने भुवनेश्वर

अभिनेता और पूर्व तृणमूल सांसद तापस पाल।

के एक अस्पताल में भर्ती सुदीप बंद्योपाध्याय से मुलाकात कीं, लेकिन बगल के कमरे में भर्ती तापस पाल से मिलना भी उचित नहीं समझा। भाजपा नेताओं का कहना है कि तापस जीवित थे तो ममता ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली और अब मौत पर राजनीति कर रही हैं। तापस को रोजवैली चिटफंड घोटाले में सीबीआइ ने वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया था और करीब 13 माह बाद उन्हें अदालत से जमानत मिली थी। कानूनी दांव-पेच का सच तो अदालत तय करेगी, लेकिन इस बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह बंगाल की कला और संस्कृति जगत के एक धरोहर थे। उनकी मौत निश्चित रूप से दुखदाई है। जमानत पर छूटने के बाद तापस ने राजनीति और फिल्म जगत से दूरी बना ली थी।

1981 में साहेब फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले तापस पाल की अनेक यादगार फिल्में हैं। वह बंगाल राज्य की तरफ से 2012 में विशेष चलचित्र पुरस्कार भी पा चुके थे। परबत पिया, भालोबासा-भालोबासा जैसी कई हिट फिल्मों के नायक रहे तापस पाल ने सिनेमा जगत को अप्रतिम योगदान दिया है। वह माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध के भी नायक थे। निःसंदेह उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। ऐसे कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर उनकी कला को याद करें। आरोप-प्रत्यारोप के बीच उनकी आत्मा को कष्ट ही मिलेगा।

उत्तराखंड

कार्यशैली में बदलाव

प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार अगले महीने तीन साल का कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों के साथ अब तक के कार्यकाल की समीक्षा की। इसके बाद से सरकार की कार्यशैली में बदलाव साफ नजर आ रहा है। खास तौर पर जिस तरह अब सरकार ने आम जनता के नजदीक जाने की पहल की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्थित कार्यालय में सप्ताह के दो दिन बैठना शुरू कर दिया है। तय किया गया है कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्री बुधवार और गुरुवार के दिन विधानसभा स्थित अपने कार्यालयों में आम जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

दरअसल मुख्यमंत्री सामान्यतया सचिवालय या फिर आवास से ही दैनिक कार्य संपादित करते हैं। राजधानी में होने की स्थिति में मंत्री भी विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता कि सभी मंत्री एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। सचिवालय की अपेक्षा विधानसभा स्थित कार्यालयों तक आम जनता की पहुंच ज्यादा आसान है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस आशय का फैसला लिया। इस फैसले के गहरे निहितार्थ भी हैं। अब अगले विधानसभा चुनाव में महज दो साल का ही वक्त शेष है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद हुए चार विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पार्टी तीन-चौथाई से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में आई। भाजपा को 70 सदस्यीय विधानसभा में 57 सीटें हासिल हुईं। भारी भरकम बहुमत के कारण जनता की सरकार से अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों से इतर मौजूदा सरकार बगैर किसी बाहरी दबाव के काम करने में सक्षम है।

> मुख्यमंत्री और मंत्रियों की विधानसभा में उपलब्धता सुनिश्चित कर सरकार ने आम जनता के नजदीक जाने की जो पहल की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए

पिछले तीन सालों के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम विकास योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास अब दो ही साल का समय शेष है। यही स्थिति केंद्र की प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की भी है। हालांकि तीन साल की अवधि में मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 57 फीसद का पूरा हो जाना संतोषजनक आंकड़ा कहा जा सकता है। इसके अलावा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक अटल आयुष्मान योजना की कामयाबी और दो हजार किमी से ज्यादा लंबाई की सड़कों के निर्माण के साथ ही 205 पुलों का निर्माण कर 353 गांवों तक सड़क पहुंचाने की उपलब्धि भी हासिल की गई है। अधिकांश महकमों के कामकाज संतोषजनक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें सुधार की गुंजाइश भी है। साफ है कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्री आम जनता तथा विधायकों के साथ सीधा संवाद कायम करते हैं तो इससे उन्हें सरकार के कार्यों को लेकर फीडबैक भी आसानी से मिल सकता है। साथ ही इससे संवादहीनता की स्थिति पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि अभी इस व्यवस्था की शुरुआत ही हो रही है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी मंत्री इसे गंभीरता से लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ही मुख्यमंत्री की अच्छी मंशा से की गई पहल धरातल पर उतर पाएगी।

झरने के नीचे विराजमान शिव, होता सतत जलाभिषेक

हर हर महादेव... ▶ 'बाहुबली' भीम ने झरने के नीचे स्थापित किया था शिवलिंग, जिस पर गिरती रहती है जलधारा

21 फरवरी महाशिवरात्रि पर विशेष

अजय तिवारी, नीमच

मान्यता है कि यहां अज्ञातवास के दौरान 'बाहुबली' भीम ने ऊंचे झरने के नीचे विशाल शिवलिंग स्थापित किया था। सूखा पड़ा हो या अकाल, शिवलिंग पर जलधारा का गिरना कभी नहीं थमा। प्रकृति के द्वारा शिव के जलाभिषेक का यह क्रम निरंतर बना हुआ है। मध्यप्रदेश के नीमच में घने पहाड़ी जंगलों के बीच मौजूद प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर का यह अद्भुत दृश्य मनमोह लेता है। यह दृश्य और इसके पीछे का इतिहास सुनकर फिल्म 'बाहुबली' का वह दृश्य ताजा हो जाता है, जिसमें बाहुबली को झरने के नीचे शिवलिंग स्थापित करते हुए दिखाया गया। हालांकि वह कृत्रिम झरना था, लेकिन यहां तो सबकुछ असली है।

मंदिर के पुजारी ने बताया, केदारेश्वर में पांडवों ने अज्ञातवाश का समय बिताया था। अज्ञातवाश के दौरान ही इस स्थान पर महाबली भीम ने शिवलिंग स्थापित किया। इसी स्थान पर द्रोपदी ने नाग चंपा के 11 पौधे लगाए थे। 2011 में पहाड़ का हिस्सा गिरने से नाग चंपा के पौधे नष्ट हो गए। प्रकृति की गोद में स्थित मंदिर में आस-पास के लोग दर्शन व पूजन के लिए आते हैं। हालांकि जंगल और वीरान क्षेत्र होने से यहां आवाजाही कम होती है।

जिला मुख्यालय से 75 किमी दूर रामपुरा व गांधीसागर के बीच केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। यह तहसील रामपुरा से 12 और ग्राम पंचायत सालरमाला से करीब 3 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां अब मंदिर बन चुका है, लेकिन प्राकृतिक झरने से मंदिर में शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से अनवरत जलाभिषेक होता है। पुजारी गिरधारी नाथ योगी ने बताया कि 1956 में अकाल के हालात बने थे, लेकिन इस दौरान भी मंदिर में भगवान का जलाभिषेक प्राकृतिक रूप से होता रहा है। महाशिवरात्रि पर करीब 5 हजार भक्त यहां जुटते हैं। रामपुरा और आसपास का क्षेत्र पूर्व में होल्कर रियासत के अधीन रहा। केदारेश्वर के प्रति अहिल्या देवी होल्कर की अगाध आस्था रही। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्मशालाओं का निर्माण कराया।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

अद्भुत...

- मध्यप्रदेश के नीमच में है महाभारतकालीन प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर, अद्भुत है दृश्य
- जंगल और वीरान क्षेत्र में होने से भक्तों की आवाजाही कम
- मान्यता- पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास, भीम ने स्थापित किया था शिवलिंग

रामपुरा के नजदीक स्थित प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर। नईदुनिया

1100 साल पुराने शिवलिंग में 1008 शिवलिंग के दर्शन

विवेक पाराशर, बड़वानी : मप्र के बड़वानी जिले के निवाली स्थित ग्राम वझर में 1100 साल पुराना साढ़े तीन फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिस पर छोटे-छोटे 1008 शिवलिंग भी बने हुए हैं। जानकारों के अनुसार शिवलिंग का निर्माण परमारकालीन राजाओं द्वारा कराया गया था। देशभर में 'सहस्त्र शिवलिंग' की संख्या दो या तीन ही है। राजस्थान के कोटा में 11 फीट ऊंचा सहस्त्र शिवलिंग स्थापित है। हालांकि वझर स्थित सहस्त्र शिवलिंग सबसे प्राचीन है। यह एक पड़े की छाया में स्थापित है। समीप ही नंदी भगवान की विशाल प्रतिमा भी है। हनुमान मंदिर निर्माण के दौरान की गई खोदाई में यहां बड़ी संख्या में प्राचीन प्रतिमाएं पाई गई थीं। जो इंदौर स्थित केंद्रीय संग्रहालय में संरक्षित हैं।

पेड़ के नीचे स्थापित है 'सहस्त्र शिवलिंग' प्रतिमा। नईदुनिया

जल घड़ी बताती थी महाकाल के पूजन का समय

राजेश वर्मा, उज्जैन : ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की परंपराएं जितनी पुरातन हैं, इनके निर्वहन का इतिहास भी उतना ही पुराना है। करीब आधी शताब्दी पूर्व महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल के चार प्रहर की पूजा का समय जल घड़ी के अनुसार तय होता था। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पं.आनंदशंकर व्यास ने बताया महाशिवरात्रि पर महाकाल की चार प्रहर की पूजा होती है। 50 साल पहले तक मंदिर में जल घड़ी का उपयोग किया जाता था। विशेषज्ञ जल घड़ी से समय की गणना करते थे तथा घंटा बजाकर इसकी सूचना देते थे। पं. व्यास के अनुसार 24 मिनट की एक घटी होती है। ढाई घटी का एक घंटा तथा साठ घटी का दिन रात होता है। इसी गणना के आधार पर एक घंटा पूरा होने पर घंटा बजाया जाता था। पुजारी इसके अनुसार महाअभिषेक पूजन का क्रम निर्धारित करते थे। जल घड़ी निर्माण की अपनी विशिष्ट कला होती थी। इसके लिए एक बड़े जलपात्र में पानी भरा जाता था। उसमें एक कटोरा डाला जाता था, जिसके नीचे छिद्र होता था। इस छिद्र के माध्यम से पानी जब कटोरे में भरने लगता था। उसी के अनुसार समय की गणना होती थी।

जलघड़ी का फाइल फोटो। नईदुनिया

भगवान शिव की आराधना एवं उनके अभिषेक का पर्व है महाशिवरात्रि

भगवान शंकर के शिवलिंग स्वरूप में प्रकट होने और शिव-शक्ति के महामिलन के उत्सव का दिन है महाशिवरात्रि। इस अवसर पर हर कोई अपनी भक्ति से मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मोक्ष का मार्ग भी पा लेना चाहता है। इस महाशिवरात्रि पर जानें- शिव पूजा का मुहूर्त, दुर्लभ मणिकांचन योग, पूजा सामग्री, पूजा विधि.

देखें मंत्र एवं महाशिवरात्रि कथा एक नये अंदाज में ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

कश्मीर में किन्नरों के लिए मसीहा हैं डॉ. एजाज बंड

प्रयास ▶ कट्टरपंथ और आतंकवाद के दौर में कश्मीर में किन्नरों का भी हुआ कत्लेआम, तब मसीहा बन सामने आए डॉ. बंड

नवीन नवाज, श्रीनगर

कट्टरपंथ के दिनों में कश्मीर में ट्रांसजेंडर्स (किन्नरों) का भी कत्लेआम हुआ। इनके कार्य को धर्मविरुद्ध करार दिया गया। समाज ने इन्हें धिक्कारा और मरने के लिए छोड़ दिया। डॉ. एजाज अहमद बंड तब इनके लिए मसीहा बनकर सामने आए। यह वर्ग अब राहत की सांस ले रहा है। स्थिति सुधरने लगी है।

जनसंख्या नियोजन

कश्मीर में ट्रांसजेंडर वर्ग अब हंसी का पात्र नहीं रह गया है। डॉ. बंड इस वर्ग के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अदालत में उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले डॉ. बंड का यह प्रयास इसलिए अहम है क्योंकि इससे स्थानीय समाज ने इस वर्ग को हिकारत की नजर से देखना छोड़ दिया है और इसे लेकर संवेदना बढ़ी है। जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ तो कई जिहादी तत्वों ने ट्रांसजेंडर्स का कत्ल भी किया क्योंकि वह इन्हें काफिर कहते थे। डॉ. बंड किन्नरों के हक के लिए संघर्षरत हैं। उनके प्रयास से कश्मीर विवि में सोशल साइंस विभाग ने ट्रांसजेंडरों केबारे में शोध की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी वह इनके अधिकारों की बहाली के लिए पहुंचे। राज्य मानवाधिकार आयोग का भी दरवाजा खटखटाया। नतीजन अब इस वर्ग की स्वीकार्यता बढ़ने लगी है।

डॉ. बंड बताते हैं, यहां इनकी संख्या का स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह लोग सम्मानजनक जिंदगी जिएं। हमने सोंजल नामक संस्था बनाई है, जो लगातार इनके लिए काम कर रही है। बंड ने कहा, शुरू में कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उलाहने मिले, लेकिन मैं ठान चुका था। कश्मीर के हिजड़े नामक किताब लिख चुके डॉ. बंड ने कहा कि मेरी बहन के रिश्ते की बात चल रही थी। मेरी एक किन्नर से मुलाकात हुई क्योंकि कश्मीर में किन्नरों के पास यही एक काम है- किसी शादी में नाच-गाना। बातचीत के

डॉ. एजाज अहमद बंड की फाइल फोटो। जागरण

दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेकअप के पीछे जो चेहरा है, वह पूरी तरह से मायूस है। मैंने इन लोगों से मिलना शुरू किया। इन्हें आपस में जोड़ना और इनके लिए रोजगार के अवसर तलाशना शुरू किए। कई दर्दनाक कहानियां सुनने को भी मिली।

यह लोग सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और भावानात्मक रूप से पूरी तरह शोषित होते हैं। जिससे मिला, उसने ही एक दर्दभरी दास्तां सुनाई। इनमें अधिकांश दयनीय हालात में ही रहते हैं। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी लाश तक उठाने वाला कोई नहीं मिलता। कोई उन्हें दफनाने के लिए नहीं आता। डॉ. एजाज ने कहा कि हमने कुछ वर्षों के दौरान यहां कई सेमीनार, सभाएं और बैठकें कीं। कश्मीर की सिविल सोसायटी को जोड़ा। किन्नर समुदाय के मुद्दों को उठाया। आज कई जगह किन्नर समुदाय के लोगों की प्रतिभा को लोग यहां स्वीकारते हैं। वह उन्हें अब उपहास और तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते। हमारी संस्था उनके लिए ब्यूटिशियन, सिलाई-कढ़ाई समेत विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाने व उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास करती है। हमारा प्रयास है कि स्कूल-कॉलेजों में इनकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न हो, सरकारी रोजगार में इन्हें हिस्सा मिले।

इस्लाम में किन्नर समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इस्लाम की गलत व्याख्या के आधार पर ही इन्हें निशाना बनाया है। किन्नर तो हमेशा से समाज के प्रत्येक वर्ग में रहे हैं। किसी के साथ लैंगिक आधार पर पक्षपात, हिंसा की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है। इस्लाम में इस समुदाय का स्पष्ट उल्लेख है। इन्हें मकहान्नथुन कहा है। इन्हें इस्लाम के मुताबिक कई अधिकार प्राप्त हैं। इनका अपने परिवार की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। अगर कोई किन्नर महिलाओं की तरह ज्यादा है तो उसे पुश्तैनी संपत्ति में महिलाओं को दिए जाने वाले हक के समान ही हक होगा और अगर वह किसी मर्द की तरह है तो उसे मर्द के लिए तय हिस्से के मुताबिक ही हिस्सा मिलेगा। कश्मीर में इन लोगों को यह हक भी नहीं मिल रहा था।

डॉ. एजाज बंड ने कहा कि आज हमारे साथ करीब 300 लोग जुड़ चुके हैं। किन्नर समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में सरकार अपने बजट में इन लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान करे। इनके सामाजिक सरोकारों के संरक्षण की कोई नीति बने।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पहले व्यावसायिक सफर पर रवाना हुई काशी-महाकाल एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, वाराणसी : काशी-महाकाल हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का व्यावसायिक सफर गुरुवार से शुरू हो गया। चंदन का टीका लगाकर और पुष्प वर्षा कर रेल कर्मियों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। सफर के दौरान यात्रियों को गिफ्ट के तौर पर आइआरसीटीसी ने छाता दिया, इस पर स्वच्छता का संदेश लिखा था। उद्घाटन सफर में बोगी-5 के बर्थ संख्या 64 पर स्थापित किया गया अस्थाई मंदिर अब यहां से हट गया है। रेल कर्मचारियों ने अब पेंट्रीकार में पूजा स्थल बनाया है। यात्रा शुरू होने से पहले यहां पूजा-पाठ किया गया। रेल कर्मियों ने बताया कि पेंट्रीकार में एक स्थान पर स्थाई तौर पर देवी-देवताओं के चित्र लगाए गए हैं। दोपहर 2:45 बजे ट्रेन प्लेटफार्म नंबर सात से रवाना हुई। इस दौरान सभी ने हर-हर महादेव का उद्घोष किया। ट्रेन को गुब्बारों व फूलों से सजाया गया था। रवानगी से एक घंटे पहले ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई थी। राजस्थानी परिधान में आइआरसीटीसी कर्मियों ने सभी का स्वागत किया।

दैनिक जागरण
सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 फरवरी, 2020

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

इस बार यहां चलें

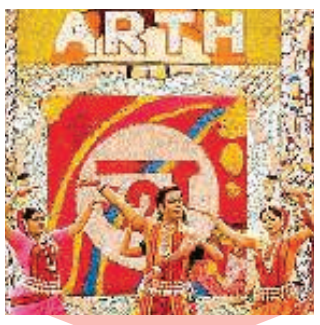

नए भारत की खोज

दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर अर्थ द कल्चर फेस्ट हाजिर है। देशभर के 200 से अधिक कलाकार, लेखक एवं कला व संस्कृति से जुड़े लोग समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखेंगे। उत्सव का उद्देश्य कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीति और समाज के माध्यम से एक बार फिर भारत की फिर खोज करना है।

- **आयोजन** : अर्थ-अ कल्चर फेस्ट।
- **कहां** : जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली। • **कब** : 21 से 23 फरवरी, सुबह दस बजे से। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

कल्पना की उड़ान

प्रसिद्ध कलाकार एवं क्यूरेटर अमृता प्रकाश एक बार फिर कलर स्पेक्ट्रा के पांचवे सीजन के साथ हाजिर है। इस बार 21 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। कैनवस पर इन्होंने अपनी कल्पनाओं और संवेदनाओं को रंगों के जरिये आकार दिया है।

- **आयोजन** : कलर स्पेक्ट्रा-5 • **कहां** : लोकायत आर्ट गैलरी, हौजखास गांव, नई दिल्ली। • **कब** : 20 से 23 फरवरी, सुबह दस से शाम सात बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

हो जाएंगे लोटपोट

ऑफिस और घर की आपाधापी के बीच सप्ताहांत हंसी के ठहाकों संग बिताना चाहते हैं तो फेस्टिवल ऑफ कॉमेडी जरूर जाएं। फेस्टिवल में पाकिस्तान और अल्जाइमर, अकबर द ग्रेट नहीं रहे, गालिब इन न्यू दिल्ली सरीखे नाटक दिखाए जाएंगे।

- **आयोजन** : फेस्टिवल ऑफ कॉमेडी।
- **कहां** : श्रीराम सेंटर फॉर आर्टस, नई दिल्ली। • **कब** : 28 फरवरी से 1 मार्च तक। शाम साढ़े सात बजे।
- **प्रवेश** : टिकट 100 से 1000 रुपये तक। ऑनलाइन बुकिंग द्वारा।

रंग बिना जीवन कहां

रंगों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती! एक कलाकार अपनी कलाकृति में जब विविध रंगों का प्रयोग करता है तो वह अपनी सोच को दर्शाता है। इसमें पेंटिंग्स, मूर्ति कला, क्राफ्ट वर्क, फोटोग्राफी इत्यादि प्रदर्शित की जाएंगी।

- **आयोजन** : कलर्स ऑफ इंडिया।
- **कहां** : ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी, रफी मार्ग, नई दिल्ली। • **कब** : 28 फरवरी से 5 मार्च तक, सुबह दस से शाम सात बजे तक। • **प्रवेश** : निश्शुल्क।

बातचीत

दर्शकों का व्यवहार बढ़ाता है हौसला

महज नौ वर्ष की उम्र में उस्ताद उस्मान खान की आवाज पहली बार रेडियो के माध्यम से दर्शकों तक पहुंची। इसके बाद तो...एक के बाद एक प्रस्तुतियों का सिलसिला चलता रहा। भारतीय संगीत प्रेमी तो इनके प्रशंसक हैं ही विदेशी दर्शक भी इनकी प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। प्राचीन कला केंद्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वे दिल्ली आ रहे हैं। कार्यक्रम समेत दिल्ली से जुड़ी यादों को लेकर उस्मान खान से संजीव कुमार मिश्र ने बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश :

सितार के तारों को जब उस्ताद उस्मान खान झंकृत करते हैं तो दर्शक मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं • फाइल फोटो

• छोटी सी उम्र में जब पहली प्रस्तुति दी तो कैसी प्रतिक्रिया मिली थी?

जब नौ साल का था तब पहली बार मैंने रोटरी क्लब द्वारा धारवाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम और फिर रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। रेडियो पर प्रस्तुति के लिए निदेशक ने मुझसे परंपरागत वस्त्र पहनकर आने को कहा था। मुझे आज भी याद है उस कार्यक्रम में मैं पगड़ी बांधकर पहुंचा था। कार्यक्रम के बाद काफी तारीफ हुई फिर मेरी खूब फोटो खींची गई। जो उस समय प्रकाशित होने वाली इंडियन लिसनर में छपी थी। तब मुझे युवा सितारवादक कहकर संबोधित किया गया था।

• दिल्ली में पहली प्रस्तुति कब हुई थी? किस तरह की यादें जुड़ी हैं?

जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तब मेरी उम्र करीब 20 साल थी। यह महाराष्ट्र सदन में गणेश उत्सव का कार्यक्रम था। तबले पर मेरे साथ लतीफ अहमद थे। दिल्ली आने के पहले मैंने सुना था कि दिल्ली में अच्छे ऑडियंस नहीं मिलेंगे? लेकिन जब मैं यहां आया तो देखा हॉल खचाखच भरा था। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों का व्यवहार दिल को छू गया। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। इससे आनंद भी मिला और हौसला भी बढ़ा।

• बीस साल की उम्र में पहली प्रस्तुति के बाद से आप लगातार दिल्ली आते रहे हैं? दर्शकों के व्यवहार में कितना फर्क आया है?

यहां दो तरह के हॉल में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बड़े ऑडिटोरियम में दर्शकों एवं कलाकारों के बीच फासला ज्यादा होता है। इसलिए बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता, जबकि छोटे हॉल में यह संज्ञान में आ जाता है, क्योंकि दर्शक बहुत पास ही बैठे होते हैं। कार्यक्रमों में कई बार दर्शकों के व्यवहार से कलाकारों को तकलीफ भी होती है। कभी उनका मोबाइल बजने लगता है तो कभी दर्शक बीच में ही उठकर चले जाते हैं। दर्शकों के इस व्यवहार से कलाकार की एकाग्रता भी प्रभावित होती है।

• दिल्ली में प्रस्तुति के दौरान कोई ऐसा यादगार अनुभव जो साझा करना चाहेंगे?

कुछ साल पहले की बात है। मेरी प्रस्तुति खत्म ही हुई थी कि दो लोग मुझसे मिलने आए। नाम तो ठीक से याद नहीं, उनमें से एक शख्स ने अपना परिचय आर्ट क्रिटिक के रूप में दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यह सोचकर आया था कि कलाकार रविशंकर या फिर विलायत खां स्टाइल में प्रस्तुति देगा। लेकिन यकीन मानिए आपकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग एवं दिल को छू जाने वाली थी। जब दर्शक इस तरह की बातें कहते हैं तो खुशी मिलती है।

• शास्त्रीय संगीत में हाल के वर्षों में किस तरह के बदलाव हुए हैं। इन्हें आप किस तरह देखते हैं?

प्रस्तुति के सिलसिले में मैं वर्ष 1970 से विदेश जाता रहा हूं। अमेरिका, यूरोप, जापान, दुबई, बहरीन, मस्कट समेत कई अन्य देशों में जाता रहता हूं। अब अगर मैं यह कहूं कि इन देशों में मैं घूमता हूं तो यह बेमानी होगी। दरअसल, एक सितार वादक होने की वजह से मुझे इन देशों में बुलाया जाता है। यह हमारे संगीत की महानता है। शास्त्रीय संगीत की आज पूरी दुनिया में पूछ हो रही है। पूरी दुनिया उसे सुनना चाहती है, इसलिए हमें बुलाया जाता है। हां, एक बात जरूरत कहना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के कलाकार नए-नए प्रयोग करते रहते हैं। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रयोग के चक्कर में शास्त्रीय संगीत की शुद्धता को कोई नुकसान ना हो जाए। यह मुझे उदास करता है।

20

साल की उम्र में दिल्ली में पहली बार महाराष्ट्र सदन में गणेश उत्सव के दौरान दी थी प्रस्तुति

- **आयोजन** : नक्षत्र सम्मान समारोह
- **कहां** : प्राचीन कला केंद्र द्वारा त्रिवेणी कला संगम, मंडी हाउस
- **कब** : रविवार 23 फरवरी, शाम 6 बजे।

• प्राचीन कला केंद्र द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर उस्ताद रफीउद्दीन साबरी होंगे। तबले और सितार के तालमेल पर क्या कहेंगे?

तबले की संगत होती है तबले की ताल, जबकि सितार की संगत राग और ये दोनों जब मिलते हैं और उससे जो संगीत की रस धारा बहती है वह दर्शकों के दिल को सुकून देती है। साबरी के साथ मैं पहली बार मंच साझा करूंगा, लेकिन यकीनन दर्शकों को संगीत का भरपूर आनंद मिलेगा

जश्न-ए-हिंद

महफिल एक, रंग अनेक

सुर...संगीत...गजल...गुरबाणी...मुशायरा...कव्वाली...भजन...ओपन-माइक...यानी महफिल एक...रंग अनेक। आयोजन है जश्न-ए-हिंद...जहां देश भक्ति के तराने छिड़ने तो लाजमी हैं ही और जब साथ में शास्त्रीय-कला-संस्कृति के दिग्गज इस उत्सव में आएंगे तो इस जश्न की सांझ बेमिसाल होगी ही। शुक्रवार से शुरू हो रहे इस तीन दिवसीय उत्सव में आर्मी बैंड भी होगा और पंडित बिरजू महाराज, शम्सुर्रहमान फारुकी सरीखे वरिष्ठ कलाकार भी। आयोजन करा रही संस्था साक्षी की अध्यक्ष मृदुला टंडन बताती हैं कि बरेली के इलियास अली दिल्ली में पहली बार प्रस्तुति देंगे। इलियास की रामायण पर आधारित नज्म बेमिसाल हैं। सुनकर रोम-रोम पुलकित हो जाता है। बताती हैं कि एक वीडियो फेसबुक पर देखी थी। कई दिनों तक तलाश के बाद पता चला कि इलियास बरेली के हैं। किसी तरह संपर्क हुआ। उन्हें दिल्ली में प्रस्तुति के बारे में बताया तो पहले पहल तो यह कहकर मना कर दिए कि मैं खाली नहीं हूं। लेकिन जब हम इनसे मिले तो इन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि, दिल्ली बहुत बड़ी है, मैं गुम हो जाउंगा। यदि कोई साथ चले तभी मैं आउंगा। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने आना स्वीकार किया।

जश्न ए हिंद कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा कुछ ऐसी की प्रस्तुति देख पाएंगे • फाइल फोटो

पुरानी दिल्ली की रंगत : उत्सव में पुरानी दिल्ली की रंगत भी दिखेगी। दरअसल उर्दू के प्रसिद्ध लेखक शम्सुर्रहमान फारुकी इसमें शिरकत कर रहे हैं। उनकी किताब 'कई चांद थे सरे आसमान में' बड़ी खूबसूरती से पुरानी दिल्ली के इतिहास को पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। यही खुला आसमान, चांदनी, महल, पुरानी दिल्ली की कला एवं संस्कृति दिखेगी। तकरीबन 750 पृष्ठों में शम्सुर्रहमान फारुकी ने कमाल की किस्सागोई की है। मिटती बादशाहत के साए में समाज और उसके शायर एवं फनकार जीव के बदलते चेहरों को जिस करीने से शम्सुर्रहमान ने उकेरा है, वाकई लाजवाब है। ऐसे ही इंसान के मन में उगने वाले बीज आंखों को भी भाता है और सपनों में चढ़ दिल में भी उतरता है।

कलाकारों का कवि रूप : शायर, कहानीकार, थियेटर कलाकारों को उनकी कृतियों के अतिरिक्त हम उनके पेशे से पहचानते हैं। मसलन, शोभना नारायन नृत्यांगना है। रमा पांडेय थियेटर कलाकार हैं। लेकिन अपनी कला को समृद्ध करती इन शख्सियतों के दिल में कवि भी बसता है। जो इन्हें कविताएं लिखने को प्रेरित करता है। प्रसिद्ध शख्सियतों को मंच पर कविता पाठ करते देखना दिलचस्प होगा।

संजीव कुमार मिश्र

खास आकर्षण

- आर्मी बैंड की प्रस्तुति
- शकील अहमद की गजल प्रस्तुति।
- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दास्तानगोई की प्रस्तुति।
- दिव्यांग बच्चों की प्रस्तुति।
- प्रतिदिन भजन, सूफी एवं गुरबाणी की प्रस्तुति।

- आयोजन : जश्न-ए-हिंद
- कहां : आइजीएनसीए, जनपथ।
- कब : 21 से 23 फरवरी तक, शाम चार से रात साढ़े आठ बजे तक। बाकि 22 एवं 23 को सुबह दस बजे से।
- प्रवेश : निश्शुल्क।
- नजदीकी मेट्रो स्टेशन : केंद्रीय सचिवालय।

जायका

रिफ्रेश कर देगा 'इंडियन पंच'

इंडियन पंच का स्वाद कभी लिया है। आप सोच रहे होंगे पंच का स्वाद... लेकिन ऐसा ही है। वह भी मसालेदार चाय, फलों के रस, गुलाब की पंखुड़ी, ड्राई फ्रूट्स की ताजगी से भरपूर पंच। जब आप ग्रेटर नोएडा स्थित क्राउन प्लाजा के स्पाइस आर्ट रेस्त्रां में पहुंचेंगे तो आपका स्वागत इसी ड्रिंक से होगा, जिसे पीते ही पल भर में सारी थकान गायब हो जाती है। उम्दा कलाकार द्वारा पसंदीदा गजलों की प्रस्तुति, खूबसूरत इंटीरियर और मध्यम रोशनी के बीच शेफ हरदेव सिंह द्वारा तैयार नार्थ इंडियन जायकों की लजीजियत ऐसी कि यादगार शाम कभी भूल नहीं पाएंगे।

सीक्रेट मसालों वाला गलौटी कबाब : यहां के गलौटी कबाब का स्वाद जितना उम्दा है, बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। मटन को करीब छह बार मशीन से निकालने के बाद कीमे में गलावट के लिए दो चम्मच कच्चा पपीता पेस्ट मिलाते हैं। फिर उसमें घी, अदरक-लहसुन पेस्ट, जावित्री, लाल मिर्च पाउडर, खस की जड़ पाउडर, नमक समेत दर्जनों सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं। उन सब को अच्छी तरह मिलाने के बाद एक दिन के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। पैन में थोड़ा घी डालकर कीमे का टिक्का बनाते हैं। गरमागरम रोटी या नान के साथ परोसा जाता है।

शेफ हरदेव सिंह • जागरण

गोश्त कोरमा लज्जत-ए-ताम: यह बेसिकली कोरमा है। लज्जत-ए-ताम का मतलब पोटली मसाला है, जिसमें कुछ स्वीट मसाले जैसे अश्वगंधा, मुलेठी, इलायची, पान की जड़, खस की जड़, बाहुबीर का मिश्रण होता है। इससे कोरमा स्पाइसी नहीं लगेगा, लेकिन फ्लेवर का भरपूर आनंद ले पाएंगे। इसमें मखाने का भी इस्तेमाल होता है ताकि ग्रेवी का कलर चेंज न हो। इसे पुलाव, राइस, ब्रेड, बादामी रोटी के साथ खा सकते हैं।

भूल नहीं पाएंगे दो दिन की दाल का स्वाद : अगर आप वेज खाने के शौकीन हैं तो काजू की गलावट, लहसुनी पालक, दाल-ए-खास, दो दिन की दाल, सब्ज बिरयानी, मकई मेथी पालक टिक्का ट्राई कर सकते हैं। हर स्वाद लाजवाब है। इन सब में दो दिन की दाल बेहद खास है। जिसे रेस्त्रां में आने वाला हर व्यक्ति एक बार जरूर चखना चाहता है। दो दिन की दाल नाम ही अपने आप में खास है। दरअसल दाल तैयार करने की प्रक्रिया दो दिनों तक चलती है। जिसकी वजह से इसका यह नाम रखा गया है। इस दाल में सबसे अहम है तड़का।

कबाब में भी कई वैरायटी : सुर्ख मुर्ग टिक्का, चटनी पनीर टिक्का, मकई मेथी के कबाब, दही कबाब, गलौटी कबाब का स्वाद ऐसा है कि जी भर कर खाना चाहेंगे। जिन लोगों को ज्यादा मसालेदार खाने की आदत नहीं उनके लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है। दही कबाब हंग कर्ड है। इसमें माइल्ड स्पाइसेज जैसे इलायची, काली मिर्च, अदरक, ग्रीन चिली और मिंट डालकर डीप फ्राई किया जाता है, जिससे कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। वहीं हैंड मेड मसालों, दही और चिकन से तैयार सुर्ख मुर्ग कबाब तंदूर में पकने के कारण इतना मुलायम हो जाता है कि खाने के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ हैवी खाया है।

मीरा सिंह

मसालों की समझ है जरूरी

शेफ हरदेव नॉथ इंडियन फूड के लिए मशहूर हैं। हरदेव स्कूल के समय मां का हाथ बंटाने के लिए कभी-कभार किचन में जाते तो ऑमलेट या सैंडविच बना लिया करते थे। लेकिन बीते 35 सालों से ये खाने में स्वाद का जादू बिखेरते आ रहे हैं। मसाले का उपयोग अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो इनके जायकों में मसालों की खुशबू और स्वाद तो है, लेकिन वे स्पाइसी नहीं होते।

दिल्ली वाला बनकर किरदार निभाना चाहता हूं

बातचीत

कभी हास्य किरदार तो कभी भ्रष्ट पुलिस अफसर की भूमिका तो कभी एक गंभीर पिता का रोल। हर किरदार बेहद संजीदगी के साथ। जिंदगी का हर लम्हा जी भरकर जीने का अंदाज। हम बात कर रहे हैं जानेमाने अभिनेता महेश मांजरेकर की। महेश ने फिल्म, टीवी से लेकर वेब सीरीज तक में अपने अभिनय से प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया है। हाल ही में अपनी वेब सीरीज पवन एंड पूजा के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए। इस दौरान **महेश मांजरेकर** से **संजीव कुमार मिश्र** ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

अब वेब सीरीज में नजर आएंगे अभिनेता महेश मांजरेकर • सौजन्य: आयोजक

• वेब सीरीज के किरदार खुशियों की तलाश करते दिखते हैं? लेकिन जिंदगी में विभिन्न परिस्थितियों के बीच खुशियां ढूंढना किता मुश्किल होता है?

जब मैं वेब सीरीज कर रहा था या कहूं कि जिस पात्र को मैं जी रहा था, उसकी जिंदगी की घटनाएं मेरी असल जिंदगी से मिलती-जुलती हैं। जब हम किसी किरदार को जी रहे होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि उसका कौन सा हिस्सा हमारी असल जिंदगी से मेल खाता है। लेकिन मैं अपने बारे में एक बात बता दूं कभी भी मैं अपने किरदार से प्रभावित नहीं होता हूं। जब निर्देशक एक्शन बोलता है तो मैं किरदार में रम जाता हूं और जैसे ही निर्देशक कट बोलता है मैं उस रोल से बाहर आ जाता हूं।

• आपने अभिनय भी किया और निर्देशन भी? दिल के करीब कौन सी भूमिका है?

निर्देशन...ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूं। एक अभिनेता स्टोरी टेलर नहीं होता है। वह तो कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। हां, मैं अभिनय भी करता हूं, क्योंकि वो मेरी क्रिएटिविटी का हिस्सा है।

• अब शहर की बात करते हैं, दिल्ली से आपका किस तरह का जुड़ाव रहा है?

यह वर्ष 1990 के आसपास की बात है। मैंने तब दिल्ली में कई नाटक किए थे। दरअसल, महाराष्ट्र के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मेरे दोस्त हैं। उस समय इनके पिता मंत्री हुआ करते थे। दिल्ली में तब महाराष्ट्र मंडल साल में एक बार नाटक का आयोजन करता था। ये महाराष्ट्र की कला-संस्कृति और गौरव पर आधारित नाटक होते थे। एक साल तो ऐसा था जब मेरे तीन नाटकों का मंचन हुआ था।

• उस मंचन में क्या दिल्ली के भी कलाकार हुआ करते थे? उन दिनों तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा?

हां, हम ट्रेन से आते थे। करीब 50 कलाकार होते थे। सभी महाराष्ट्र से आते थे। कलाकारों के लिए पूरी बोगी बुक करनी पड़ती थी। नाटक का सारा सामान ट्रक से भिजवाते थे। ट्रक भी कलाकारों के ट्रेन पकड़ने के चार दिन पहले रवाना करना होता था।

• बॉलीवुड में दिल्ली बेस्ड फिल्में, यहां के दृश्य खूब दिखते हैं? आपकी फिल्म में दिल्ली कब दिखेगी?

दिल्ली की बात निराली है। फिल्म बधाई हो बधाई में दिल्ली का बेहतरीन तरीके से फिल्मांकन किया गया है। यदि मुझे भी कोई बढ़िया स्क्रिप्ट मिल जाए तो मैं भी दिल्ली को फिल्माना चाहता हूं। हाल ही में मैं द व्हाइट टाइगर की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली आया था। दरअसल दिल्ली के दृश्यों पर फिल्माने के लिए उस तरह का विषय भी होना चाहिए।

• दिल्ली की कौन सी बात आपको पसंद है?

दिल्ली का खाना लाजवाब है। यहां खाने की इतनी वैराइटी हैं कि किसी को भी इस शहर से प्यार हो जाए। दिल्ली की बोली मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह दिल्ली के लोग एक दूसरे से बात करते हैं वो टोन बेमिसाल है। कानों में मिश्री सी घोलती है। मैं ऐसा रोल जरूर करना चाहूंगा जो दिल्ली वाली बोली बोलता हो।

बेहतरीन फिल्मों का उत्सव

आप सिंगापुर की फिल्मों के शौकीन हैं और दिल्ली में बैठ इन फिल्मों को इंज्वॉय करना चाहते हैं तो सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तीन दिनों तक एक से बढ़कर एक फिल्में दिखाई जाएंगी। शुरुआत चेन्नई टू सिंगापुर फिल्म से होगी।

- **आयोजन** : सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल।
- **कहां** : सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली। • **कब** : 21 से 23 फरवरी, शाम चार से रात आठ बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

पंजाबियत से लबरेज व्यंजन

हाईवे किनारे स्थित ढाबों में परोसे जाने वाले पंजाबी जायकों का स्वाद लिया है कभी। एक बार इन व्यंजनों का स्वाद चख लेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। अब दिल्ली में भी उनका स्वाद ले पाएंगे। नई दिल्ली में पंजाबी हाइवे जायकों की सीरीज शुरू हुई है। नौ दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में जरूर जाएं।

- आयोजन : पंजाबी जायका। • **कहां** : नोवोटेल नई दिल्ली एयरोसिटी।
- **कब** : 23 फरवरी तक।
- **शुल्क** : 2150 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

स्पाइसी जायके

मूंगफली चना मसाला, चटपटा चिकन, चना जोर गरम, मसाला फ्रेंच फ्राई, पनीर टिक्का, स्पाइसी चिकन टिक्का, चटोरी, चिली पोटैटो, अचारी पनीर टिक्का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया होगा न। तो देर किस बात की किल द बिल रेस्त्रां का रुख कर लें और मजेदार जायकों का स्वाद लें।

- **रेस्त्रां** : किल द बिल • **कहां** : एफ- ब्लॉक, मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
- **कब** : दोपहर 12 से रात बारह बजे तक।
- **शुल्क** : 1200 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 21 फरवरी 2020
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

नवीकरणीय और थर्मल ऊर्जा के जरिये 24 घंटे बिजली की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ड्रॉफ्ट पॉलिसी पेश की है। इसमें कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा और कोयले से बनने वाली थर्मल ऊर्जा को एक साथ मिलाकर अबाधित बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि नई नीति के जरिये पहले से मौजूद ढांचागत व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत वर्ष भर सप्लाई होने वाली कुल बिजली का 51 फीसद हिस्सा थर्मल कंपनियां देंगी, बाकी की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से की जाएगी।

अगर कानून सरल हो और उस पर थोड़ी निगरानी रहे, तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। साधारण नियमों के मामले में सबको पता होता है कि क्या करना है।

— संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय

सेंसेक्स	41,170.12 ▼ 152.88	निफ्टी	12,080.85 ▼ 45.05	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 42,492 ▲ ₹111	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 48,599 ▼ ₹67	$ डॉलर	₹ 71.64 ▲ ₹ 00.10	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 59.52

कारपोरेट हलचल

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए गेल गैस लिमिटेड की पहल

गेल गैस लिमिटेड ने नोएडा में 10 फरवरी, 2020 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए स्पेशल वेंडर डेवपलमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया।

मनोज जैन ने संभाला गेल के सीएमडी का पद

मनोज जैन ने गेल (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) का पदभार संभाल लिया है। मैकेनिकल इंजीनियर मनोज जैन 1985 में गेल से बतौर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जुड़े थे। उन्होंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए भी किया है। सीएमडी के पद पर नियुक्ति से पहले वह गेल के डायरेक्टर (बिजनेस डेवलपमेंट) पद पर कार्यरत थे। बिजनेस डेवलपमेंट, पाइपलाइन इंटीग्रिटी मैनेजमेंट और गैस मार्केटिंग क्षेत्रों में मनोज जैन को व्यापक अनुभव है।

आरएलडीए का लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पकड़ रहा गति

रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) को रेलवे की सरप्लस जमीनों से कमाई के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। रेलवे के पास देशभर में 43,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन है। इनमें काफी जमीन मेट्रो शहरों में भी है। इन्हें मोनेटाइज करने की दिशा में बढ़ते हुए आरएलडीए ने ओपन मार्केट बिड के जरिये अशोक विहार, दिल्ली प्रोजेक्ट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड को चुना है। बोलीकर्ता ने 99 साल के डेवलपमेंट राइट के साथ जमीन की लीज के लिए 1,359 करोड़ लीज प्रीमियम का प्रस्ताव दिया है। अशोक विहार साइट 10 .76 हेक्टेयर में फैली है।

एएआइ ने तीन एयरपोर्ट के लिए किए कंसेशन एग्रीमेंट

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों पर परिचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए तीन कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी मोड के आधार पर ये एग्रीमेंट क्रमशः अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ किए गए हैं। एएआइ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्ट्रेटजिक इनीशिएटिव यूनिट बीके मेहरोत्रा और एयरपोर्ट्स अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के सीईओ बहनाद जेंदी ने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया।

नई रेंज लाने को तैयार लैंसर फुटवियर

नई दिल्ली, (वि.) : फुटवियर सेक्टर की अग्रणी कंपनी लैंसर फुटवियर गर्मियों में सस्ते स्लिपर्स की नई रेंज जारी करने को पूरी तरह तैयार है। दिल्ली और हरियाणा में अपने सात कारखानों की मदद से कंपनी उत्तर भारत और टियर-2 व 3 शहरों में जाना-पहचाना नाम है। मौजूदा समय में डेली वियर से लेकर कैजुअल व स्पोर्ट्सवियर तक कंपनी के उत्पादों की विस्तृत रेंज है। गर्मियों में कंपनी 500 से 600 रुपये की कीमत के ट्रेंडी स्लिपर्स लांच करेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता ने कहा कि कंपनी अपने उत्पाद बनाते समय हमेशा नवीनतम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देती है। उन्होंने कंपनी के ड्रैगन सिरीज की लोकप्रियता का भी जिक्र किया।

वोडाफोन आइडिया की रेटिंग में गिरावट

मुंबई, आइएएनएस : एजीआर भुगतान पर संकट में घिरी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की रेटिंग में लगातार गिरावट आ रही है। दो दिनों में तीन रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग घटाई है। गुरुवार को ब्रिकवर्क रेटिंग्स और क्रिसिल ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग गिरा दी। इंडिया रेटिंग्स पहले ही रेटिंग को डाउनग्रेड कर चुकी है। इस बीच कंपनी ने गुरुवार को एजीआर के मद में 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। सोमवार को वह 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। गौरतलब है कि एजीआर के तहत कंपनी पर कुल 53,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

कई वस्तुओं के बढ़ने लगे दाम

हालात ▶ उद्यमियों ने कहा, माहौल का फायदा उठा रहे हैं कुछ व्यापारी

कच्चे माले के घरेलू कारोबारी भी ज्यादा कीमत वसूल रहे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चीन में फैले कोरोना वायरस का कारोबारी असर दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। कई कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी है तो कई के दाम आने वाले दिनों में बढ़ने की आशंका है। मैन्यूफैक्चरर्स का कहना है कि कच्चे माल के घरेलू सप्लायर्स भी माहौल का फायदा उठा रहे हैं।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक सुरंजन गुप्ता ने बताया कि इंजीनियरिंग गुड्स से जुड़े कुछ कच्चे माल के दाम बढ़े हैं। कुछ विशेष प्रकार के स्टील के दाम में 10 फीसद तक का इजाफा हुआ है। इंजीनियरिंग गुड्स निर्यातक एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गनाइजेशंस के पूर्व अध्यक्ष एससी रल्हन ने बताया कि नायलॉन जैसे कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। कई केमिकल्स से जुड़े कच्चे माल के दाम में पांच से 10 फीसद की बढ़ोतरी हो चुकी है। सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक एवं व्हाइट गुड्स के लिए भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है। टेलीविजन पैनल, एसी व फ्रिज के कंप्रेसर एवं एलॉय चिप्स के दाम पांच से 10 फीसद तक बढ़ चुके हैं और सप्लाई चेन में सुधार नहीं होने पर स्थिति खराब हो सकती है। भारत के इलेक्ट्रिक गुड्स बाजार की अग्रणी कंपनियां क्राम्पटन, वोल्टास, हैवल्स अपने कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर करती हैं। चीन से होने वाले आयात में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी आठ फीसदी है।

कच्चे माल की समीक्षा का इंतजार : उद्यमियों का कहना है कि अभी कच्चे माल का स्टॉक है। स्टॉक की समीक्षा के बाद ही स्थिति साफ होगी, लेकिन मांग के मुकाबले सप्लाई कम रहने पर कीमत हर हाल में बढ़ेगी। कुछ कारोबारी अभी कोरोना के कारण बने नकारात्मक माहौल का भी फायदा उठा रहे हैं। इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के चेयरमैन राजीव चावला कहते हैं कि चीन विश्व की फैक्ट्री है और पूरी दुनिया में उसके संकट का असर आएगा। छोटे उद्यमी सीधे तौर पर चीन से माल नहीं मंगाते हैं। वे कच्चे माल के लिए घरेलू सप्लायर्स पर निर्भर करते हैं। उन्होंने बताया कि मार्च में स्टॉक की समीक्षा होने के बाद कच्चे माल के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों के पास चीन का विकल्प नहीं है। उदाहरण के तौर पर पैरासीटामॉल दवा बनाने के लिए चीन से कच्चे माल की सप्लाई होती है। चीन से सप्लाई बंद होने पर जर्मनी से पैरासीटामोल के लिए कच्चा माल मंगवाया जा सकता है, लेकिन यह चीन के कच्चे माल के मुकाबले कई गुना महंगा है। इससे बनी दवा बाजार में बेचना व्यावहारिक नहीं रह जाएगा।

कई घरेलू उद्योगों के समक्ष बन रही संकट की स्थिति

चीन में कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट का असर कई घरेलू उद्योगों पर पड़ रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में गारमेंट्स सेक्टर की कई बड़ी इकाइयां हैं। ये कंपनियां बटन, धागा, जिप, हुक, लटकन, मोती, बीड्स, इलॉस्टिक, फैब्रिक आदि के लिए चीन पर निर्भर हैं। घरेलू स्तर पर इन कच्चा माल की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में चीन से आपूर्ति प्रभावित होना इनके लिए संकट का सबब बन रहा है। महंगा कच्चा माल खरीदने से कंपनियों को अपने उत्पाद महंगे करने पड़ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है। उद्योगपति एवं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान बीआर भाटिया का कहना है कि अभी तो कच्चे माल का स्टॉक है, लेकिन संकट लंबा खिंचा तो मुश्किल आ सकती है। गुरुग्राम में भी कमोबेश यही हालात दिख रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की इकाइयां मौजूदा परिस्थिति से चिंता में हैं। हालांकि उद्यमियों को उम्मीद है कि जल्द इससे मुश्किल का हल निकल आएगा।

फिक्की ने कहा, भारत अपने हाथ में ले आपूर्ति की कमान

- निवेश तेज करके उत्पादन बढ़ाने की दी सलाह
- कोरोना से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों की तारीफ

लखनऊ, प्रेट्र : चीन में कोरोना के कारण उसके कई बाजारों में आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारतीय उद्योग संगठन फिक्की इसे घरेलू कंपनियों के लिए अवसर के तौर पर देखता है। फिक्की ने कहा है कि स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां इस सप्लाई गैप का फायदा उठा सकती हैं। भारतीय कंपनियां निवेश बढ़ाकर इस खाली जगह की भरपाई कर सकती हैं।

फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के कारण बनी परिस्थिति को लेकर इनके प्रयास काफी बेहतर रहे हैं। सरकार ने आपूर्ति की बाधा से निपटने के लिए अंतर-मंत्रालय समन्वय प्रणाली का गठन किया है। चिनॉय ने कहा कि चीन से जो सामान लिया जा चुका है, उसे जल्दी भारत पहुंचाने के वैकल्पिक रास्तों की खोज करना चाहिए। इसके लिए हवाई मार्ग एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां भी इसकी आपूर्ति करने का प्रयास कर सकती हैं। इसके लिए घरेलू कंपनियों में तेज गति से निवेश की जरूरत होगी। चिनॉय ने कहा कि ऐसे मौके पर वित्तीय संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन से कच्चे माले की आपूर्ति बाधित होने के चलते भारतीय दवा कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

दिलीप चिनॉय। फाइल फोटो

मंत्रिसमूह गठित कर हो असर का आकलन

नई दिल्ली, आइएएनएस : उद्योग संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना को लेकर मंत्रिसमूह गठित करने की अपील की है। कैट ने घरेलू कारोबार को कोरोना के चलते होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भारतीय लोगों पर चीन से आने वाले उत्पादों के बुरे प्रभाव का आकलन करने के लिए उनकी सुरक्षा जांच होनी चाहिए। आपूर्ति प्रभावित नहीं हो इसके लिए कैट ने घरेलू कंपनियों को विशेष सहायता पैकेज की सलाह भी दी है।

कोरोना वायरस बनता जा रहा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा

- आइएमएफ ने कहा – पहले से कमजोर पड़ी इकोनॉमी के लिए कोरोना नई चुनौती
- वैश्विक संस्थाओं से मौद्रिक नीतियों के जरिये किया सहायता का अनुरोध

प्रतीकात्मक फोटो

वाशिंगटन, एएनआइ : चीन में फैली कोरोना वायरस महामारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा बनती जा रही है। इसके चलते पहले ही इकोनॉमी को काफी नुकसान हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर को पटरी पर लौटाने के रास्ते में कोरोना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सऊदी के रियाद में आयोजित जी-20 देशों की बैठक के लिए तैयार नोट में आइएमएफ ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के सामने इस समय कई चुनौतियां मौजूद हैं।

आइएमएफ ने कहा कि जलवायु से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं और चीन-अमेरिका ट्रेड वार के बाद अब कोरोना वायरस बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। हालांकि आइएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ रेट के अनुमान में कोई कटौती नहीं की है। इसे पहले की तरह 3.3 परसेंट रखा गया है। संस्थान पिछले वर्ष अक्टूबर में इसमें 0.1 परसेंट की कटौती कर चुका है।

आइएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने कहा कि इस समय कोरोना वायरस हमारे सामने सबसे बड़ी अनिश्चितता बनकर खड़ा हो गया है। हमने पिछले महीने तक इस ग्लोबल इमरजेंसी के बारे में सोचा भी नहीं था। पहले से ही पटरी से उतर रही ग्लोबल इकोनॉमी को कोरोना और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी इस महामारी के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में व्यवधान आया है, जिसका असर दिखाई देने लगा है। आइएमएफ ने नीति निर्माताओं से मौद्रिक नीतियों के जरिये इकोनॉमी को सहायता देने का अनुरोध किया है।

ग्लोबल विकास दर में एक फीसद तक की गिरावट की आशंका

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना का खतरा धीरे-धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। इसके प्रकोप से बुरी तरह से प्रभावित चीन से जरूरी वस्तुएं और कच्चे माल का निर्यात बाधित हो रहा है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते वैश्विक इकोनॉमी की विकास दर में एक परसेंट तक गिरावट की आशंका है। मौजूदा समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीन का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 90 परसेंट कारोबार उसी हिस्से में है, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर जून तक इस समस्या से निजात नहीं मिल पाई तो ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट तय है।

...तो औद्योगिक विकास की राह नहीं रोकेंगे राजनीति के रोड़े

राजीव कुमार, नई दिल्ली

- पूरे देश के लिए बनाई जाएगी एक औद्योगिक नीति, केंद्र एवं राज्यों के लिए अनिवार्य होगा नीति का पालन

औद्योगिक विकास के रास्ते में केंद्र एवं राज्य की राजनीति का रोड़ा सामने नहीं आएगा। पूरे देश में औद्योगिक विकास के लिए एक औद्योगिक नीति होगी। केंद्र और सभी राज्य सरकारें उस नीति को मानने के लिए बाध्य होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआइआइटी) को ऐसी ही नीति बनाने के लिए कहा गया है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक हाल ही में उन्होंने डीपीआइआइटी को औद्योगिक विकास के लिए ऐसी नीति बनाने का प्रस्ताव दिया है जो वैधानिक रूप से केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए लागू हो सके। नीति का प्रारूप ऐसा हो कि केंद्र एवं राज्य दोनों ही औद्योगिक विकास में एक-दूसरे के पार्टनर बन सकें। केंद्र एवं राज्य हर हाल में उस नीति का पालन करें, इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। औद्योगिक विकास की नीति में राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए रिवार्ड एवं पेनाल्टी का प्रावधान होगा। अगर कोई राज्य उस नीति को मानने या अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटता है तो उसके खिलाफ प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

दरअसल ऐसा कई बार देखा गया है कि औद्योगिक नीति में भी राजनीतिक विचारधारा आड़े आ जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार की अलग-अलग नीतियां एवं रुख होने की वजह से उद्यमियों को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। राज्य औद्योगिक विकास के लिए अलग नीति बनाते हैं और कई मामलों में केंद्र की नीति से वह बिल्कुल भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर बौद्धिक संपदा व इनोवेशन के लिए पेटेंट के मामले में कई बार राज्यों एवं केंद्र के बीच मतभेद होता है। ऐसे में कंपनियों को या इनोवेशन करने वालों को सही लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य में कई बार सरकार बदल जाने पर नई सरकार नए सिरे से औद्योगिक नीति लाती है जिससे संपूर्ण औद्योगिक विकास पर असर पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का यह प्रस्ताव शुरुआती स्तर पर है, लेकिन उद्देश्य औद्योगिक विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना है चाहे वह केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद राज्यों से चर्चा की जाएगी।

विदेशी टेलीकॉम वेंडर्स के लिए भारत आना होगा मुश्किल

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम उपकरण कारोबार में जैसे को तैसा की नीति पर बढ़ते हुए सरकार ने कहा है कि उन देशों की कंपनियों को भारत में कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो भारतीय कंपनियों के लिए बाजार नहीं खोलती हैं। यह फैसला सरकारी खरीद आदेश, 2017 के तहत आया है। इस कदम से स्थानीय मैन्यूफैक्चरर्स को बढ़ावा देते हुए 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन मिलेगा।

दूरसंचार उपकरणों का बाजार काफी बड़ा है। इसमें वाई-फाई, फिक्स्ड लाइन, सेल्युलर नेटवर्क और 5जी सेवाओं से जुड़े उपकरणों की खरीद-फरोख्त शामिल है। दूरसंचार विभाग ने सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी करके इस बारे में सूचना दी है।

नोटिस के मुताबिक कोई भी विदेशी सरकार जो भारतीय टेलीकॉम वेंडर्स को अपने बाजार में प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं देती है, उसके टेलीकॉम वेंडर्स से किसी तरह का सौदा नहीं किया जाए। अगर नोडल एजेंसी को ज्ञात होता है कि किसी देश द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में जगह नहीं दी गई है तो वह उसकी कंपनियों को बोली से बाहर कर सकती है या अयोग्य ठहरा सकती है। टेलीकॉम उपकरणों के मामले में दूरसंचार विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

5-जी के लिए डीओटी की टेलीकॉम कंपनियों से मुलाकात

नई दिल्ली, आइएएनएस : दूरसंचार विभाग (डीओटी) 5जी सेवाओं की तैयारी में लगा हुआ है। इसी क्रम में विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों और उन्हें उपकरण की आपूर्ति करने वाले वेंडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में 5जी ट्रायल की तैयारी पर चर्चा हुई। इस दौरान डीओटी ने इन कंपनियों से उनकी जरूरतों के बारे में जाना। बैठक में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और बीएसएनएल ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जून में सरकार ने 5जी ट्रायल के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया था।

टेलीकॉम सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संकट है एजीआर : मित्तल

नई दिल्ली, आइएएनएस : अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने एजीआर को टेलीकॉम सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संकट बताया है। मित्तल ने गुरुवार को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात कर सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने का आग्रह किया।

टेलीकॉम कंपनियां काफी समय से करों में छूट की मांग कर रही हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वोडाफोन आइडिया ने बेलआउट पैकेज की मांग की है। हालांकि इस मामले में सरकार के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस फीस में कुछ कटौती की जा सकती है। इसके अलावा ब्याज और जुर्माने में भी कुछ कटौती संभव है। सूत्रों का कहना है कि सरकार भी इस मामले में संतुलन की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से कोई सीधा संकेत नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि एजीआर के तहत एयरटेल पर 35,500 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें से 10,000 करोड़ वह पहले ही दे चुकी है। कंपनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले वह शेष बकाया का भुगतान कर देगी।

तैयारी

टेक्सटाइल मंत्रालय नई पॉलिसी के लिए लगातार कर रहा है संबंधित पक्षों से विमर्श, नई नीति के तहत चीन की तरह कम लागत पर अधिक उत्पादन क्षमता का होगा विस्तार

कपड़ा बाजार में खत्म होगा चीन, बांग्लादेश का बोलबाला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक फोटो

कोरोना की वजह से कॉटन यार्न हो सकता है सस्ता

टेक्सटाइल उद्योग के मुताबिक चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से भारत में कॉटन यॉर्न की कीमत में गिरावट हो सकती है। भारत चीन को हर माह दो से ढाई करोड़ कॉटन यार्न का निर्यात करता है। चीन में फैले वायरस की वजह से चीन माल नहीं ले रहा है। इस कारण घरेलू बाजार में कॉटन यार्न की कीमतों में गिरावट की संभावना है। टेक्सटाइल उद्योग के मुताबिक भारत चीन से लगभग 14 करोड़ डॉलर के बटन, जिप, हैंगर्स, नीडल्स जैसे कच्चे माल का निर्यात करता है। भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई के लिए उत्पादन क्षमता नहीं है।

भारत के कपड़ा बाजार से चीन एवं बांग्लादेश के दबदबे को खत्म करने के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय जल्द ही नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रहा है। पॉलिसी के तहत कम लागत पर टेक्साइल उद्योग की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय टेक्सटाइल को मुकाबले में खड़ा करने के लिए कई नए उपाए किए जाएंगे। इनमें भारतीय कपड़ों की वैश्विक ब्रांडिंग, उत्पादन में उच्च तकनीक का इस्तेमाल और बड़े ऑर्डर को तय समय में डिलीवरी देने की क्षमता की स्थापना करना है। टेक्सटाइल उद्योग के लिए श्रम नियमों में भी बदलाव की बात चल रही है।

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सिटी) के चेयरमैन टी. राजकुमार के मुताबिक भारत में चलने वाले ग्लोबल ब्रांड के रिटेल स्टोर्स में चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के गारमेंट्स बड़ी मात्रा में होते हैं। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स वालों ने कहा था कि भारत में उनकी मांगों को पूरा करने के लायक बड़े गारमेंट निर्माता नहीं हैं। उन ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स वालों ने बताया कि कम लागत और एक साथ भारी मात्रा में सप्लाई मिलने के कारण वे भारत स्थित अपने स्टोर के लिए चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से गारमेंट का आयात करते हैं।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बने ताकि सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर के रिटेल स्टोर में भारत में निर्मित गारमेंट की बिक्री हो। टीटी टेक्सटाइल के एमडी संजय जैन कहते हैं, 'पिछले एक माह से टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव रवि कपूर के नेतृत्व में टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर गहन विमर्श चल रहा है। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ कई राउंड की बैठक हो चुकी है।' सिटी के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को आकर्षित करने के साथ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लाने के लिए आकर्षक नियम बनाए जा सकते हैं। वहीं, प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क में एक ही साथ टेक्सटाइल के हर सेक्टर जैसे कि यार्न, फैब्रिक और गारमेंट की एकीकृत यूनिट की स्थापना करने की सहूलियत देने का भी प्रावधान होगा। मैन्यूफैक्चरिंग के लिए कम लागत पर पानी, बिजली, तकनीकी सहायता जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा।

नकारात्मक ग्लोबल संकेतों से घरेलू शेयर बाजारों में नरमी

- ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट की आशंका से निवेशक निराश

मुंबई, प्रेट्र : कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर में गिरावट की आशंका के चलते शेयर बाजारों में निराशा देखने को मिली। गुरुवार को प्रमुख घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 152.88 अंक नीचे उतरकर 41,170.12 के स्तर पर स्थिर हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 45.05 अंकों की कमी दर्ज की गई। निफ्टी 12,080.85 पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार के कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली थी। महाशिवरात्रि के चलते शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे।

बीएसई के सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एचयूएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसके विपरीत इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एसबीआइ, पावरग्रिड और ओएनजीसी के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस, आइटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, टेक एंड रियल्टी स्टॉक्स में 0.90 परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं मेटल, टेलीकॉम, बैंक और पावर कंपनियों के शेयरों में 0.90 परसेंट तक की तेजी दर्ज की गई। कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट की आशंका है। जानकारों के मुताबिक इससे बाजार में नकारात्मक संदेश गया है। इस महामारी के चलते मृतकों की संख्या 2,100 के ऊपर पहुंच गई है। एशिया के अन्य शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला।

33 लोगों की मौत हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से और लाखों की संख्या में जानवर भी मारे गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एलान किया है कि देश के जंगलों में लगी भीषण आग की राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराई जाएगी।

...तो यह होगा कोरोना का सर्वाधिक संक्रमण स्तर

कोरोना वायरस का प्रकोप अपने शिखर पर कब होगा, इसको लेकर दुनिया के कई विशेषज्ञों के अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं। कुछ ने सुझाया है कि नए संक्रमित लोगों की संख्या किसी भी दिन अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है और यह किसी भी वक्त हो सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि इसमें अभी महीनों लगेंगे और यह वायरस अपने शिखर तक पहुंचने से पहले करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा।

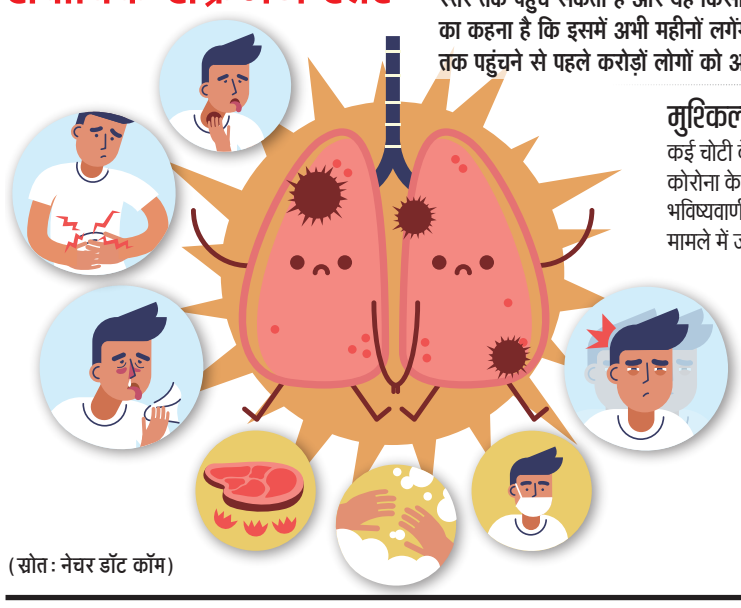

(स्रोत: नेचर डॉट कॉम)

मुश्किल है पूर्वानुमान

कई चोटी के विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के अपने शिखर पर पहुंचने की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है। वो भी ऐसे मामले में जब आपके पास अपूर्ण जानकारी हो।

23 लाख
अनुमान है कि एक दिन में इतने मामले सामने आ सकते हैं

55-65 करोड़
चीन में संक्रमित हो सकने वाले लोग

आशावादी नजरिया

कोरोना वायरस को काबू करने में जुटे विशेषज्ञों में से एक चीनी डॉक्टर झोंग नंशान ने 11 फरवरी को कहा था कि कोरोना वायरस फरवरी के आखिर तक अपने शिखर पर होगा। सार्स वायरस का पता लगाने वाले झोंग का कहना है कि सरकार के प्रयासों से हालात कुछ काबू में आए हैं। यात्रा प्रतिबंधों और छुट्टियां बढ़ाने जैसे उपाय कारगर रहे हैं। चीन में करीब 70 हजार लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जितने मामले सामने आए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

संक्रमण दर अधिक

सांख्यिकीविद् सेबस्टियन फंक के अनुसार वुहान में एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 1.5 से 4.5 लोगों को संक्रमित कर रहा है। यात्रा प्रतिबंध से पहले बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके थे। उनके अनुसार कोरोना जब शिखर पर पहुंचेगा तब तक संक्रमितों की संख्या करीब दस लाख तक पहुंच सकती है।

सबसे भीषण अनुमान

जापान के महामारी विशेषज्ञ हिरोशी निशिउरा ने अनुमान लगाया है कि मई के आखिर तक इसका प्रकोप चरम पर रहेगा। इस बिंदु पर, एक दिन में 23 लाख मामले सामने आ सकते हैं। अनुमान है कि चीन में 55 से 65 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, जो देश की आबादी का 40 फीसद हैं।

असर

लिउंग का कहना है कि चरम पर संक्रमित लोगों की संख्या कम करना महत्वपूर्ण है। अगर हर कोई एक ही समय में बीमार हो जाता है, पूरा समाज रुक जाता है।

अधिक मृत्युदर

हांगकांग विश्वविद्यालय के महामारी विशेषज्ञ गैब्रियल लियुंग का कहना है कि ये अनुमानों का चरम है। 9 फरवरी को झोंग द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर में मृत्य दर की नई गणना से पता चलता है कि प्रति सौ मामलों में लगभग 1.36 मौतें होती हैं। यह संख्या बहुत अधिक है।

कोरोना के सर्वाधिक शिकार हैं बुजुर्ग

चीन में कोरोना से पीड़ित 44, 672 मरीजों में सबसे ज्यादा 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं। जिनका फीसद 14 .2 है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एवं प्रिवेंशन सेंटर के अध्ययन के मुताबिक बढ़ती आयु के क्रम में लोग इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। यह स्पष्ट इंगित करता है कि उम्र के साथ इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है।

मृत्युदर 2.3 फीसद

विश्लेषण में इस्तेमाल किए गए 44,672 मामलों में 1,023 लोगों की मौत हुई जो 2 .3 फीसद है। इसमें पाया गया कि उम्र के साथ मृत्युदर भी बढ़ती जाती है।

आयुवर्ग मौतें

10-19	0.2%
20-29	0.2%
30-39	0.2%
40-49	0.4%
50-59	1.3%
60-69	3.6%
70-79	8.0%
80+	14.8%

ये बीमारियां घातक

जिन लोगों को हृदय व श्वसन संबंधी रोग, हाइपरटेंशन या मधुमेह है उनमें मृत्युदर का फीसद अधिक पाया गया। साथ ही कोरोना की गिरफ्त में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा आ रहे हैं। पुरुषों की मृत्युदर का फीसद 2.8 जबकि महिलाओं का 1.7 फीसद है।

वुहान में उद्योगों की मौजूदगी

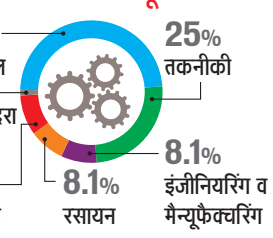

(स्रोत: चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज एवं प्रिवेंशन सेंटर)

चीन में कोरोना पीड़ितों की संख्या 75 हजार के करीब पहुंची

वायरस का प्रकोप ▶ 2,100 लोगों की मौत, नए मामलों में दिखी गिरावट

अब तक 25 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है यह महामारी 349 नए मामलों की हुई पुष्टि

बीजिंग, एजेंसियां : चीन में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या बढ़कर 75 हजार के करीब पहुंच गई है। अब तक तकरीबन 2,100 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में हालांकि अब नए मामलों की दर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि दुनिया में अनुमान से ज्यादा तेजी से वायरस का प्रसार हो रहा है।

मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला मामला गत दिसंबर में सामने आया था। तब से यह वायरस वुहान से पूरे चीन समेत दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, हुबेई में बुधवार को 349 नए मामलों की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा 25 जनवरी के बाद सबसे निम्न है। मंगलवार को 1693 मामले सामने आए थे।

चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी का रूप धारण कर चुका है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रभावितों का इलाज करने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। सर्वाधिक प्रभावित वुहान शहर में अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। ऐसे ही एक अस्पताल में उपचाराधीन पीड़ित। एपी

इंफ्लुएंजा जैसा व्यवहार : कोरोना वायरस पर किए गए एक अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित की गई। इसमें वायरस का बर्ताव काफी हद तक इंफ्लुएंजा जैसा पाया गया है। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का लक्षण दिखने से पहले ही यह दूसरे में पहुंच सकता है।

क्रूज के दो यात्रियों की गई जान, एक और भारतीय संक्रमित : जापान के तट पर गत तीन फरवरी से खड़े डायमंड प्रिंसेज क्रूज के दो बुजुर्ग यात्रियों की वायरस से मौत होने की खबर है। जबकि क्रूज पर सवार एक और भारतीय में वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आठ भारतीयों समेत क्रूज पर पीड़ितों की संख्या बढ़कर 621 हो गई है। क्रूज पर कुल 3,711 लोग सवार हैं। इनमें 132 भारतीयों समेत 1,100 चालक दल के सदस्य हैं। क्रूज पर छह भारतीय यात्री भी बताए जा रहे हैं। बुधवार को 500 से ज्यादा यात्रियों को क्रूज से निकलने की इजाजत दी गई थी।

ईरानी शहर में दो की मौत के बाद बंद किए गए स्कूल : ईरान की राजधानी तेहरान से 140 किमी दूर कोम शहर में कोरोना वायरस से दो लोगों की मौत के बाद गुरुवार को तीन नए मामले सामने आए। इसके चलते शहर के सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया गया।

दक्षिण कोरिया में पहली मौत, लोगों से घरों में रहने की अपील

दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से पहली मौत होने की खबर है। इस खबर के कुछ घंटे बाद ही 25 लाख की आबादी वाले दक्षिण कोरिया के चौथे सबसे बड़े शहर डेगू के मेयर ने शहरवासियों से घरों में ही रहने की अपील की। डेगू में वायरस के 53 मामले सामने आए हैं। शहर के कई मॉल और शॉपिंग सेंटर खाली देखे गए।

चीन में फंसे छात्रों के परिजनों का इमरान सरकार को अल्टीमेटम

इस्लामाबाद, आइएएनएस : कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के वुहान शहर से पाकिस्तानी छात्रों को नहीं निकाले जाने से उनके परिजनों में इमरान सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्रों के अभिभावकों ने इमरान सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके बच्चों को तीन दिन में नहीं लाया गया तो वे चीनी दूतावास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। चीन में फंसे छात्रों के परिजनों ने बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन भी किया।

वुहान के विश्वविद्यालयों में करीब 500 पाकिस्तानी छात्र पढ़ते हैं और वे इस शहर में आवाजाही बंद होने से फंस गए हैं। डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक की और उन्हें यह जानकारी दी कि छात्रों को क्यों नहीं निकाला जा रहा? विदेश मामलों पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी ने अभिभावकों को बताया कि चीन में कोरोना वायरस से हालात जटिल हो गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री के एक अन्य सहायक जफर मिर्जा ने कहा कि सरकार छात्रों के परिवारों की व्यथा को समझ रही है। छात्रों के अभिभावकों ने हालांकि अधिकारियों की दलीलों को खारिज कर दिया और पूछा कि अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश अपने नागरिकों को निकाल सकते हैं तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा?

कहा, तीन दिन में बच्चों को नहीं लाया गया तो चीनी दूतावास के बाहर देंगे धरना

बता दें कि चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद ज्यादातर देशों ने चीन से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने लोगों को वुहान से निकालने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया में इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा था।

कोरोना वायरस के इलाज की दिशा में बड़ी सफलता

वाशिंगटन, एएफपी : जानलेवा कोरोना वायरस का टीका व इलाज खोजने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मिली है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका 3डी एटॉमिक स्केल मैप तैयार कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों ने चीन के शोधकर्ताओं की तरफ से उपलब्ध कराए गए वायरस के जेनेटिक कोड की मदद से यह सफलता पाई है। वैज्ञानिक इस एटॉमिक मैप को दुनियाभर के वैज्ञानिकों के साथ साझा करते हुए शोध की दिशा में प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि इसकी मदद से इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करना संभव हो सकता है।

सैन्य विमान से 100 भारतीयों को वुहान से लाया जाएगा वापस

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत चिकित्सा सामग्री लेकर जो विमान वुहान (चीन) भेज रहा है वह विमान लौटते वक्त कोरोना वायरस प्रभावित इस शहर से करीब 100 भारतीयों को लेकर आएगा। इस महीने एयर इंडिया दो अलग-अलग उड़ानों के जरिये वुहान से 640 भारतीयों को वापस ला चुका है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि चीन जाने और वहां से आने के संदर्भ में परामर्श बरकरार हैं, लेकिन वहां की यात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत वुहान में फंसे भारतीयों को निकालने और वहां चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए सी-17 सैन्य परिवहन विमान भेजने को तैयार है। भारत को इस संदर्भ में चीन से मंजूरी का इंतजार है। रवीश कुमार ने कहा, 'जो लोग वापस आने के इच्छुक हैं उनसे दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है... क्षमता और अन्य साजो-सामान की गुंजाइश रहने पर हम अन्य देशों के नागरिकों को भी इसमें जगह देंगे।'

जापान में क्रूज जहाज पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए आठ भारतीयों के संदर्भ में रवीश कुमार ने कहा कि भारतीय पक्ष जापानी अधिकारियों के संपर्क में है। कई संभावनाएं हैं जिन्हें देखा जा रहा है। जापान में भारतीय दूतावास नियमित जानकारी दे रहा है। वे हालात पर करीबी नजर रख रहे हैं। क्रूज जहाज को पृथक रखने की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई। जहाज से यात्रियों को निकाला जाना जारी है और इसमें कुछ दिन लगेंगे। पहले यात्रियों को निकाला जा रहा है बाद में चालक दल सदस्यों को उतारा जाएगा। वायरस से संक्रमित आठ भारतीयों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अमेरिका में घुसपैठ का प्रयास करते 7,000 से ज्यादा भारतवंशी पकड़े गए

वाशिंगटन, प्रेट्र : गत वर्ष अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश की कोशिश करते 7,720 भारतवंशी गिरफ्तार किए गए। इनमें 272 महिलाएं और 591 नाबालिग भी शामिल हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई।

नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन (एनएपीए) के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने गुरुवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2019 (अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019) में कुल 8,51,508 लोग घुसपैठ का प्रयास करते पकड़े गए। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 115 फीसद ज्यादा और विगत 12 वर्षों में सबसे ज्यादा था। एनएपीए ने सूचना की आजादी (एफआइए) कानून के तहत हासिल जानकारी के आधार पर बताया कि गत वर्ष अमेरिकी सीमा पर कस्टम सुरक्षा अधिकारियों ने 7,720 भारतवंशियों को गिरफ्तार किया। वर्ष 2017 में 4,620 भारतवंशी गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा वर्ष 2016 में 3,544, वर्ष 2015 में 3,019 व वर्ष 2014 में 1,663 भारतवंशी घुसपैठ के प्रयास में गिफ्तार किए गए।

31 मार्च को शाही जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे हैरी और मेगन

हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल। फाइल/रायटर

कनाडा में बनाया है आशियाना

शाही परिवार से अलग हो चुके हैरी और मेगन फिलहाल कनाडा में हैं। वह वेंकूवर द्वीप के विक्टोरिया स्थित एक आलीशान घर में अपने दस माह के बेटे आर्ची के साथ रह रहे हैं।

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन की शाही जिम्मेदारियां 31 मार्च को आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। हैरी और मेगन एक अप्रैल से लंदन स्थित बकिंघम पैलेस में अपने दफ्तर को बंद कर देंगे। इस शाही दंपती ने गत आठ जनवरी को यह एलान कर सबको चौंका दिया था कि वे शाही जिम्मेदारियां छोड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं।

हैरी और मेगन के कार्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है, हैरी मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर के पदों पर बने रहेंगे। मेगन आने वाले समय में अपने नए गैर लाभकारी संगठन का एलान करेंगी। यह जोड़ा अपनी अंतिम शाही जिम्मेदारियों के तौर पर नौ मार्च को वेस्टमिंस्टर एबी में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होगा। इस मौके पर पूरा शाही परिवार जमा होगा।

आठ साल बाद सीरिया ने खोला अलेप्पो एयरपोर्ट

दमिश्क, आइएएनएस : सीरिया की सरकार ने भीषण गृहयुद्ध के कारण 2012 से बंद अलेप्पो एयरपोर्ट को फिर चालू कर दिया है। सीरिया के परिवहन मंत्री अली हमूद बुधवार को दमिश्क से फ्लाइट के जरिये अलेप्पो पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अलेप्पो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब यात्री विमानों की उड़ान और लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार है।

सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के हवाई अड्डे को फिर से चालू करने का काम इस क्षेत्र से विद्रोहियों को खदेड़ने के बाद किया गया है। रूस समर्थित सीरियाई सेना की लगातार कार्रवाई के बाद इस हफ्ते अलेप्पो से लगते इलाकों को विद्रोहियों के कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया। वर्ष 2012 में विद्रोहियों के कब्जे के बाद से अलेप्पो एयरपोर्ट से नागरिक उड़ानें बंद कर दी गई थीं। सीरिया की सेना ने चार साल बाद अलेप्पो शहर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। परिवहन मंत्री अली हमूद ने उम्मीद जताई है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

लंदन में मस्जिद के बाहर हमला, संदिग्ध गिरफ्तार

न्यूयॉर्क टाइम्स से

लंदन : ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध मस्जिद के बाहर गुरुवार को दोपहर की नमाज के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग पर एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं बताई गई है। पुलिस ने फिलहाल इस हमले के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाल में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में हुईं आतंकी घटनाओं को देखते हुए पुलिस हर पहलू से इस घटना की जांच कर रही है।

स्थानीय समयानुसार अपरान्ह करीब तीन बजे इस हमले की सूचना पुलिस को दी गई। ट्विटर पर पोस्ट किए गए फोटो और वीडियो में दिखाई दिया कि लंदन के बीचोंबीच रीजेंट पार्क के समीप स्थित मशहूर मस्जिद में लोगों की भीड़ लगी थी, तभी लाल जैकेट पहने एक हमलावर नजर आया। हमले के बाद लोगों ने उसे घेर लिया। पास में ही में फर्श पर चाकू भी पड़ा था। वीडियो में एक व्यक्ति यह कहता सुनाई दे रहा है कि पुलिस को अपना काम करने दें।

पुलिस ने हमलावर के बारे में नहीं दी कोई जानकारी, पहले भी ब्रिटेन में मस्जिद को बनाया जा चुका है निशाना

मुस्लिम काउंसिल आफ ब्रिटेन के प्रवक्ता मिकदाद वर्सी ने बीबीसी को बताया कि यह सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है और आज की घटना बहुत अधिक विचलित करने वाली है। इस मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया 1940 में शुरू हुई थी। विंस्टन चर्चिल की कैबिनेट ने इसके लिए जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, लेकिन 1974 तक काम आरंभ नहीं हो सका। बाद में मस्जिद 1977 में बनकर तैयार हो सकी। ब्रिटेन में मस्जिद को निशाना बनाए जाने की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले जून 2017 में एक ब्रिटिश व्यक्ति ने किराए में ली गई वैन फिंसबरी पार्क एरिया में स्थित मस्जिद से बाहर निकल रहे लोगों पर चढ़ा दी थी।

पाकिस्तान को उठाने होंगे ठोस कदम

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

पाकिस्तान को जो कदम उठाने होंगे उनमें आतंकियों के लिए मनी लांड्रिंग को पूरी तरह से रोकना, गैर कानूनी तरीके से राशि हस्तांतरित करने की हर तरह की गतिविधियों को रोकना, दूसरे देशों में ब्लैक मनी को भेजना या दूसरे देशों से ब्लैक मनी के प्रवाह को रोकना, आतंकी फंडिंग को रोकने में सरकारी व कानूनी एजेंसियों को मजबूत बनाना जैसे कदम शामिल होंगे। यह भी साबित करना होगा कि उसकी एजेंसियों ने आतंकी फंडिंग को रोकना शुरू कर दिया है। इसके साफ तौर पर उदाहरण देने होंगे। यह भी दिखाना होगा कि अभी तक आतंकी संगठनों को जो मदद मिली थी या फंड मिला था उसे अब जब्त किया जा रहा है। जानकारों की मानें तो पाकिस्तान के एफएटीएफ से ब्लैक लिस्ट होने की स्थिति में उसे भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं कि ऐसा होने पर पाकिस्तान पर सालाना 10 अरब डॉलर को बोझ पड़ेगा।

रिपोर्ट

एनएफएपी के मुताबिक, यहां पिछले तीन साल में 105 प्रतिशत बढ़ गई है भारतीयों की संख्या, इसका कारण अमेरिका द्वारा वीजा नियमों को सख्त करने के साथ-साथ गन कल्चर भी है

बढ़ रही कनाडा में बसने वाले भारतीयों की संख्या

वाशिंगटन, आइएएनएस : कनाडा में स्थायी तौर पर बसने वाले भारतीयों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वर्जीनिया स्थित नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (एनएफएपी) के मुताबिक, पिछले तीन साल के दौरान ऐसे भारतीयों की संख्या में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2016 में कनाडा में स्थायी तौर पर बसने वाले भारतीयों की संख्या जहां 39,340 थी। वहीं 2019 के 11 महीनों में यह 80,685 तक पहुंच गई। अमेरिका से सटे इस देश में आने वाले समय में भारतीयों की आबादी में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। आव्रजन अधिकारियों के मुताबिक, कनाडा में कुशल पेशेवर जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि की बढ़ती संख्या इस बात की ओर भी इशारा करती है कि कनाडा प्रवासियों के बसने के लिए सबसे अच्छे देशों में से एक है और विश्व भर से बड़ी संख्या में पेशेवर कनाडा का अपना घर बनाना चाहते हैं। भारतीयों समेत अन्य देशों के पेशेवर कनाडा की ओर इसीलिए भी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आइटी कंपनियों के संगठन अपने कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं देते हैं। साथ ही साथ लंबित वीजा की समस्याओं के निपटान के लिए उन्होंने कई मुख्य शहरों में अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं।

'अमेरिकन बाजार' ने एक चिकित्सक रवि भट के हवाले से बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा की ओर भारतीयों के ज्यादा रुख करने की वजह अमेरिका द्वारा वीजा नियमों को सख्त करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा गन कल्चर और नस्लवाद की समस्याओं ने भी भारतीयों का अमेरिका से मोह भंग किया है। अमेरिका में बढ़ती बंदूक संस्कृति पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। कनाडा की शुचिता एम. कहती हैं कि अमेरिका से लोगों का इसलिए भी मोह भंग हो रहा है कि वहां कनाडा की तरह जीवन सुगम नहीं है।

कई पेशेवरों को लगता है कि अमेरिका के मुकाबले कनाडा में जीवन सुगम होता है। प्रतीकात्मक

जर्मनी में गोलीबारी में नौ की मौत

हनाऊ, एपी : जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के उपनगरीय इलाके हनाऊ में बुधवार रात एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी कर नौ लोगों की जान ले ली। हमलावर ने पहले एक हुक्का बार में गोलीबारी की और इसके बाद ढाई किलोमीटर दूर अपने घर के करीब लोगों पर गोलियां बरसाईं। 43 साल के हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली से उड़ा लिया।

गोलीबारी की घटना से आहत जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने गुरुवार को हाले यूनिवर्सिटी का अपना दौरा रद कर दिया। मर्केल ने गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में मारे गए ज्यादातर लोग तुर्की के नागरिक थे। स्थानीय मीडिया इस घटना को जर्मनी में कट्टर दक्षिणपंथ के सिर उठाने से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने एक विशेष दल का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश होगा।

कार्बन उत्सर्जन घटाने में चीन से बड़ी समस्या है भारत : ब्लूमबर्ग

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग (78) ने दावा किया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने और खासतौर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने के मामले में चीन के मुकाबले भारत ज्यादा बड़ी समस्या है।

लास वेगास में डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारी की प्रारंभिक बहस में ब्लूमबर्ग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने का फैसला हास्यास्पद था। ब्लूमबर्ग ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'पूरी तरह ईमानदारी से कहूं तो चीन ने कमी लाई है। भारत ज्यादा बड़ी समस्या है, बल्कि यह असाधारण समस्या है। कोई इस बारे में कुछ नहीं कर रहा।' ब्लूमबर्ग से उनके कारोबार के बारे में पूछा गया था जिसका दुनिया के सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश चीन में काफी निवेश है। उन्होंने आगे कहा, 'आप उनसे (चीन से) युद्ध करने नहीं जा रहे। आपको उनसे बातचीत करनी होगी और हमने टैरिफ के मामले में यह देख लिया है। आपको चीनियों को मनाना होगा कि यह उनके भी हित में है, जिस तरह हमारे लोग मरेंगे, उसी तरह उनके लोग भी मरेंगे और हम मिलकर काम करेंगे।'

डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में हैं अमेरिकी कारोबारी

'ट्रंप जैसे अहंकारी और धूर्त को मैं ही हरा सकता हूं' : ब्लूमबर्ग ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप को कौन हरा सकता है? और दूसरा, व्हाइट हाउस पहुंचकर कौन काम कर सकता है? मेरा कहना है कि मैं ही ऐसा उम्मीदवार हूं जो दोनों काम कर सकता है। मैं जानता हूं कि ट्रंप से कैसे निपटना है।

कीवी टेस्ट के लिए तैयार टीम इंडिया

- भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से
- तेज व उछाल भरी पिच पर मिलेगी मेजबानों से कड़ी चुनौती

वेलिंगटन, प्रेट्र: देश-विदेश में विजय पताका फहराने वाली भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से यहां बेसिन रिजर्व की तेज और उछाल भरी पिच पर पहले टेस्ट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम का सामना करेगी तो उसके सामने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। शीर्ष टेस्ट रैंकिंग वाली विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम के 360 अंक हैं और कागजों पर उसका पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन केन विलियमसन की कीवी टीम संयम की पूंजी है जो इन पिचों पर उपयोगी साबित होगी। न्यूजीलैंड ने पिछली बार मार्च 2017 में अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज गंवाई थी। उसके बाद से उसने यहां 10 में से पांच टेस्ट जीते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के इरादे जीत की राह पर वापसी के होंगे, जबकि भारतीय टीम यह साबित करना चाहेगी कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत तुक्का नहीं थी और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीतने का तरीका उसे बखूबी आता है। विपरीत दिशा से आती हवाओं के कारण बेसिन रिजर्व गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल की नई सलामी जोड़ी को ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी और टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने जा रहे काइली जेमिसन जैसे आला दर्जे के गेंदबाजों का सामना करना है।

बायें हाथ के तेज गेंदबाज नील वैगनर की गैरमौजूदगी में भारतीय मध्यक्रम ने राहत की सांस ली होगी। वैगनर अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण ब्रेक पर हैं। न्यूजीलैंड की टीम में ऑलराउंडर डेरिल मिशेल और बायें हाथ के स्पिनर एजाज पटेल में से एक को जगह मिलेगी। भारतीय कप्तान कोहली टॉस जीतने पर गेंदबाजी चुन सकते हैं ताकि जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा और मुहम्मद शमी पिच से मिलने वाली शुरुआती मदद का फायदा उठा सकें। कोहली स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी टीम को पिच के अनुकूल होने का इंतजार करना होगा, जबकि विलियमसन की टीम इसी संयम के लिए जानी जाती है। कोहली ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी टीम में कितना संयम है, हमें और सब्र दिखाना होगा। हम ऐसे तैयारी नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड अपने संयम के दम पर हम पर दबाव बना दे।'

न्यूजीलैंड टीम चार तेज गेंदबाजों और एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है, जबकि भारतीय टीम प्रबंधन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उतार सकता है जिनके पास रवींद्र जडेजा से ज्यादा विविधता है। न्यूजीलैंड टीम चोट के बाद ट्रेंट बोल्ट और भारतीय टीम इशांत की वापसी से मजबूत हुई है। भारतीय टीम का भरॉसा तकनीक के धनी चेतेश्वर पुजारा, कोहली और अजिंक्य रहाणे पर होगा।

शास्त्री की 39 साल पुरानी यादें हुईं ताजा

वेलिंगटन, प्रेट्र: मुंबईया भाषा में 'खडूस' कहे जाने वाले रवि शास्त्री आम तौर पर जज्बात जाहिर नहीं करते, लेकिन बेसिन रिजर्व पर पहुंचकर वह यादों के गलियारों में चले गए। इसी मैदान पर 39 साल पहले उन्होंने भारत के लिए पहला टेस्ट खेला था। बड़ी बड़ी आंखों वाले शास्त्री ने 39 साल पहले 19 वर्ष की उम्र में भारत की 151वें नंबर की टेस्ट कैप पहनी थी। बेसिन रिजर्व पर ठंडी हवाओं के बीच छह फुट लंबे इस युवा क्रिकेटर तो तीन स्वेटर पहनने पड़े थे। लकड़ी की बैंचों और सफेद ग्रिल की सीमारेखा को निहारते अपनी तस्वीर के साथ शास्त्री ने ट्वीट किया, '39 वर्ष हो गए। इतिहास खुद को दोहराता है। कल यही दिन, यही मैदान, यही टीम और यही शहर होगा, जहां मैंने 39 साल पहले पहला टेस्ट खेला था। ड्रेसिंग रूम अब भी वही है। कुछ नहीं बदला।' शास्त्री को दरअसल विकल्प के तौर पर न्यूजीलैंड बुलाया गया था, क्योंकि दिलीप दोशी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर घायल हो गए थे। उस समय शास्त्री कानपुर में रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे। उस गेस्टहाउस के गेटकीपर से शास्त्री को अपने चुने जाने की खबर मिली थी, जिसमें मुंबई की टीम रह रही थी। मदन लाल जैसे मध्यम तेज गेंदबाजों को घरेलू स्तर पर खेलने वाले शास्त्री ने 10वें नंबर पर उतरकर 19 रन बनाए थे। उन्होंने स्पिन गेंदबाजी से 54 रन देकर तीन और नौ रन देकर तीन विकेट लिए थे। भारत वह टेस्ट 62 रन से हार गया, लेकिन शास्त्री अगले 11 साल तक भारत के लिए 80 टेस्ट और 150 वनडे खेले। शास्त्री अब अपनी टीम से जीत की नई पटकथा लिखने की उम्मीद कर रहे होंगे।

अभ्यास सत्र के दौरान अजिंक्य रहाणे से बात करते भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ● एएनआइ

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, इशांत शर्मा, मुहम्मद शमी, बुमराह, अश्विन, जडेजा।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डि ग्रैंडहोम, काइली जेमिसन, टॉम लाथम, डेरिल मिशेल, निकोल्स, एजाज पटेल, साउथी, टेलर, बीजे वाटलिंग।

57 टेस्ट मैच खेले गए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक। इनमें से भारत ने 21 और न्यूजीलैंड ने 10 जीते हैं। 26 टेस्ट ड्रॉ रहे

23 टेस्ट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक न्यूजीलैंड में खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने पांच और न्यूजीलैंड ने आठ टेस्ट जीते हैं। 10 टेस्ट ड्रॉ रहे

07 टेस्ट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें भारत ने एक और न्यूजीलैंड ने चार टेस्ट जीते हैं। दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे

खेल पर मेरे और कोहली के विचार एक जैसे : केन

वेलिंगटन, प्रेट्र : मैदान पर उनकी शख्सियत में भले ही जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन स्वभाव में अंतर के बावजूद केन विलियमसन और विराट कोहली एक-दूसरे के मुरीद हैं। आक्रामक कोहली और शांतचित्त विलियमसन मैदान के भीतर और बाहर एक-दूसरे के प्रशंसक हैं। विलियमसन और कोहली हाल ही में एक टी-20 मैच के दौरान सीमारेखा के पास बैठकर एक-दूसरे से बात कर रहे थे। विलियमसन ने कहा, 'हमने कई विषयों पर बात की और खूब मजा आया। खेल के बारे में हमारे विचार मिलते जुलते हैं। हमारा तरीका अलग है, लेकिन एक ऐसे कप्तान की सोच जानना प्रेरणास्पद था, जो अपने प्रतिस्पर्धी रवैये के साथ अगुआई करता है।' विलियमसन और कोहली अंडर-19 दौर से एक-दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। जूनियर विश्व कप 2008 में भी सेमीफाइनल में वे एक-दूसरे के सामने थे जो कोहली की टीम ने जीता। इसके 11 साल बाद सीनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जीत विलियमसन के नाम रही। विलियमसन ने कहा, 'मैं हमेशा से विराट का कायल रहा हूं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।'

कीवी कप्तान विलियमसन ● एएनआइ

संयम के साथ करेंगे सामना: विलियमसन ने कहा कि उनकी टीम पहले टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाजों इशांत शर्मा, मुहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का स्वागत 'जांचें और परखें' संयम के साथ करेगी। विलियमसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का उनकी सरजमीं पर सामना करने से यह बिलकुल अलग होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। उसमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क ने कीवी बल्लेबाजों को खेलने ही नहीं दिया। विलियमसन ने कहा, 'यहां हालात बिलकुल अलग हैं। भारत के पास विश्व स्तरीय तेज आक्रमण है जिसने हर हालात में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया में मिली हार के बाद हम निश्चित तौर पर जीत की राह पर लौटना चाहते हैं। हमने उस सीरीज से सबक लिया है, लेकिन हम यहां भी अपनी शैली में ही खेलेंगे।' बेसिन रिजर्व की पिच के बारे में उन्होंने कहा, 'यहां शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए भी यह आसान हो जाएगी। इसमें संतुलन है और सभी को मौका मिलेगा।' उन्होंने कहा कि विराट कोहली का विकेट अहम है, लेकिन उनकी टीम सिर्फ उन्हीं पर फोकस नहीं कर रही है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक प्रणाली अनुचित: विलियमसन को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक प्रणाली रास नहीं आ रही, जिसमें सीरीज कितने भी मैचों की हो, टीम को अधिकतम 120 अंक ही मिलेंगे । इसके अनुसार आगामी दो मैचों की सीरीज में हर मैच में जीतने पर 60 अंक दिए जाएंगे। वहीं एशेज में एक टेस्ट जीतने पर 24 ही अंक मिलेंगे, क्योंकि उसमें पांच मैच होते हैं। विलियमसन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह उचित है, लेकिन टेस्ट में प्रतिस्पर्धा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो पहले नहीं थे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह संपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले साल या दो साल बाद इसे बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इसका बेहतर रूप देखने को मिलेगा।'

न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी, पर 320 का स्कोर अच्छा : अजिंक्य

वेलिंगटन, प्रेट्र: पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी बताते हुए भारतीय उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि बेसिन रिजर्व की उछालभरी पिच पर पहली पारी में 320 रन का स्कोर अच्छा माना जाएगा। रहाणे ने कहा, 'घरेलू हालात में उन्हें पता है कि कैसी गेंद डालनी है और बल्लेबाजों को पता है कि कौन से शॉट खेलने हैं। एक इकाई के रूप में हमें हालात के अनुरूप तेजी से ढलना होगा। न्यूजीलैंड के हर मैदान का आकार अलग है।' भारत ने 2014 में लॉर्ड्स पर और 2018 में एडिलेड पर पहली पारी में 300 से कम स्कोर बनाकर जीत दर्ज की और रहाणे के अनुसार वेलिंगटन में भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, 'पहले बल्लेबाजी करते हुए आपकी मनोदशा एकदम सकारात्मक होती है। ऐसा नहीं है कि पहले गेंदबाजी करने पर ऐसा नहीं होता। भारत के बाहर पहली पारी में 320 या 330 का स्कोर अच्छा कहा जाएगा। हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जितने मैच जीते, पहली पारी में 320 या 350 के करीब रन बनाए थे। हमें पता है कि हमारे गेंदबाज हर हालात में विकेट ले सकते हैं, लेकिन टॉस हारने पर पहले बल्लेबाजी करनी पड़े तो पता होना चाहिए कि सामना कैसे करना है।'

पंत को दी सलाह: रहाणे ने कहा कि रिषभ पंत को स्वीकार करना होगा कि वह खराब दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें बतौर क्रिकेटर बेहतर होने पर फोकस जारी रखना होगा। 22 वर्ष के पंत पांच महीने पहले तक सभी प्रारूपों में विकेटकीपर के तौर पर भारत की पहली पसंद थे। रहाणे ने कहा, 'यह स्वीकार करना जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं। सकारात्मक रहकर ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। बात सीनियर या जूनियर की नहीं है। किसी को भी बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि टीम को उस दिन क्या जरूरत है।'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का उद्घाटन मुकाबला आज, हरमनप्रीत और मंधाना पर होंगी सभी की नजरें

जीत के साथ आगाज करना चाहेगी भारतीय महिला टीम

सिडनी, प्रेट्र: पहली आइसीसी ट्रॉफी जीतने के सपने संजोने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप के शुरुआती मैच में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई चुनौती का सामना करेगी। लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना भारत की कमजोरी रही है। ऑस्ट्रेलिया में त्रिकोणीय सीरीज में टीम फाइनल तक पहुंची थी। भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच गंवाया और एक जीता और फाइनल में मेजबान से हार गई।

ऑस्ट्रेलिया ने अब तक छह बार हुए टी-20 विश्व कप में चार बार जीत दर्ज की है। भारतीय मध्यक्रम और निचलेक्रम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हराया जा सके। टीम प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा कि मध्यक्रम बार-बार विफल साबित नहीं होने पाए। 16 वर्ष की शेफाली वर्मा से भारत को अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही कप्तान हरमनप्रीत कौर से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में पदार्पण करने वालीं 16 वर्ष की रिचा घोष को लगातार मौका मिलता है या नहीं, यह देखना होगा। गेंदबाजी में भारतीय टीम स्पिनरों पर काफी निर्भर है। आमतौर पर अंतिम एकादश में अकेली स्पिनर रहने वाली शिखा पांडे पर शुरुआती सफलता दिलाने की जिम्मेदारी रहेगी। पांडे ने कहा कि नई गेंद संभालने के कारण निश्चित तौर पर मैं शुरुआती कामयाबी के बारे में सोच रही हूं। भारतीय टीम से पिछली बार की तरह सेमीफाइनल में पहुंचने की तो उम्मीद है ही, लेकिन अगर उससे आगे कुछ होता है तो भारत में महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत होगी। कोच डब्ल्यूवी रमन ने कहा कि 2018 टी-20 विश्व कप से अब तक हालात बहुत बदले हैं। हमारे प्रदर्शन और बल्लेबाजी के रवैये में बदलाव आया है। भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से है जिसने हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज जीती है। टूर्नामेंट के पहले मैच से पूर्व ही उसे करारा झटका लगा जब उनकी प्रमुख तेज गेंदबाज तायला व्लाएमिंक पैर की चोट के कारण बाहर हो गईं। ऑफ स्पिनर मोली स्ट्रानो को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदार, लेकिन भारत भी कमजोर नहीं : मिताली

नई दिल्ली: अनुभवी मिताली राज ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ होने वाले आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत का प्रबल दावेदार बताया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस मुकाबले में काफी रन बनेंगे और यह बेहद करीबी मैच होगा। मिताली ने कहा कि भारत के पास कुछ बेहद प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि यह काफी करीबी मुकाबला होगा और इसमें काफी रन बनेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं, विशेषकर बल्लेबाजी क्रम में और यह इस पर निर्भर करेगा कि उस दिन अपने देश के लिए जरूरी रन कौन बनाता है। मिताली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के टी-20 रिकॉर्ड के कारण वे फायदे की स्थिति में हैं और भारत के खिलाफ पहला मैच जीतने की उनकी संभावना कुछ बेहतर है।

टी-20 महिला विश्व कप ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ● फाइल फोटो, प्रेट्र

भारत: हरमनप्रीत, तानिया, हरलीन, राजेश्वरी, रिचा, कृष्णामूर्ति, मंधाना, शिखा, अरुंधति, जेमिमाह, दीप्ति, पूजा, शेफाली, पूनम, राधा।

ऑस्ट्रेलिया: लैनिंग, एरिन, निकोला, एश्ले, रशेल, एलिसा, जेस, डेलिसा, सोफी, मूनी, एलिसे, मेगान, एनाबेल, मोली, जार्जिया।

जीत के लिए एक-दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकते : हरमनप्रीत

सिडनी: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम को टी-20 विश्व कप में एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर रहने की बजाय एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हरमनप्रीत ने कहा कि एक टीम के रूप में अच्छा खेलने के लिए आपको तालमेल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पिछले टूर्नामेंटों से हमने सीखा है कि एक या दो खिलाड़ियों पर ही जीत के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। भारतीय टीम रन बनाने के लिए हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना पर निर्भर रही है जिसकी बानगी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज में भी देखने को मिली। कप्तान ने कहा कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन जरूरी है और हम वही करेंगे।

भारतीय महिला पहलवानों ने जीते तीन स्वर्ण

एशियन कुश्ती चैंपियनशिप

- दिव्या, सरिता और पिंकी ने अपने-अपने वर्गों में जीते स्वर्ण पदक
- निर्मला को करना पड़ा रजत पदक से संतोष

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: दिव्या काकरान, सरिता मोर और पिंकी ने गुरुवार को यहां अपने-अपने वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जिससे भारत ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धाओं में पहले दिन दबदबा बनाया। मेजबानों के लिए दिन यादगार रहा जिसमें भारतीय पहलवान पांच में से चार के फाइनल में पहुंची और दिव्या (68 किग्रा), पिंकी (55 किग्रा) और सरिता (59 किग्रा) ने शीर्ष स्थान हासिल किया। निर्मला देवी को 50 किग्रा में रजत से संतोष करना पड़ा, जबकि किरण (76 किग्रा) ही एकमात्र पहलवान रहीं जो पदक हासिल नहीं कर सकीं।

चित से जीते काकरान ने सभी मुकाबले: जकार्ता एशियन गेम्स की कांस्य विजेता दिव्या ने अपने सारे मुकाबले प्रतिद्वंद्वियों को चित करके जीते जिसमें जापान की जूनियर विश्व चैंपियन नरूहा मातसुयुकी को हराना भी शामिल रहा। दिव्या ने पांच पहलवानों के 68 किग्रा वर्ग में अपने चारों मुकाबले जीते जो राउंड रोबिन प्रारूप में खेले गए। उन्होंने पहले कजाखिस्तान की एलबिना कैरजेलिनोवा को हराया और फिर मंगोलिया की डेलगेरमा एंखसाइखान को मात दी। तीसरे दौर में दिव्या का सामना उज्बेकिस्तान की एजोडा एसबर्जेनोवा से था और उन्होंने 4-0 की बढ़त बनाने के बाद अपनी प्रतिद्वंद्वी को महज 27 सेकेंड में मात दी। जापान की जूनियर विश्व चैंपियन के खिलाफ दिव्या ने 4-0 की बढ़त हासिल कर ली। जापानी पहलवान ने दूसरे राउंड में मजबूत शुरुआत की और भारतीय पहलवान के बायें पैर पर हमला किया, लेकिन उन्होंने अंक दायें पैर पर आक्रमण से जुटाए जिससे स्कोर 4-4 हो गया। दिव्या ने हालांकि फिर प्रतिद्वंद्वी को चित कर दिया। इसके बाद रेफरी ने उन्हें 6-4 से विजेता घोषित किया।

स्वर्ण पदक के साथ पिंकी ● प्रेट्र

तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतीं सरिता: सरिता 2017 में 58 किग्रा में रजत पदक जीतने के बाद अपनी पहली एशियाई प्रतियोगिता में भाग ले रही थीं। उन्होंने कजाखिस्तान की मदीना बाकबेरजेनोवा और किर्गिस्तान की नाजिरा मार्सबेकिजी के खिलाफ अपने पहले दो मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीते। इसके बाद उन्होंने जापान की युमी कोन पर 10-3 से जीत हासिल की। उन्होंने फाइनल में मंगोलिया की बातसेतेग अटलांटसेतसेग को 3-2 से हराया। पहली बार सीनियर एशियन प्रतियोगिता में भाग ले रहीं पिंकी ने उज्बेकिस्तान की शोकिदा अखमेदोवा को चित करके शुरुआत की और फिर अगले मुकाबले में जापान की काना हिगाशिकावा को हराया। फिर उन्होंने सेमीफाइनल में मारिना जुयेवा को 6-0 से हराया। उन्होंने मंगोलिया की डुलगुन बोलोरमा पर 2-1 की जीत से स्वर्ण जीता।

भारत में भी खेलो में अमेरिका जैसी शुरुआत बड़ा कदम

पुलेला गोपीचंद

स्मैश

पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुक्रवार से ओडिशा में शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की ये खेल मंत्रालय की शानदार पहल है। खेलो इंडिया ने ग्रास रूट स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशने व तराशने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। अब इन गेम्स को यूनिवर्सिटी स्तर पर शुरू किया जा रहा है, जिससे अंडर-25 वर्ग में खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पदक विजेता खिलाड़ियों को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तराशा जा सकता है। यहां तक कि ओलंपिक के लिए भी।

दुनियाभर में बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभा तलाशने का काम यूनिवर्सिटीज में ही होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका को ही ले लीजिए। वहां यूएसए नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन चैंपियनशिप का स्थान अहम है। 2018-19 में अकेले डिविजन-1 में ही 1.82 लाख एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि ऐसी तीन डिविजन हैं। इसमें जीतने वाले प्रतिभागी सभी बड़े टूर्नामेंटों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्भाग्य से भारत में हम लंबे समय तक खेल और शिक्षा को दो अलग-अलग रूप में रखते रहे, जबकि ये महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षण संस्थानों को अकादमिक केंद्र के तौर पर न देखें, बल्कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भी देखें।

फिंच को सता रहा है द. अफ्रीका में छींटाकशी का डर

साक्षात्कार

मार्च, 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंद से छेड़छाड़ के मामले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर एक साल का प्रतिबंध लगा था और उसके बाद से वे दोनों खिलाड़ी जब भी मैदान पर उतरे हैं, उन्हें छींटाकशी का सामना करना पड़ा है। अब जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज में भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच को छींटाकशी का ही डर सता रहा है। इस सीरीज व अन्य मुद्दों पर **आरोन फिंच** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

- **क्या यह दौरा टी-20 विश्व कप को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण है?**

-चोट के कारण ग्लेन मैक्सवेल इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैक्सवेल के नहीं खेलने से टीम को नुकसान हुआ है। वह शानदार खिलाड़ी हैं। डि आर्ची शॉर्ट और अन्य खिलाड़ियों के पास मैदान पर खुद को साबित करने का मौका है। आर्ची शॉर्ट आक्रामक बल्लेबाज हैं और बायें हाथ से स्पिन गेंदबाजी कभी करते हैं। वह क्षेत्ररक्षण में भी योगदान देते हैं।

- **डुप्लेसिस के बारे में क्या कहेंगे, अब वह टीम के कप्तान भी नहीं हैं?**

-डुप्लेसिस का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित प्रारूपों की सीरीज में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वह दमदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने देश के लिए कई साल तक नेतृत्वकर्ता के तौर पर योगदान दिया है। हर हालात में उन्होंने टीम के लिए अपना 100 प्रतिशत दिया है। उन्होंने टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली हैं।

- **क्या ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के प्रशंसकों से छींटाकशी की उम्मीद है?**

-मैं उनके प्रशंसकों से इस चीज की उम्मीद कर रहा हूं। उनके प्रशंसक हमेशा से प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन हम गर्व से अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **हाल ही में दक्षिण अफ्रीका अपने घर में इंग्लैंड से टी-20 सीरीज हारी है, क्या इससे आपकी टीम को फायदा होगा?**

-इंग्लैंड के खिलाफ सफेद गेंद की क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने प्रभावित किया है। यह सीरीज अच्छी रही थी और मैंने इस सीरीज को ध्यान से देखा था। इंग्लैंड के इयोन मोर्गन ने बल्ले से अच्छा योगदान दिया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है और कई नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं। नंबर एक से लेकर 11 तक के उनके खिलाड़ी अपना प्रभाव डालते हैं।

- **क्विंटन डिकॉक की कप्तानी में ही दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवाई है?**

-मैं दक्षिण अफ्रीका के नए कप्तान डिकॉक से प्रभावित हूं। उनके ऊपर टीम की कमान के अलावा और भी जिम्मेदारी हैं। वह सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं। सलामी बल्लेबाज को शुरुआत से टीम के स्कोर बोर्ड को चलाना होता है और फिर विकेट के पीछे खड़े रहकर मुस्तैदी दिखानी होती है।

मजबूत ऑस्ट्रेलिया की चुनौती से पार पाने उतरेगा भारत

प्रो हॉकी लीग

- मनप्रीत की अगुआई वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में
- भारत के खिलाफ पिछले 30 में से 22 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने

भुवनेश्वर, प्रेट्र: मेजबान भारत एफआइएच प्रो लीग में शुक्रवार को मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी चुनौतियों से पार पाने उतरेगा तो उसका इरादा अपनी शानदार फॉर्म को कायम रखने का भी रहेगा। भारत ने एफआइएच प्रो हॉकी लीग में पदार्पण करते हुए शानदार शुरुआत की और चार मैचों में आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ छह में से पांच अंक बनाए। इसके बाद विश्व और यूरोपीय चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज करके तीन अंक हासिल किए। बेल्जियम ने दूसरा मैच 3-2 से जीता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ग्राहम रीड की कोचिंग में भारत ने पिछले कुछ समय में शानदार हॉकी खेली है। इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम लीग के अगले कुछ मैच विदेश में खेलेगी। दुनिया की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पिछले 30 में से 22 मैच जीते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कोच का एफआइएच पुरस्कार जीतने वाले कोलिन बैच ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कलिंगा स्टेडियम पर चैंपियंस ट्रॉफी 2014 सेमीफाइनल में जर्मनी से मिली हार के बाद निर्धारित समय में कोई मैच नहीं गंवाया है। इसी मैदान पर 2017 हॉकी विश्व लीग फाइनल में सभी छह मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया अपराजेय रहा था। इसके बाद 2018 विश्व कप सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने उसे पेनाल्टी शूटआउट में हराया था। ऑस्ट्रेलिया इस समय लीग में चार मैचों में छह अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। बेल्जियम के खिलाफ दो मैचों में उसे एक ही अंक मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों के बाद भारतीय टीम जर्मनी (25 और 26 अप्रैल) और ब्रिटेन (दो और तीन मई) में खेलेगी। इसके बाद 23 और 24 मई को न्यूजीलैंड से यहां खेलना है।

हीरो इंडियन ओपन में चुनौती पेश करेंगे भारतीय गोल्फर

नई दिल्ली, आइएएनएस : अगले महीने होने वाले हीरो इंडियन ओपन के 56वें संस्करण में इस साल यूरोपीयन और एशियाई टूर चैंपियनों सहित कई भारतीय गोल्फर अपनी-अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 22 मार्च तक गुरुग्राम के डीएलफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में होगा, जिसमें 17 .5 लाख डालर की पुरस्कार राशि दांव पर होगी।

हम सभी आइसीसी टी-20 महिला विश्व कप को लेकर उत्साहित हैं।
- शेफाली वर्मा, भारतीय महिला क्रिकेटर

वर्नर के गोल से लीप्जिग ने टॉटनहम को हराया

फुटबॉल डायरी ▶ टीमो ने पेनाल्टी पर किया एकमात्र गोल, चोट के कारण मैच में नहीं खेले टॉटनहम के सोन और हैरी

लंदन, रायटर : टीमो वर्नर के पेनाल्टी पर किए गोल की मदद से आरबी लीप्जिग ने यहां यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के पहले चरण के मुकाबले में टॉटनहम को 1-0 से हरा दिया। अपने घर में खेल रही मैनेजर जोश मॉरिन्हो की टीम टॉटनहम मैच जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन मैनेजर यूलियन नेगल्समैन की टीम लीप्जिग ने उसकी मैच जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जर्मनी का क्लब लीप्जिग पहली बार इस लीग में नॉकआउट चरण का मैच खेल रहा है और टीम इसे जीतने की हकदार थी। अब दोनों टीमों के बीच दूसरे चरण का मुकाबला 10 मार्च को खेला जाएगा।

टॉटनहम को अपने मुख्य स्ट्राइकरों सोन ह्यूंग-मीन और हैरी केन की कमी खली। उन दोनों की अनुपस्थिति के कारण ही टीम मैच में एक भी गोल नहीं कर पाई। दोनों स्टार स्ट्राइकर चोट के कारण इस मैच में खेलने नहीं उतरे। उन दोनों की जगह अंतिम एकादश में मॉरिन्हो ने क्रमशः डेले अली और लुकास मौरा को शामिल किया, लेकिन दोनों ने टीम को निराश किया।

लीप्जिग की टीम ने आक्रामक अंदाज में फुटबॉल खेलना शुरू किया। मेजबान टीम ने तेज शुरुआत की और वर्नर ने दूसरे मिनट में ही गोल भी कर दिया था, लेकिन इस ऑफ साइड करार दे दिया गया। इसके बाद 36वें मिनट में वर्नर के पास एक बार फिर गोल करने का मौका आया, लेकिन टॉटनहम के गोलकीपर हुगो लोरिस ने इसका अच्छी तरह से बचाव किया। पहला हाफ गोलरहित रहा, लेकिन इस हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने अच्छा काम किया। दूसरे हाफ में लीप्जिग को फ्री किक मिली और इस बार भी गोल करने का अच्छा मौका था, लेकिन फ्री किक से मिली गेंद को मिडफील्डर क्रिस्टोफर नुनकू का शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से चला गया। इस बीच, गेंद पर पकड़ बनाने के चक्कर में टॉटनहम के बेन डेविस की लीप्जिग के कोनराड लैमर से टक्कर होने के कारण रेफरी ने इसे फाउल मानते हुए डेविस को येलो कार्ड दिखाकर लीप्जिग को पेनाल्टी दे दी। फिर 58वें मिनट में वर्नर ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर लीप्जिग को मैच में उपयोगी बढ़त दिलाई। हालांकि इसके बाद टॉटनहम के गोलकीपर हुगो लोरिस ने एक और अच्छा बचाव करके टीम को राहत दी। मैच में बराबरी का गोल करने की कवायद में जुटी मॉरिन्हो की टीम के पास एक अच्छा मौका आया था जब फ्री किक पर गियोवानी लो सेल्सो के शॉट को गोलकीपर पीटर गुलाची ने रोक दिया। मेहमान टीम ने मैच के अंत तक इस बढ़त को कायम रखते हुए जीत हासिल की।

टॉटनहम के खिलाफ गोल करने के बाद साथी खिलाड़ियों संग जश्न मनाते आरबी लीप्जिग के टीमो वर्नर (मध्य)। एपी

हमारे लिए यह मैच अच्छा रहा। हम टॉटनहम को अपनी रणनीति के तहत खिलाते रहे, लेकिन गोल का अंतर कुछ कम रह गया।
- टीमो वर्नर, स्ट्राइकर, आरबी लीप्जिग

07
वां गोल आरबी लीप्जिग के टीमो वर्नर ने चैंपियंस लीग के इस सत्र में किया है

अटलांटा ने वेलेंसिया को दी आसानी से शिकस्त

मिलान, रायटर : अटलांटा ने यहां यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के पहले चरण के मुकाबले में वेलेंसिया को 4-1 से शिकस्त दी। अटलांटा के लिए हैंस हेटबाएर (16वें व 62वें मिनट), जोसिप इलिचिक (42वें मिनट) और रेमो फ्रयूलर (57वें मिनट) ने गोल किए, जबकि वेलेंसिया के लिए एकमात्र गोल स्थानापन्न खिलाड़ी डेनिस चेरिशेव ने 66वें मिनट में किया। दो बार की उप विजेता वेलेंसिया अब दूसरे चरण के मैच की मेजबानी अपने घर में 10 मार्च को करेगी। अटलांटा ने पहली बार यूरोप के शीर्ष टूर्नामेंटों के लिए क्वालीफाई किया है और पिछले सत्र में सीरी-ए लीग में तीसरे स्थान पर रहा था।

मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हम को दी 2-0 से मात

मैनचेस्टर, आइएएनएस : यूएफा द्वारा लगाए गए दो साल के प्रतिबंध का मैनचस्टर सिटी पर किसी तरह का असर नहीं दिखा और टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के मैच में वेस्ट हम युनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी के पास शुरुआती बढ़त लेने का मौका आया, लेकिन ग्रैबियल जीसस ने वेस्ट हम के गोलकीपर लुकास फाबियानस्की के साथ वन ऑन वन के मौके को गंवा दिया। हालांकि, मेजबान टीम को बढ़त लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। आधे घंटे का समय निकल जाने के बाद केविन डि ब्रूयन ने रोड्रिगो के लिए मौका बनाया और रोड्रिगो गोल करने में सफल रहे। दूसरे हाफ में डि ब्रूयन ने बर्नाडो सिल्वा के पास पर गोल करते हुए मेजबान टीम को 2-0 से आगे कर दिया।

यूएफा के आरोप गलत : मैनचेस्टर सिटी सीईओ

लंदन, आइएएनएस : इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) फेरान सोरियानो ने कहा है कि क्लब पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप गलत हैं। यूएफा ने पिछले सप्ताह ही क्लब को लाइसेंस और वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण यूरोपियन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सोरियानो ने कहा, 'सबसे अहम चीज जो मुझे कहनी है वो यह है कि क्लब के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है। वह पूरी तरह से गलत है। मालिक ने क्लब में वो पैसा नहीं लगाया है जिसकी घोषणा नहीं की गई। हम टिकाऊ क्लब हैं, हम फायदे में चल रहे हैं। हमारे ऊपर कर्ज नहीं है। ऑडिटर्स, रेग्यूलेटर्स, निवेशकों द्वारा हमारे खातों की कई बार जांच हो चुकी है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई।

आइपीएल फ्रेंचाइजी ने ऑल स्टार मैच पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली, आइएएनएस : इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के 13वें संस्करण से पहले खेले जाने वाले ऑल स्टार मैच पर काले बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि फ्रेंचाइजियों ने इस मैच को लेकर आपत्ति जताई है। बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली की ख्वाहिश थी कि आइपीएल की शुरुआत से पहले 25 मार्च को शीर्ष खिलाड़ियों को मिलाकर एक मैच खेला जाए, लेकिन अब इस पर पानी फिरता दिख रहा है।

फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने कहा कि यह मैच लीग की तैयारियों का समय खा जाएगा और फ्रेंचाइजी यह नहीं चाहती हैं। अधिकारी ने कहा कि बड़े नाम टूर्नामेंट की शुरुआत से एक सप्ताह पहले भारत आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप खिलाड़ियों को 25 मार्च को होने वाले ऑल स्टार मैच खेलने की अनुमति देते हो तो वह 23 मार्च की रात या 24 मार्च की सुबह रवाना हो जाएंगे। अगले दिन वो खेलेंगे और 26 मार्च को वापस लौट आएंगे और फिर टूर्नामेंट 29 मार्च को शुरू होगा। क्या इसका कोई औचित्य है? साथ ही क्या, यह फ्रेंचाइजियों के लिए सही है? मुझे नहीं लगता। एक और अधिकारी ने कहा कि ऑल स्टार मैच में महेंद्र सिंह धौनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ियों को खेलना होगा। बोर्ड ने इस विचार को लाने से पहले फ्रेंचाइजियों से बात तक नहीं की थी। अधिकारी ने कहा कि हमारे पास मीडिया से यह खबर आई की ऑल स्टार मैच का आयोजन किया जा सकता है।

आइपीएल डायरी

राजस्थान हाई कोर्ट ने आइपीएल की सुनवाई 17 मार्च तक टाली

जयपुर, आइएएनएस : राजस्थान रॉयल्स की आइपीएल 2020 के कुछ मैच गुवाहाटी में कराने की योजना को झटका लग सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए टाल दी है। राजस्थान रॉयल्स के अपने कुछ घरेलू मैचों को स्थानांतरित करने के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिस पर हाई कोर्ट को गुरुवार को फैसला देना था, लेकिन अब मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

बीसीसीआइ ने हालांकि फ्रेंचाइजी के फैसले का समर्थन किया था और साफ तौर पर कहा था कि दूसरे गृहनगर की अपील करने में फ्रेंचाइजी ने किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। कुछ दिन पहले जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक, रॉयल्स की टीम को दो अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स और पांच अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है। यह दोनों मैच या तो जयपुर या गुवाहाटी में आयोजित होने हैं। इसके बाद नौ अप्रैल को रॉयल्स को जयपुर या गुवाहाटी में कोलकाता नाइटराइडर्स की मेजबानी करनी हैं।

फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगे चोटिल फेडरर

पेरिस, एएफपी : स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लंबे समय से चली आ रही घुटने की समस्या को दूर करने के लिए सर्जरी कराई है और गुरुवार को उन्होंने कहा कि वह फ्रेंच ओपन सहित कई टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता ने अपने फेसबुक अकाउंट से प्रशंसकों के साथ यह जानकारी साझा की। उन्होंने बुधवार को स्विट्जरलैंड में सर्जरी कराई और वह 24 मई से सात जून तक चलने वाले फ्रेंच ओपन सहित कई टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ समय से मेरा दायां घुटना मेरी चिंताएं बढ़ा रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह सही हो जाएगा, लेकिन कुछ जांच और अपनी टीम से बातचीत के बाद मैंने बुधवार को स्विट्जरलैंड में ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी कराने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के बाद डॉक्टरों ने बताया कि यह (ऑपरेशन) सही चीज थी, जो की जानी थी और उन्हें (डॉक्टरों) बहुत विश्वास है कि यह पूरी तरह सही हो जाएगा। परिणामस्वरूप, मैं दुबई, इंडियन वेल्स, बोगोटा, मियामी और फ्रेंच ओपन में भाग नहीं ले पाऊंगा। मैं हर किसी के समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं दोबारा खेलने के लिए बेकरार हूं।

टेनिस डायरी

दिविज-आर्टेम ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

फ्लोरिडा, प्रेट्र : भारत के दूसरे नंबर के डबल्स खिलाड़ी दिविज शरण ने न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार आर्टेम सिटाक के साथ मिलकर यहां आंद्रे गोरानसन और यूगो हंबर्ट की जोड़ी को 5-7, 6-4, 10-7 से हराकर डेलरे बीच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दिविज-आर्टेम का सामना अब शुक्रवार को माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन की अमेरिकी जोड़ी से होगा। दिविज ने कहा कि यह निश्चित रूप से कठिन मैच था।

मजूमदार, अहमद ने बंगाल को बचाया

रणजी ट्रॉफी

कटक, प्रेट्र : अनुस्तूप मजूमदार (नाबाद 136) और शहबाज अहमद (नाबाद 82) ने सातवें विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी कर यहां डीआरईएमएस ग्राउंड पर खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के पहले दिन शुक्रवार को बंगाल को मेजबान ओडिशा के खिलाफ पहली पारी में सस्ते में सिमटने से बचा लिया।

इन दोनों के बीच यह साझेदारी तब आई जब टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने छह विकेट सिर्फ 141 रनों पर ही खो दिए थे। यहां से इन दोनों ने ओडिशा के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया और बंगाल ने पहले दिन का अंत छह विकेट के नुकसान पर 308 रनों के साथ किया। मजूमदार ने अभी तक अपनी पारी में 194 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके लगाए हैं। शहबाज ने 154 गेंदें खेलीं हैं और 13 चौके मारे हैं। इससे पहले, ओडिशा ने बंगाल को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (07), कौशिक घोष (09), अभिषेक (01), अर्नब (24) और मनोज तिवारी (04) पवेलियन लौट लिए। ओडिशा के लिए सूर्यकांत और कंवर ने दो-दो विकेट लिए।

सौराष्ट्र ने पहले दिन बनाए छह विकेट पर 226 रन

अंगोले (आंध्र प्रदेश), प्रेट्र : सौराष्ट्र ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतकों की मदद से यहां खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच के पहले दिन गुरुवार को अपनी पहली पारी में आंध्र के खिलाफ दिन का खेल समाप्त होने तक छह विकेट पर 226 रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक चिराग जानी 128 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से नाबाद 53 रन बनाकर लौटे।

बारिश ने डाली जम्मू-कश्मीर के अभियान में बाधा

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहले दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में खेले जा रहे मुकाबले में गुरुवार को महज छह ओवर डाले जा सके। कर्नाटक ने इस दौरान दो विकेट के नुकसान पर 14 रन बनाए। दोपहर तीन बजे अंपायर ने मैदान का मुआयना किया।

विविध

उत्तराखंड पुलिस ने गुब्बारों व बैनर को कब्जे में लिया

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ : उत्तराखंड के जिले के कोटयूड़ा गांव में गैस के गुब्बारों के साथ एक पेड़ में फंसे मिले पाकिस्तान में आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप के बैनर मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुब्बारे व बैनर को पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं, जिसमें पुलिस को कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है। बैनर व गुब्बारों के चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ को कोटयूड़ा गांव में मिलने को लेकर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। खुफिया एजेंसियों ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

बुधवार को कोटयूड़ा गांव की महिलाओं ने जंगल में हरे और सफेद रंग के गुब्बारों का गुच्छा देखा। गुब्बारों से एक बैनर भी बंधा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान में फरवरी के पहले हफ्ते में आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप-2020 का जिक्र होने के साथ ही एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी का बैनर लगा हुआ था। पाकिस्तान में हुए कबड्डी वर्ल्ड कप से जुड़ी प्रचार सामग्री के सीमांत क्षेत्र में पहुंचने से पुलिस हरकत में आई। नाचनी थाने से पुलिस का दल देर रात कोटयूड़ा गांव पहुंचा और गुरुवार को गुब्बारे व बैनर को कब्जे में लिया। पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शिनी ने बताया कि कोटयूड़ा में जो सामग्री मिली है, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया।

ममता ने मोदी को लिखा पत्र, बंगाल के लिए फंड की कटौती पर चिंतित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- **कहा, जनवरी तक 50 हजार करोड़ के कुल केंद्रीय फंड का हिस्सा बंगाल को अब तक नहीं मिला**
- **फंड जारी करने में देरी के चलते प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हो रही मुश्किल**

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का पुरजोर विरोध कर रहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए केंद्रीय फंड में कटौती और फंड जारी करने में अप्रत्याशित देरी पर चिंता प्रकट की। ममता ने अपने पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांच फीसद दर रहने की तुलना में बंगाल की जीडीपी दोगुनी से ज्यादा 10.4 फीसद से आगे बढ़ीं। ममता ने लिखा कि केंद्र सरकार से बंगाल के लिए केंद्रीय फंड में कटौती और हमारे लिए धनराशि जारी करने में अप्रत्याशित देरी को लेकर गहरी चिंता के साथ मैं पत्र लिख रही हूं। उन्होंने कहा कि राज्य को जनवरी 2020 तक 50 हजार करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय फंड का अपना हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि फंड जारी करने में अप्रत्याशित देरी के चलते राज्य के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने पत्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से संबंधित फंड में कटौती आदि का भी पूरा विवरण दिया है।

हाल में पेश किए गए राज्य बजट के बाद ममता ने दावा किया था कि यदि सभी बकाया को मिला दिया जाए तो केंद्र पर बंगाल का 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इससे पहले पिछले महीने 11 जनवरी को पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम के सिलसिले में जब पीएम मोदी कोलकाता के दो दिवसीय दौरे पर आए थे, उस दौरान भी ममता ने राजभवन में पीएम से मुलाकात कर बकाया 38 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार का तर्क है कि उसमें बाकी बकाया को नहीं जोड़ा गया था। राज्य बजट के बाद पता चला कि बंगाल का केंद्र के पास 90 हजार करोड़ से अधिक का बकाया है।

ममता बनर्जी। फाइल

मुसलमान नहीं, मानवता का करती हूं तुष्टीकरण : ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : ममता बनर्जी ने खुद पर मुसलमानों के तुष्टीकरण के लगने वाले आरोपों का गुरुवार को खुलकर जवाब दिया। कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की जयंती के उपलक्ष में नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा-'कुछ लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों को तुष्ट करती हूं लेकिन मैं असल में मानवता को तुष्ट करती हूं। आजकल कुछ लोग धर्म को लेकर बेतुकी बातें कर रहे हैं। उन्हें जो अच्छा लगेगा, उन्हें रखना चाहते हैं और जो अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें बाहर कर देना चाहते हैं। हम इस तरह के धर्म में विश्वास नहीं करते।' पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बंगाल में तृणमूल के खराब प्रदर्शन से खफा होकर ममता ने कहा था-'मैं मुसलमानों को तुष्ट करती हूं। जो गाय दूध देती है, उसकी लात भी अच्छी होती है।' उनके इस बयान को भी भाजपा ने खूब उछाला था और कहा था कि ममता के मन की बात उनकी जुबान पर आ गई है।

चिन्मयानंद की जमानत के खिलाफ पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चिन्मयानंद पर उनके ट्रस्ट के कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यह मामला उप्र में शाहजहांपुर का है। चिन्मयानंद को इस आरोप में पिछले वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन फरवरी को चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दोनों पक्षों ने अपनी सीमाएं लांघी। इस समय यह कह पाना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया। दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया।

गुरुवार को पीड़िता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई की सहमति दे दी। यह मामला पिछले वर्ष उस समय उछला था जब कानून की छात्रा ने वीडियो क्लिप जारी कर चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया और उसके बाद वह गायब हो गई। तब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्रा को ढूंढकर पेश करने की मांग की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था।

पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की राह आसान करेगा 'ट्रैक्ड्रील'

अभय कुमार पांडेय, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)

प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर पहाड़ की खेती आसान नहीं। जुताई की झंझट के साथ सिंचाई की चिंता अलग से। किसानों की मुश्किल को कुछ हद तक आसान करने की कोशिश की है महाराष्ट्र के श्रीलेश माडेय ने। पहाड़ी खेतों की जुताई के लिए विशेष ट्रैक्टर डिजाइन किया है। नाम दिया है ट्रैक्ड्रील। काशीपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में तीन माह के प्रशिक्षण के बाद उन्हें यह सफलता मिली। इससे प्रभावित होकर आइआइएम ने कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को फंड जारी करने की संस्तुति की है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो पांच से छह लाख में मिलने वाले ट्रैक्टर के विकल्प के तौर ट्रैक्ड्रील मात्र दो लाख में ही किसानों को मिल सकेंगे। ट्रैक्ड्रील को पहाड़ की खेती के अनुसार डिजाइन किया गया है। इससे वह ऊंची चढ़ाई आसानी से पार करने में सक्षम है। इसे कम जगह में मोड़ा जा सकता है। ऐसे में किसानों को जुताई और फॉगिंग करने में आसानी होगी।

महाराष्ट्र के पुणे जिले के ओजर गांव निवासी श्रीलेश माडेय के पिता किसान हैं। खेती को सुगम बनाने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति से मजबूर रहे। गन्ने की खेती के लिए पॉवर ट्रिलर खरीदा, जिसे चलाना आसान नहीं था। यहीं से ट्रैक्ड्रील की सोच शुरू हुई। इसे साकार करने के लिए श्रीलेश हाई स्कूल के बाद से ही जुट गए। महाराष्ट्र के शिवनगर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इस दौरान ही वर्ष 2013 में श्रीलेश ने ट्रैक्टर का पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अब ट्रैक्ड्रील के मॉडल का नया रूप मिला।

श्रीलेश के सपनों को पंख देने का काम विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। स्टार्टअप के तहत आइआइएम काशीपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के तहत तीन माह का प्रशिक्षण भी दिया गया। मॉडल की प्रस्तुति के लिए मंत्रालय ने 10 लाख रुपये का बजट दिया। इसके बाद 25 लाख की अतिरिक्त मंजूरी के लिए कृषि मंत्रालय को भी प्रोजेक्ट भेजा गया।

पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को आसान करने के लिए महाराष्ट्र के श्रीलेश माडेय (दाएं) ने ट्रैक्ड्रील ट्रैक्टर तैयार किया है। इससे पूरी टीम (बाएं से) अमित, प्रतीक और मंजेश भी उत्साहित हैं। जागरण

अब इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज जंक्शन कहिए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- **सवा साल बाद जिले के चार रेलवे स्टेशनों के नाम बदले**
- **कुंभ मेले से पहले शुरू हुई थी नाम बदलने की कवायद**

प्रयागराज जिले के तमाम स्टेशनों के नाम भी अब प्रयागराज से ही शुरू होंगे। मसलन इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन कहा जाएगा। कुंभ मेले से पहले ही इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज कर दिया गया था। नगर निगम, विकास प्राधिकरण समेत अन्य विभागों में नाम बदल गया था, लेकिन शहर के स्टेशनों का नाम बदलने में सवा साल लग गए।

2018 में जिले का नाम बदलने के बाद स्टेशनों के नाम बदलने के लिए जिला प्रशासन ने शासन और रेल मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी। वहां से पत्र गृह मंत्रालय को भेजा गया। गृह मंत्रालय से स्टेशनों के नाम बदलने की स्वीकृति मिलने के बाद शासन से पत्र जारी हो गया है। प्रयाग जंक्शन के नाम में कोई बदलाव नहीं है। सूबेदारगंज स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव भी था, लेकिन गृह मंत्रालय ने फिलहाल उसके लिए कोई पत्र नहीं जारी किया है। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी का कहना है कि गृह मंत्रालय की चिट्ठी मिलते ही तत्काल स्टेशनों का नाम बदल दिया जाएगा।

वर्तमान	परिवर्तित
इलाहाबाद जंक्शन	प्रयागराज जंक्शन
इलाहाबाद सिटी	प्रयागराज रामबाग
इलाहाबाद छिवकी	प्रयागराज छिवकी
प्रयागघाट	प्रयागराज संगम

रेलमंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट : 'केंद्र व उप्र सरकार ने प्रयागराज जिले में स्थित स्टेशनों के नाम को प्रयागराज से प्रारंभ होने वाले शब्दों पर रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्राचीन नगर की पहचान वापस मिलेगी।'

एनएचआरसी के पास होनी चाहिए और शक्तियां : दत्तू

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष एचएल दत्तू ने गुरुवार को कहा कि आयोग के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए, जिससे राज्य उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य हो जाएं। अभी राज्य आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

एनएचआरसी प्रमुख ने कहा कि वह केंद्र के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने प्राधिकारों को पत्र भी लिखा है। यहां एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा, 'हमारी सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। वे चाहें तो हमारी सिफारिशें लागू कर सकती हैं और चाहे तो नहीं। अगर वे हमारी सिफारिशें लागू नहीं करती हैं तो हमें कोर्ट जाना पड़ता है।' सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दत्तू ने कहा, 'अगर सिफारिशों को राज्यों में लागू कराया जाना अनिवार्य कर दिया जाए तो वह ज्यादा प्रभावी होगा। एनएचआरसी को अपनी सिफारिशों को लागू करवाने और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।'

मौसम विशेष

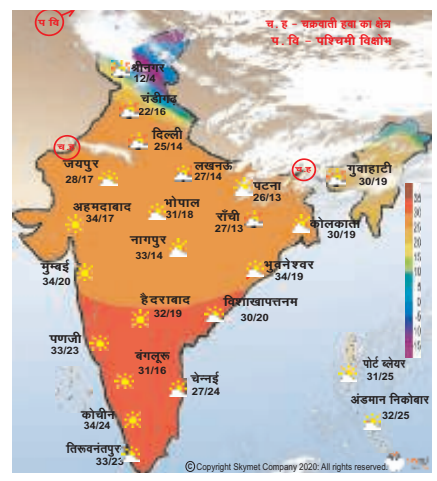

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में गरज और तेज हवाओं के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में घने बादल छाये रहेंगे। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा और बर्फबारी जारी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/19/सा	अहमदाबाद	35/12/आंबा
कोलकाता	29/19/ब	बड़ौदा	35/12/सा
चेन्नई	31/22/ब	नागपुर	34/15/सा
हैदराबाद	31/18/आंबा	इन्दौर	31/17/आंबा
बंगलूरू	31/17/आंबा	रांची	25/12/ब
त्रिवेन्द्रम	34/24/आंबा	पटना	24/14/आंबा
गुवाहाटी	30/17/आंबा	जमशेदपुर	30/14/आंबा
जंगटोक	11/08/सा	पुणे	34/19/सा

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

शुक्रवार 21 फरवरी 2020

16

www.jagran.com

लाहौर घोषणापत्र पर हुए हस्ताक्षर

आज ही के दिन 1999 में लाहौर में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा के दौरान हुए इस समझौते ने संबंधों को पटरी पर लाने का काम किया।

पहली टेलीफोन डायरेक्टरी का हुआ प्रकाशन

आज ही के दिन वर्ष 1878 में अमेरिका में पहली टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन हुआ। इसे एक गत्ते पर प्रकाशित किया गया। इस डायरेक्टरी में न्यूहैवन के 50 लोगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नंबर थे। पहली ब्रिटिश टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन 15 जनवरी 1880 में हुआ था।

भारतीय शोध प्रयोगशालाओं के जनक शांति स्वरूप भटनागर

आज ही के दिन 1894 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब के बहेरा में हुआ। 1921 में इंग्लैंड से विज्ञान में डॉक्टरेट की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर बने। 1941 में नाइटहुड की उपाधि और 1943 में रॉयल सोसायटी के सदस्य चुने गए। भारत की शोध प्रयोगशालाओं के जनक रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना के लिए याद किया जाता है। 1 जनवरी 1955 को दिल्ली में निधन हो गया।

इधर-उधर की

ज्वालामुखी से निकल रही बर्फ

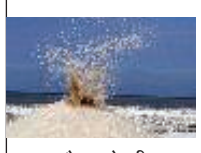

न्यूयॉर्क, एजेंसी : धरती की गर्म सतह से लावे और धुएं को बाहर निकलते आपने कहीं न कहीं देखा या पढ़ा जरूर होगा। हालांकि अमेरिका की मिशिगन झील के पास स्थित जमीन आग और लावे की जगह बर्फ उगल रही है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के विज्ञानी एर्नी ओस्तुनो ने सौगातुक के ओवल बीच पर बर्फ के ज्वालामुखी के विस्फोट की अद्भुत तस्वीरें ली हैं। शंकु के आकार का बर्फ का एक टीला है, जो कि स्थलीय झील के ऊपर पानी के विस्फोट से बनता है। मौसम विज्ञानी कॉर्ट स्फोलटेन ने कहा कि बर्फ के ज्वालामुखी उन स्थानों पर होते हैं, जहां लहरें कुछ बल के साथ तटरेखा पर जमी बर्फ से टकराती हैं।

दुनिया को कट, कॉपी, पेस्ट देने वाले टेस्लर का निधन

सैन फ्रांसिस्को, एएफपी : दुनिया को कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड देने वाले दिग्गज अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक लॉरेंस 'लैरी' टेस्लर का निधन हो गया है। वह 74 वर्ष के थे। टेस्लर ने ये कमांड 1973 में ईजाद की थीं। कंप्यूटर की दुनिया में ये कमांड रोजाना अनगिनत बार इस्तेमाल की जाती हैं। उनके निधन से अमेरिका के सिलिकॉन वैली शहर में शोक की लहर है। उन्होंने इसी शहर से अपना करियर शुरू किया था।

अमेरिकी कंपनी जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, 'कट, कॉपी और पेस्ट के खोजकर्ता और जेरॉक्स के पूर्व शोधकर्ता लैरी टेस्लर का सोमवार को निधन हो गया। हमारे रोजमर्रा के काम को आसान करने वाले शख्स को श्रद्धांजलि।' जबकि सिलिकॉन वैली के कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम ने ट्वीट में कहा, 'टेस्लर ने कट कॉपी और पेस्ट का आविष्कार कर सभी के लिए कंप्यूटर साइंस ट्रेनिंग को आसान बनाया।' टेस्लर ने जेरॉक्स पाल आल्टो रिसर्च सेंटर के अलावा अमेजन, एपल और याहू में भी काम किया था। एपल में उन्होंने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में 1980 से 1997 तक अपनी सेवाएं दी थीं।

कई कमांड ईजाद कर कंप्यूटर इस्तेमाल बनाया था आसान

लैरी टेस्लर। फाइल/ट्विटर

फाइंड और रिप्लेस कमांड भी दी थीं : कंप्यूटर इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए टेस्लर ने 1973 में उस वक्त कट, कॉपी, पेस्ट कमांड ईजाद की थीं, जब वह जेरॉक्स पाल आल्टो रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। उन्होंने फाइंड और रिप्लेस कमांड भी ईजाद की थीं।

इंटरफेस डिजाइन में हासिल की थी महारत : न्यूयॉर्क में 1945 में जन्मे टेस्लर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल को आसान बनाने वाले सिस्टम इंटरफेस डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल की। इसका मकसद यही था कि किस तरह कंप्यूटर को लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके।

जप्सी टेक्स्ट एडिटर भी बनाया

1973 में लॉरेंस पॉलो अल्टो रिसर्च सेंटर (पीएआरसी) से जुड़े थे। यहां उन्होंने टिम मॉट के साथ मिल कर जिप्सी टेक्स्ट एडिटर तैयार किया। इसी एडिटर में उन्होंने टेक्स्ट को कॉपी और मूव करने के लिए मोडलेस मेथड तैयार किया और कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड ईजाद की। लैरी टेस्लर के 'सीवी' के मुताबिक, वे मोडलेस एडिटिंग और कट कॉपी पेस्ट के शुरुआती इन्वेंटर हैं। उन्होंने सीवी में यह भी बताया था कि उन्हें 'फादर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटफेस फॉर मैकिनताश' कहा गया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लैरी ने पीएआरसी में कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड ईजाद की। हालांकि बाद में ये कट, कॉपी और पेस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के इंटरफेस और टेक्स्ट एडिटर्स के लिए लाया गया।

पर्यावरण में परिवर्तन से मनुष्यों में होते हैं आनुवांशिक बदलाव

भारतीय विषविज्ञान संस्थान (आइआइटीआर) लखनऊ में आयोजित ईएमएसआइ के 44वें वार्षिक सम्मेलन में मौजूद वैज्ञानिक। साभार : आइएसडब्ल्यू

- वनस्पतियों के साथ-साथ कई जीवों पर पड़ता है पर्यावरण का प्रभाव
- कैंसर जैसे रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं 'म्यूटेजेन'

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारक मनुष्य के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षात्मक व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र के जीनोम को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में कई भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक एजेंट आनुवंशिक रूपांतरणों का कारण बनकर उभरते हैं। इस तरह के आनुवांशिक बदलावों के लिए जिम्मेदार इन एजेंट्स को म्यूटेजेन कहते हैं, जो कैंसर जैसे रोगों को जन्म देने के लिए जाने जाते हैं। रासायनिक तत्व, पराबैंगनी अथवा एक्स-रे विकिरण जैसे एजेंट्स म्यूटजेन के कुछेक उदाहरण हैं।

लखनऊ स्थित भारतीय विषविज्ञान संस्थान (आइआइटीआर) में आयोजित ईएमएसआइ के 44वें वार्षिक सम्मेलन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई की सचिव डॉ. बिराजालक्ष्मी दास ने कहा, 'अधिकतर मामलों में इस तरह के परिवर्तनों के पीछे निहित कारणों को निर्धारित करना एक चुनौती माना जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय बदलाव मनुष्यों के साथ-साथ वनस्पतियों और अन्य जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए, रासायनिक एजेंटों का सुरक्षित उपयोग और निपटान सुनिश्चित करना जरूरी है।'

इस मौके पर मौजूद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक और इन्वायरमेंटल म्यूटजेन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. के.बी. सैनीस ने कहा कि आनुवांशिक रूपांतरणों के लिए जिम्मेदार म्यूटेजेन्स की क्षमता का पता लगाने के लिए आनुवांशिक परीक्षण की प्रभावी हाई-थ्रूपुट तकनीक का विकास जरूरी है। इससे तत्वों का जैविक परीक्षण किया जाता है।

बदलावों से जुड़े खतरों पर हुआ मंथन

आइआइटीआर के निदेशक प्रोफेसर आलोक धवन ने बताया कि म्यूटजेन सोसाइटी के अतिरिक्त, ईरान एवं यूनाइटेड किंगडम के सोसाइटीज भी इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रही हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा में दिए गए योगदान को देखते हुए यह ईएमएसआइ के सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। इस दौरान पर्यावरणीय बदलावों के कारण मानव स्वास्थ्य से जुड़े खतरों, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी, नैनो-जीनोटॉक्सिसिटी और डीएनए क्षति एवं मरम्मत जैसे विषयों पर वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण भी किए गए। वैज्ञानिकों द्वारा इस मौके पर पोस्टर्स प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

बैटरी खत्म होने के बाद भी काम करेगी माइक्रोचिप

तकनीक ▶ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया उपकरण

अब और प्रभावी तरीके से काम करेंगे इंटरनेट के पावर सेंसर नोड्स

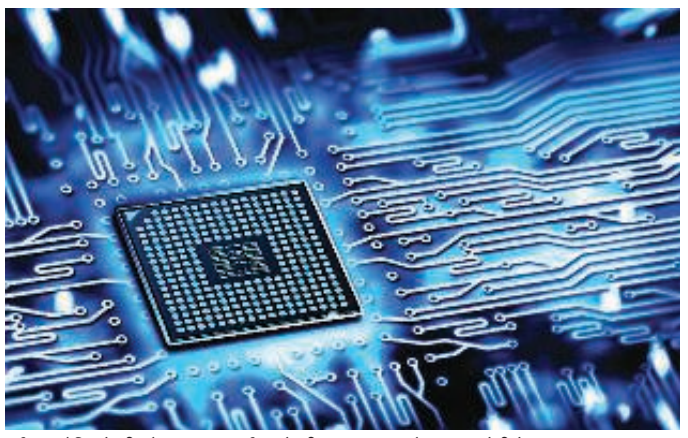

नई माइक्रोचिप बैटरी को बार-बार चार्ज करने की आवश्यकता को कम कर देती है। फाइल

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक ऐसी माइक्रोचिप विकसित की है, जो बैटरी खत्म होने के बाद भी आसानी से लंबे समय तक काम कर सकती है। इसे 'बैटलेस' नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह माइक्रोचिप लंबे समय तक चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसकी मदद से खासकर ऐसी डिवाइस तैयार की जा सकती हैं जिनमें आमतौर पर बैटरी की खपत काफी ज्यादा होती है।

'बैटलेस' के बारे में शोधकर्ताओं ने अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल सॉलिड-स्टेट सर्किट्स कांफ्रेंस (आइएसएससीसी) में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह पावर मैनेजमेंट की एक नई तकनीक है। इसे एक बहुत ही छोटे सोलर-सेल चिप के जरिये बिना की किसी बैटरी की सहायता के चलाया जा सकता है।

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) के शोधकर्ताओं के अनुसार, यह माइक्रोचिप इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसों में पावर सेंसर नोड्स के लिए आवश्यक बैटरियों के आकार को भी काफी हद तक छोटा कर सकती है। उन्होंने कहा कि नई माइक्रोचिप इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आइओटी) के सेंसर नोड्स के उत्पादन को 10 गुना सस्ता बना सकती है।

हमेशा देखरेख की नहीं होती जरूरत : एनयूएस के प्रमुख वैज्ञानिक मासिमो अलीटो ने कहा, 'अध्ययन के दौरान हमने पाया कि आइओटी डिवाइसों के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी को काफी हद तक सिकोड़ा यानी छोटा किया जा सकता है और उन्हें लगातार काम के लायक बनाए रखने के लिए हमेशा देखरेख की भी आवश्यकता नहीं होती है।' उन्होंने कहा कि बैटरियों की मरम्मत जैसी मूलभूत समस्या से निपटने के लिए आइओटी सेंसर नोड्स को बिना बैटरी के चलाना इस दिशा में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और इसके जरिये दुनियाभर में प्रयोग में लाए जाने वाले लाखों आइओटी डिवाइसों के किफायती निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

खुद-ब-खुद बदल जाता है इसका पावर मोड : शोधकर्ताओं ने कहा कि जब तक बैटरी में ऊर्जा उपलब्ध रहती है जब तक यह चिप न्यूनतम-ऊर्जा मोड में चलती है ताकि इस लाइफ बढ़ाई जा सके...और जब बैटरी खत्म हो जाती है, तो चिप न्यूनतम-पावर मोड में बदल जाती है और लगभग आधे नैनो-वाट से भी कम बिजली की खपत करती है, जो एक फोन कॉल के दौरान स्मार्टफोन की बिजली की खपत से भी एक अरब गुना कम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग आधा वर्ग मिलीमीटर के क्षेत्र में यह पावर एक बहुत छोटी-सी सौर सेल चिप के जरिये भी प्रदान की जा सकती है।

जल्द बंद नहीं होती डिवाइस : शोधकर्ताओं ने कहा कि जब बैटरी खत्म हो जाती है और माइक्रोचिप न्यूनतम-पावर मोड पर चली जाती है तब भी यह चिप आइओटी की एप्लीकेशंस को निरंतर चलाए रखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बैटरी के खत्म हो जाने के बाद भी यह चिप इंटरनेट से संबंधित डिवाइसों को जल्द बंद नहीं होने देती है।

शुरुआती दौर में है चिप का निर्माण : वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी यह माइक्रोचिप निर्माण के शुरुआती दौर में है। लेकिन भविष्य में जब यह पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और कई उपकरणों को यह माइक्रोचिप ही बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेगी और बैटरियों को बार-बार चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

माइक्रोकंट्रोलर की तुलना में है कई बेहतर

प्रतीकात्मक

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रमुख वैज्ञानिक मासिमो अलीटो ने कहा, 'बैटलेस' चिप्स के नए वर्ग का पहला उदाहरण है जो बैटरी चार्ज उपलब्धता के प्रति उदासीन है यानी इसके लिए बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, न्यूनतम बिजली मोड में यह चिप 1,000 से 1,00,000 गुना कम बिजली का उपयोग करती है, जो कि न्यूनतम ऊर्जा संचालन के लिए डिजाइन किए गए सबसे अच्छे मौजूदा माइक्रोकंट्रोलर की तुलना में कई बेहतर है और हो सकता है कि भविष्य में यह माइक्रोकंट्रोलर की भी आवश्यकता का कम कर दे।

भूल सुधार

20 फरवरी, गुरुवार को देश-विदेश जागरण के मत्थे पर भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति का साल 1935 गलत प्रकाशित हो गया है। वे मार्च 1947 में देश के वायसराय बने थे। 1931 से 1936 तक लॉर्ड विलिंगटन इस पद पर तैनात रहे। पाठकों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

फोटो न्यूज

जापान में बर्फ से बनाया पोलैंड का महल

जापान के होक्काइडो में ओडोरी पार्क में आयोजित सपोरो स्नो फेस्टिवल के लिए बर्फ से तैयार किया गया पोलैंड का महल। बर्फ से तैयार यह महल कलाकृति का उत्कृष्ट नमूना है। फेस्टिवल में आए आर्टिस्टों ने बर्फ से अद्भुत कलाकृतियां बनाई हैं। सपोरो ने ही 1972 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी की थी। एपी

स्क्रीन शॉट

मैं औसत दर्जे का कलाकार हूं : महेश मांजरेकर

सात सवाल

मराठी और हिंदी फिल्मों में सक्रिय महेश मांजरेकर अभिनय और निर्देशन दोनों ही कर रहे हैं। जहां उनकी मराठी फिल्म 'पांघरुण' रिलीज के लिए तैयार है, वहीं वह डिजिटल पर 'सिलेक्शन डे' के बाद एमएक्स प्लेयर पर 'पवन ऐंड पूजा' वेबसीरीज में दीप्ति नवल के साथ नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत:

● आप एक मैच्योर प्रेम कहानी में नजर आ रहे हैं। अब किरदारों के साथ प्रयोग कर रहे हैं?

- मैं ऐसी ही फिल्में बनाता आया हूं। 'वास्तव' को छोड़ दिया जाए, तो 'अस्तित्व' व मराठी फिल्म 'काकस्पर्श' ऐसी ही फिल्में थीं, जो सामाजिक तौर पर प्रांसगिक रही हैं। मेरी अगली फिल्म 'पांघरुण' एक प्रेम कहानी ही है। 'वांटेड' फिल्म के बाद मुझ पर नेगेटिव किरदारों का टैग लग गया था, जबकि मराठी में मैंने कई तरह के किरदार किए हैं। पहले यह हीरो वाली इंडस्ट्री थी। हीरो युवा ही होता था। अब बदलाव आ गया है। ऐसे किरदार भी करता हूं, जो मैं वास्तविक जीवन में नहीं हूं। अभिनेता होने के नाते हमेशा अलग जॉनर्स में काम करते रहना चाहिए।

आपके लिए प्यार क्या है? बढ़ती उम्र के साथ इसके मायने बदले हैं?

- जब आप किसी इंसान के साथ सहज महसूस करें, वह प्यार है। एक-दूसरे से लगाव किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर कोई अपनी पत्नी को खो देता है, तो कहीं न कहीं उसे अपनी खुशी और गम साझा करने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। जब उसे वैसा साथी मिल जाता है, तो वह प्यार है। यह व्यक्तिगत अनुभव होता है।

आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों को किरदार में डालते हैं?

- हां, लेकिन मैं यह जानबूझ कर नहीं करता, वह स्वतः आ जाता है। मैं मेथड अभिनेता नहीं हूं। कई लोग हैं, जो किरदार में इतने रम जाते हैं कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी उसी किरदार को अपने अंदर रखते हैं। मैं वह नहीं कर सकता हूं। मैं न स्क्रिप्ट पहले से लेता हूं, न लाइनें पढ़ता हूं। मैं सेट पर ही लाइनें सुनकर किरदार को निभा देता हूं। अभिनय के लिए कोई नियम नहीं बने हैं।

क्या हिंदी के मुकाबले आप मराठी फिल्मों में अपनी पसंद का कंटेंट बना लेते हैं?

- हां, मैं मराठी फिल्मों में ज्यादा प्रयोग कर पाता हूं। हिंदी में अब लोग थोड़े बोल्ड हुए हैं। अलग विषयों पर फिल्म बनाने लगे हैं। हिंदी फिल्मों का बजट ज्यादा होता है, वे प्रयोग करने से डरते हैं।

अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्मों के लिए कंटेंट कैसे चुनते हैं?

- मैं पढ़ता बहुत हूं। कोई खबर भी मुझे उत्साहित कर सकती है। 'वास्तव' में मुंबई में बंद हुई मिल के मजदूरों का गुस्सा और तकलीफ को दिखाया था। मिल में काम करने वालों को हटाकर वहां मॉल खड़े किए गए थे। दूसरी फिल्म 'सिटी ऑफ गोल्ड' का यह शीर्षक मैंने इसलिए रखा था, क्योंकि मुंबई में जमीनों के दाम बढ़ गए थे। वह ट्रायोलॉजी थी, जिसका तीसरा पार्ट मैं बनाऊंगा।

अभिनय से ज्यादा निर्देशन दिल के करीब है?

-बिल्कुल। अभिनय मैं पैसे कमाने के लिए करता हूं। खुद को औसत दर्जे का अभिनेता मानता हूं। मैं अपनी होशियारी से अपनी खामियों को छुपाकर खुद को बेहतर अभिनेता बना लेता हूं। मैं अपनी ताकत और कमजोरियां दोनों जानता हूं।

आपकी बेटी सई ने 'दबंग 3' से डेब्यू किया था। आपने नहीं सोचा उन्हें लॉन्च करने के लिए?

- मैंने उन्हें आजादी दी है। वह जो चाहे कर सकती हैं। 'दबंग 3' जैसी फिल्मों का निर्देशन मैं नहीं कर सकता हूं। मुझे उस तरह का सिनेमा समझ में नहीं आता है। विवेकपूर्ण सिनेमा बनाना आसान है। निरर्थक सिनेमा बनाना मुश्किल है। सलमान ने कभी कहा भी नहीं निर्देशन करने के लिए। वह जानते हैं कि मैं उनकी तरह के सिनेमा में यकीन नहीं करता हूं। उनकी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जीवन में अंत हमेशा अच्छा होता है।

प्रियंका सिंह

अपनी फिल्म के लिए पाकिस्तानी कलाकार नहीं चाहते थे रहमान

आखिरकार तीन सालों के इंतजार के बाद गुरुवार को मुंबई में एआर रहमान की फिल्म '99 सॉन्स' का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस मौके पर एआर रहमान के साथ उनका परिवार, फिल्म के अभिनेता एहान भट्ट, निर्देशक विश्वेश कृष्णमूर्ति और इंडस्ट्री से बोनी कपूर, मुकेश छाबड़ा समेत कई लोग पहुंचे। एआर रहमान इस फिल्म से निर्माण और लेखन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। फिल्म का संगीत भी उन्हीं का है, जिसमें लगभग 15 गाने हैं। निर्माण के क्षेत्र में उतरने को लेकर उन्होंने कहा कि वह कई फिल्म निर्माताओं के साथ काम कर चुके हैं। उन्हें लगा कि अब उन्हें भी कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए। रहमान ने बताया कि उन्हें फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि वे फिल्म में नए कलाकारों और नए निर्देशक को ले रहे हैं, जबकि उनकी फिल्म का बजट अक्षय कुमार की फिल्मों जैसा है, ऐसे में उन्हें रिटर्न नहीं भी मिलेगा। लेकिन रहमान कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। फिल्म के लिए एआर रहमान को एक ऐसा कलाकार चाहिए था, जिसे संगीत की समझ हो। फिल्म निर्देशक ने जिन तीन नए चेहरों को चुना था, वे पाकिस्तान से थे। रहमान ने उनसे पूछा कि वह भारत से कोई नया चेहरा क्यों नहीं ढूंढ़ रहे हैं, जो गाना गा सके। रहमान ने उनसे कहा कि यह उनकी पहली फिल्म है, इसलिए दिक्कतें पैदा न करें। रहमान ने दोबारा ऑडिशन्स देखे और एहान को फाइनल किया। फिल्म के लिए एहान भट्ट ने एक साल तक पियानो सीखा है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एहान भट्ट की यह पहली फिल्म है।

मोटापे से बचना है तो करें भरपूर नाश्ता

शोध अनुसंधान

मोटापे की रोकथाम में सुबह के नाश्ते का नया फायदा सामने आया है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि रात में ज्यादा भोजन करने की जगह सुबह भरपूर नाश्ता करने से मोटापे और उच्च ब्लड शुगर से बचाव हो सकता है। इस तरीके से ना सिर्फ वजन घट सकता है बल्कि डायबिटीज जैसी मेटाबोलिक बीमारियों की रोकथाम भी हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह निष्कर्ष 16 पुरुषों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। उन्हें तीन दिनों तक सुबह नाश्ते में निम्न कैलोरी वाला और रात में उच्च कैलोरी वाला आहार दिया गया था। फिर तीन दिनों तक इसके उलट आहार दिया गया। जर्मनी की ल्युबेक यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता जूलियन रिक्टर ने कहा, 'यदि आपको वजन घटाना है और मेटाबोलिक रोगों से स्वयं को बचाए रखना है तो हमारी सलाह है कि मोटापे से ग्रसित लोगों को सुबह भरपूर नाश्ता करना चाहिएं। -प्रेट्र

शिशुओं को एक्जिमा से नहीं बचाता मॉस्चराइजर

शोधकर्ताओं का कहना है कि शिशुओं को रोजाना मॉस्चराइजर लगाने से एक्जिमा से बचाव नहीं हो सकता। एक्जिमा त्वचा संबंधी आम समस्या है और इससे हर पांचवां बच्चा प्रभावित होता है। ब्रिटेन की नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हावेल विलियम्स ने कहा, 'गंभीर एक्जिमा के उपचार की दिशा में हालिया वर्षों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन प्रारंभ में ही इस समस्या की रोकथाम का कोई प्रभावी तरीका नहीं है।' यह निष्कर्ष 1394 नवजात शिशुओं पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इन शिशुओं को दो समूहों में रखा गया था। पहले समूह के शिशुओं को एक वर्ष तक मॉस्चराइजर लगाने और दूसरे को नहीं लगाने की सलाह दी गई थी। अध्ययन में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि रोजाना मॉस्चराइजर लगाने से एक्जिमा की रोकथाम हो सकती है। -आइएएनएस

पत्रलेखा को विज्ञापनों में देख फिदा हुए थे राजकुमार राव

पिछले दस वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे राजकुमार राव और पत्रलेखा अपने रिश्ते पर बात करने से परहेज नहीं करते हैं। गुरुवार को पत्रलेखा ने अपना 30वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर राजकुमार ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने दिल की बात लिखी। पत्रलेखा के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए राजकुमार ने लिखा, 'प्रिय पत्रलेखा, मुझे आज भी याद है, जब भी मैं तुम्हें विज्ञापनों में देखता, तो सोचता था कि काश, किसी दिन मैं इस लड़की से मिल पाऊं। किस्मत से मैं कुछ महीनों बाद ही तुमसे मिला। कई वर्षों से एक साथ होने के बावजूद लगता है कि जैसे हम अभी मिले हैं। मैं जितनी लड़कियों से मिला हूं, तुम उनमें सबसे खूबसूरत और सशक्त हो। आओ, एक साथ मिलकर हम शानदार स्मृतियों का सृजन करें।' पत्रलेखा का जन्म 20 फरवरी 1990 को मेघालय के शिलांग में हुआ था।

तापसी ने दिखाई पिता-पुत्री के रिश्ते की सुंदर झलक...

पिता-पुत्री का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। हिंदी सिनेमा में इस रिश्ते को 'दंगल', 'पीकू' जैसी फिल्मों में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। तापसी पन्नू अभिनीत आगामी फिल्म 'थप्पड़' में भी एक पिता-पुत्री के रिश्ते की कहानी है। इस फिल्म में कुमुद मिश्रा तापसी के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। गुरुवार को तापसी ने सोशल मीडिया पर कुमुद के साथ फिल्म की एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में कुमुद कुछ पढ़ रहे हैं और तापसी उनके पीछे खड़ी हैं। इस तस्वीर के साथ तापसी ने लिखा, 'पापा की प्यारी बेटी होने से अमृता के लिए चीजें आसान और मुश्किल हो जाती हैं। वह सोचती थी कि उसका जीवनसाथी उसके पिता की तरह होगा, इससे उसकी उम्मीदों की उड़ान काफी ऊंची थी, लेकिन उम्मीदें टूटने पर उसे संभालने के लिए वह उसके साथ थे।' महिलाओं के मुद्दों को दर्शाती फिल्म 'थप्पड़' 28 फरवरी को रिलीज होगी। अनुभव सिन्हा निर्देशित इस फिल्म में पवेल गुलाटी, रत्ना पाठक और दीया मिर्जा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

असली आइएएस अफसर अब करेंगे अभिनय

फिल्म में कलाकारों को गायक बनना हो या पुलिसवाला, वे किरदार से जुड़ी बारीकियां सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन काम तब आसान हो जाता है, जब उसी क्षेत्र में काम करने वाला इंसान ही कलाकार हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है आइएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के साथ भी। वह अभिनय के क्षेत्र में उतर गए हैं। वेबसीरीज 'दिल्ली क्राइम' के दूसरे सीजन में अभिषेक अपना ही किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक देश के प्रसिद्ध युवा आइएएस अधिकारियों में से एक हैं। वर्तमान में वह दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया है। ऑड-ईवन ट्रैफिक योजना भी उनकी देखरेख में संचालित की गई थी।